यूनियन धारा
Union Dhara

जिल्द. 48, सं. 2 VOL.XXXXVIII NO. 2, मुंबई अप्रैल-जून, 2023

अमृत काल और बैंकिंग विशेषांक
SPECIAL ISSUE ON AMRIT KAAL AND BANKING

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

गृह पत्रिका • HOUSE MAGAZINE OF

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

यूनियन धारा
Union Dhara

प्रकाशन तिथि : 14.08.2023

संरक्षक Patron

ए. मणिमेखलै A Manimekhalai
एमडी एवं सीईओ MD & CEO

प्रधान संपादक Chief Editor

लाल सिंह Lal Singh
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.) CGM (HR)

संपादकीय सलाहकार Editorial Advisors

ए. के. विनोद A. K. Vinod
मुख्य महाप्रबंधक CGM

शैलेश कुमार सिंह Shailesh Kumar Singh
मुख्य महाप्रबंधक CGM

योगेंद्र सिंह Yogendra Singh
मुख्य महाप्रबंधक CGM

रामजीत सिंह Ramjeet Singh
सहा. महाप्रबंधक (रा.भा.) AGM (OL)

संपादक Editor

गायत्री रवि किरण Gayathri Ravi Kiran
मुख्य प्रबंधक (रा.भा.) Chief Manager (OL)

संपादन सहयोग Editorial Support

नितिन वासनिक Nitin Wasnik
सहा. प्रबंधक (रा.भा.)
Asst. Manager (OL)

जागृति उपाध्याय Jagriti Upadhyay
सहा. प्रबंधक (रा.भा.)
Asst. Manager (OL)

गृह पत्रिका • HOUSE MAGAZINE OF

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

अनुक्रमणिका Contents

- परिदृश्य 1
- सुस्वागतम और विदाई 2
- संपादकीय 3
- अमृत काल और बैंकिंग क्षेत्र 4-5
- अमृतकाल की संकल्पना 6-7
- अमृतकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था 8-9
- अमृत काल और फिनटेक 10-11
- अमृत काल के पंच प्रण और बैंकिंग 12-13
- कौशल विकास में बैंकों का योगदान 14-15
- बैंकिंग में ज्ञानार्जन और विकास का महत्व 16-17
- कृषि बैंकिंग का बदलता स्वरूप 18-19
- उद्यमिता विकास - आर्थिक विकास का आधार 20-21
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बैंकिंग 22-23
- अमृतकाल -विकासशील से विकसित देश का सफर 24-25
- आत्मनिर्भरता पहल 26-27
- विकास पथ पर नारी का योगदान 28-29
- हमें गर्व है 29
- विज़न 40 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था 30-31
- अमृतकाल में दिव्यांग वर्ग उत्थान : बैंकों की भूमिका 32-33
- अमृत काल में भारतीय भाषाएं 34-35
- सेंटर स्प्रेड 36-37
- काव्यधारा 38-39
- Agricultural Trends 40-41
- Inclusive Banking and Economic Development 42-44
- Contribution of Personal Banking in Economic Growth 45
- Government Schemes for Upliftment of Small Businesses 46-47
- Importance of Green Revolution in Sustainable Development 48-49
- Digital Transformation for Eco-Innovation 50-51
- शिखर की ओर 52-53
- शुभमस्तु 54
- सेवानिवृत्त जीवन से 55-57
- प्रतियोगिता/परिणाम 58
- गतिविधियां 59-70
- व्यंजन और हेल्थ टिप्स 71
- आपकी पाती 72

ई-मेल E-mail: uniondhara@unionbankofindia.bank
gayathri.ravikiran@unionbankofindia.bank
Tel.: 022-41829288 | Mob.: 9849615496

यूनियन धारा में प्रकाशित लेख आदि में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.
The views expressed in the articles published in Union Dhara are solely that of the author and do not necessarily reflect the views of the management.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित.
Published by Union Bank of India for internal circulation

परिदृश्य
PERSPECTIVE

प्रिय यूनियनाइट्स,

मैं यूनियन धारा के इस अंक के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. मैं व्यावहारिक, आकर्षक और विचारोत्तेजक सामग्री के साथ बेहतरीन अंक के संपादन के प्रति यूनियन धारा टीम के समर्पण की सराहना करती हूँ. आपके उत्साहपूर्ण कार्य से महत्वपूर्ण विषय का सृजन संभव हुआ है.

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि यह अंक "अमृत काल" के प्रति समर्पित है. यह अवधारणा विकास, परिवर्तन और सामूहिक पुनरुत्थान की हमारी यात्रा से गहराई से मेल खाती है. देश की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत काल की घोषणा की गई थी, जो 2022 से 2047 तक 25 वर्षों की अवधि में एक विकसित राष्ट्र की ओर भारत की परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाता है. "अमृत काल" आत्मनिर्भर, अभिनव, डिजिटल रूप से परिवर्तनकारी और समृद्ध भारत के निर्माण का पथप्रदर्शक है. इस दृष्टिकोण के मूल में "पंचप्रण" की अवधारणा निहित है, जिसमें सभी नागरिकों से एक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने का आग्रह किया गया है.

सारांश के रूप में, 'अमृत काल' के विज़न में पुनरुत्थान और नवीकरण की भावना समाहित है. यह बाधाओं को दूर करने, परिवर्तन को अपनाने और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने हेतु हम सभी में नई ऊर्जा का संचार करता है.

देश के एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में, हमारे बैंक पर जन-मानस के सपनों को साकार करने और देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने की एक बड़ी जिम्मेदारी है. हम नवोन्मेषी वित्तीय समाधान प्रदान करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और पूरे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम इस परिवर्तनकारी यात्रा में सार्थक योगदान देने के लिए अपनी विशेषज्ञता, संसाधनों और पहुंच का लाभ उठाने के लिए अथक प्रयास करेंगे. हम एकजुट होकर एक उज्ज्वल भविष्य को आकार दे रहे हैं - एक ऐसा भविष्य जिसमें अनंत संभावनाएं हैं.

इस अंक के कुशल संपादन हेतु मैं यूनियन धारा टीम को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ. "अमृत काल" की संकल्पना को उत्कृष्टता के साथ निरूपित करने के प्रति आपका समर्पण वास्तव में सराहनीय है.

शुभकामनाओं सहित,

(ए. मणिमेखलै)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Dear Unionites,

I extend warm greetings to all through this issue of Union Dhara. I congratulate the Editorial Team of Union Dhara for the dedication to crafting insightful, engaging, and thought-provoking content in a truly commendable fashion. It is your enthusiasm that fuels motivation to create content that matters.

I am happy to note that this issue is a dedication to the "Amrit Kaal", a concept that resonates deeply with our journey of growth, transformation, and collective resurgence. The declaration of "Amrit Kaal" was made by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, on the occasion of the country's 75th year of Independence marking India's transformative journey towards a developed nation in the 25 years period from 2022 to 2047. "Amrit Kaal" is a roadmap to building a self-reliant, innovative, digitally transformative and prosperous India. At the core of this vision lies the concept of "Panch Pran" (Five Pledges), wherein, all citizens are urged to carry out their duties & responsibilities, to fulfil the vision of a developed nation.

In essence, the "Amrit Kaal" vision encapsulates the spirit of rejuvenation and renewal. It challenges all of us to overcome obstacles, embrace change and work collectively towards a brighter future.

As a premier financial institution in the country, our Bank has a great responsibility in realizing the dreams of the people and be a part of the growth story of the nation. We are committed to provide innovative financial solutions, fostering financial inclusion and driving economic development across the country. We will work tirelessly to leverage our expertise, resources and reach to contribute meaningfully to this transformative journey. Together, we are shaping a brighter future - a future that holds endless possibilities.

I extend my heartfelt gratitude to the Union Dhara team that has meticulously curated this issue. Your dedication to capture the spirit of the "Amrit Kaal" is truly commendable.

With best regards,

(A. Manimekhalai)
Managing Director & CEO

सुस्वागतम

श्री प्रकाश बलियारसिंह को दिनांक 14 जुलाई 2023 से बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

श्री प्रकाश बलियारसिंह, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक थे. आप एक कैरियर सेंट्रल बैंकर रहे हैं और आपके पास भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों (मुख्य रूप से पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग) के साथ 3 से भी अधिक दशकों का समृद्ध अनुभव है.

आपने अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रधान निरीक्षण अधिकारी/ वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के रूप में कार्य किया है. आप बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (ए.क्यू.आर), जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के साथ-साथ जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एस.पी.ए.आर.सी) से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विभिन्न समितियों/उप समितियों के सदस्य भी रहे हैं. आपने अंतरराष्ट्रीय समितियों में सदस्य के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व भी किया है.

आप राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और ऑक्सफर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, यूके से एम.एससी.(वित्त) किया है. आप भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता रहे हैं. आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट हैं.

विदाई

श्री अरुण कुमार सिंह, दिनांक 26.04.2019 से 14.07.2023 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक रहे. वर्तमान में आप सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय मुंबई के प्रमुख है, और बैंक में तकनीकी विकास, विशेष रूप से मुद्रा प्रबंधन, सरकारी बैंकिंग भुगतान प्रणाली, साइबर सुरक्षा, डाटा सेंटर उन्नयन, आंतरिक अनुप्रयोग, आईटी अवसंरचना आदि क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं.

आपको भारतीय रिजर्व बैंक में सरकारी बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, गैर - बैंकिंग एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण, बैंकिंग विनियमन, मौद्रिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने का समृद्ध अनुभव है. आप गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य से लंबी अवधि तक जुड़े रहे हैं. आपने विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों हेतु प्रधान निरीक्षक अधिकारी / वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के रूप में कार्य किया है तथा आप प्रक्रिया एवं विकास से संबंधित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के साथ - साथ बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से जुड़े रहे हैं. आप बैंकों की नियामक नीति तैयार करने में विभिन्न क्षमताओं से शामिल रहे हैं. आपने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नामित निदेशक के रूप में भी सेवाएँ प्रदान की हैं तथा आपने मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया के तहत नियामक एवं विकास मामलों में सहायता प्रदान की है. आप अपने मौजूदा कार्यभार से पूर्व तीन वर्षों 2019-22 के लिए राजस्थान में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत थे तथा राजस्थान राज्य में मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग / गैर-बैंकिंग विकास, सरकारी बैंकिंग आदि के क्षेत्र में केंद्रीय बैंकिंग का निर्वहन किया है.

श्री अरुण कुमार सिंह ने अर्थशास्त्र में स्नातक तथा वित्त एवं मानव संसाधन में एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है. आप भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट हैं.

संपादकीय
EDITORIAL

प्रिय पाठकगण,

टीम यूनियन धारा की हमेशा से कोशिश रही है कि अपने पाठकों के समक्ष समीचीन विषयों को प्रस्तुत करे. इसी परंपरा को जारी रखते हुए हम आपके समक्ष यह "अमृत काल और बैंकिंग" विशेषांक लेकर प्रस्तुत हुए हैं.

अमृत काल की संकल्पना वर्ष 2047 यानी आजादी के 100वें वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में महत्वाकांक्षी पहलों का समागम है. देश की प्रगति में बैंकों की भूमिका, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान, निर्विवादित है. अत: यह आवश्यक है कि हम बैंकर होने के नाते अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु अमृत काल की मुहिम में अपनी भूमिका पहचानें और यथापेक्षित योगदान दें.

अमृत काल की बृहत संकल्पना में एक तरफ भारत के समृद्ध विरासत के संरक्षण और पुनरुत्थान करते हुए अपनी जड़ों को मजबूत करना शामिल है तो दूसरी ओर प्रत्येक क्षेत्र में नित नूतन प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाते हुए ज्ञानार्जन और कौशल विकास के दम पर विकास और प्रगति के कीर्तिमान स्थापित करने के प्रयास. इस विशेषांक में इन सभी पहलुओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है.

इस अंक को साकार रूप देने हेतु अपना योगदान देने वाले यूनियन धारा के लेखकों को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं. संपादकीय सलाहकारों के अमूल्य मार्गदर्शन से इस अंक में निखार आया है. विशेष रूप से हम आदरणीय कार्यपालक निदेशक श्री नितेश रंजन जी के प्रति आभारी हैं जिन्होंने इस विशेषांक हेतु मुख्य लेख लिखकर हमारे हौसलों को बुलंद किया है.

आशा है कि 'यूनियन धारा' का यह अंक आपको रुचिकर लगेगा. हम इस अंक के बारे में आपकी राय तथा मूल्यवर्धन हेतु आपके सुझाव का लाभ पाने की इच्छा रखते हैं, अत: हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें.

आपकी,

(गायत्री रवि किरण)

Dear Readers,

Team Union Dhara has always endeavoured to present current topics to its readers. Continuing this tradition, we present this special issue of "Amrit kaal and Banking".

The concept of "Amrit Kaal" is a set of ambitious initiatives towards establishing India in the category of developed nations by the year 2047 i.e. the 100th year of independence. The role of banks, especially public sector banks, in the progress of the country is undisputed. Therefore, it is necessary that we, as bankers, recognize our role in the campaign of "Amrit Kaal" for the revival of the economy and contribute our mite.

The comprehensive concept of "Amrit Kaal" encapsulates, on the one hand, strengthening India's roots by preserving and reviving its rich heritage, and on the other hand, attaining new heights of development and progress on the basis of Learning and skill development by adopting new technology and innovation in every field. This special issue is an attempt to present all these aspects of "Amrit Kaal".

We express our heartfelt gratitude to the writers of Union Dhara for their contribution in bringing forth this issue. It has acquired finesse with the invaluable guidance of the editorial advisors. We are especially grateful to our respected Executive Director Shri Nitesh Ranjan ji who has boosted our morale by honouring us with the lead article for this special issue.

Hope this issue of 'Union Dhara' makes for an interesting read. We wish to benefit from your opinion regarding this issue and suggestions for further improvement, so kindly do send us your response.

Yours sincerely,

(Gayathri Ravi Kiran)

अमृत काल और बैंकिंग क्षेत्र

नितेश रंजन
कार्यपालक निदेशक

अमृत कालः 'न्यू इंडिया' के लिए विज़न 2047 : माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित 'अमृत काल' या 'अमृत युग' की अवधारणा का उद्देश्य भारत को समृद्ध और समावेशी बनाना है, जिसमें विकास का सुपरिणाम सभी क्षेत्रों और नागरिकों तक पहुंचे. 'न्यू इंडिया' के लिए विज़न 2047 में एक प्रौद्योगिकी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था, मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं. यह अगले 25 वर्षों के लिए भारत के आर्थिक विकास और समृद्धि का रोडमैप है.

अमृत काल के दौरान, भारत @100 हेतु सरकार, पीएम गति शक्ति के अनुसरण में आधुनिक अवसंरचना के लिए बड़े पैमाने में सार्वजनिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगी. हाल के वर्षों में केंद्रीय बजट का जोर उच्च पूंजीगत व्यय के माध्यम से अवसंरचना के विकास पर केंद्रित रहा है, जो अब 10 लाख करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 37% अधिक) है, जिसमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने और जनता की समृद्धि में सुधार की नींव डाली गई है. सुदृढ़ अवसंरचना किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, इस क्षेत्र पर किए जा रहे व्यय को बढ़ाने से शिक्षा और कौशल विकास, शहरी विकास, हरित अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को गति प्राप्त होगी .

अमृत काल में बैंकों की भूमिका : किसी देश के वित्तीय और आर्थिक विकास पर बैंकिंग का सीधा असर पड़ता है. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और कुशलता से आर्थिक विकास में तेजी आती है. भारत के अमृत काल की राह में, वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. इसलिए, आने वाले दशकों में, भारत में बैंकों को वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी अवसंरचना को पुनर्व्यवस्थित करना होगा और व्यावसायिक रणनीतियों को फिर से तैयार करना होगा.

अनुकूल जनसांख्यिकीः संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है. हमारी आबादी युवा प्रधान है, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है. इसके अलावा, भारत की जनसंख्या अगले चार दशकों तक बढ़ती रहने की उम्मीद है, जो 2063 में अत्यधिक 1.7 अरब हो जाएगी. अब से 2050 तक की अवधि के दौरान वैश्विक कार्यबल की वृद्धि में भारत का योगदान 1/6 से अधिक होगा. यह आने वाले वर्षों में बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को अपार अवसर प्रदान करता है.

डिजिटल अवसंरचना को उन्नत करनाः तत्काल भुगतान लेनदेन में 50% के करीब हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा प्रतिभागी बनकर उभरा है. चैटबॉट्स, मोबाइल ऐप और वैयक्तिकृत डिजिटल समाधान जैसी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर, बैंक ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान कर रहे हैं. फिनटेक के साथ सहयोग से बैंक अपनी डिजिटल क्षमताओं में वृद्धि और तकनीक-प्रेमी ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बने हैं. भारत द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को अन्य राष्ट्रीय त्वरित भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ने के साथ सीमा-पार भुगतान क्षेत्र में डिजिटलीकरण से क्रांति आ रही है.

भारत में कुल डिजिटल भुगतान 2026 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें तीन में से दो लेनदेन गैर-नकद माध्यम से होंगे. अगले 25 वर्षों में मेटावर्स, अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, डिजिटल करेंसी और यूपीआई जैसी अभूतपूर्व तकनीक भारतीय बैंकिंग उद्योग का चेहरा बदल देंगी. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार, क्रय शक्ति समानता के मामले में भारत 2048 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी. बैंकिंग क्षेत्र को अपने भौतिक और डिजिटल अवसंरचना दोनों को वैश्विक स्तर पर अपग्रेड करते हुए इस परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए.

साइबर सुरक्षाः डिजिटल बैंकिंग में प्रगति के साथ, साइबर सुरक्षा बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी रहेगी. बैंकों द्वारा आईटी प्रणालियों के बढ़ते उपयोग, ग्राहकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को अपनाने में तेजी, साथ ही विभिन्न सेवाओं के लिए तीसरे पक्षों पर बढ़ती निर्भरता के कारण व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संवर्धित आघात-सहनीयता क्षमताओं की आवश्यकता होगी. इसमें साइबर हमलों और कंप्यूटिंग अवसंरचना को बाधित करने या अक्षम करने या गोपनीय जानकारी और डेटा चुराने हेतु दुर्भावनापूर्ण

प्रयासों के खिलाफ सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करना शामिल होगा. आने वाले दिनों में बैंकों को अपने कार्मिकों का सतत कौशल विकास करना होगा. निरंतर ज्ञान अर्जित करना और आगे बने रहना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा.

वित्तीय समावेशन: डिजिटलीकरण से भारत को वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में अधिक पैठ हासिल करने में भी मदद मिलेगी. शहरी और ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग में भारी अंतर एक चुनौती बनी हुई है. चूंकि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य केवल बचत और ऋण तक पहुंच प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, यह बैंकों को अपने ग्राहकों की वास्तविक क्षमता को उभारने और एक संपन्न अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए उन्हें सशक्त बनाने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है.

डिजिटल ऋण: वित्तीय सेवाओं तक पहुंच केवल बुनियादी बैंक खाते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऋण के औपचारिक चैनलों तक भी है. ग्राहकों को समग्र रूप से किसी भी समय किसी को भी डिजिटल भुगतान करने के लिए अपने बैंकिंग खाते का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए. डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाकर वित्तीय संस्थान, ग्राहक व्यवहार, बाजार के रुझान और उभरते जोखिमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जिससे वे अधिक सूचित क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं. जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, अधिक नवीन मॉडल उभरने की संभावना है जो ऋण देने के परिदृश्य को बदलने के लिए डेटा, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाएंगे.

अनुकूलित उत्पाद: बैंकों को ऐसे अनुकूलित उत्पाद और सेवाएँ भी विकसित करनी होंगी जो उनकी आय के स्तर के आधार पर समाज के विभिन्न स्तरों के लिए सबसे उपयुक्त हों. इसमें नवोन्मेषी समाधान शामिल होंगे जो लोगों के लिए न केवल बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाएंगे बल्कि विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग भी आसान बनाएंगे.

एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण की मांग और आपूर्ति के बीच लगातार अंतर भारत के ऋण बाजार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. एमएसएमई क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और निर्यात में 48% योगदान देता है. इसे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अवसर के क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए.

मानव संसाधन में निवेश: जैसे-जैसे बैंकिंग प्रक्रियाएं डिजिटलीकरण में वृद्धि की ओर बढ़ रही हैं, बैंकों को अपने कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाना होगा और उन्हें संस्थागत वातावरण प्रदान करना होगा जिसमें वे बदलती प्रौद्योगिकियों और मांग पैटर्न के अनुरूप काम करने में सक्षम बन सकें. साथ ही, हमें कार्यबल में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी.

जलवायु जोखिम: निकट भविष्य में बैंकों को जलवायु जोखिम पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा. नियामकों ने पहले ही इस चिंता को चिह्नित कर लिया है और वित्तीय संस्थानों द्वारा जलवायु जोखिम के प्रबंधन के लिए आवश्यक सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है. बैंकों को संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए उचित व्यावसायिक रणनीतियां विकसित करनी होंगी और अभिशासन ढांचे को मजबूत करना होगा. इसके अलावा, बैंक टिकाऊ और हरित परियोजनाओं के लिए वित्त को चैनलाइज़ करने के साथ-साथ हरित पहल को प्रोत्साहित करने वाले नए वित्तीय उत्पादों को विकसित करके कम कार्बन अर्थव्यवस्था में रूपांतरण के वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

विनिर्माण को सहयोग: इसी कड़ी में आगे, भारत तेज़ी से वैश्विक विनिर्माण मूल्य शृंखला का हिस्सा बनने का प्रयास करेगा. भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए, जो तेज़ी से अपनी वैश्विक उपस्थिति दर्ज करा रही है, वैश्विक मूल्य शृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आवश्यक है. सरकार भी इस पहलू पर उचित ध्यान दे रही है और हाल के वर्षों में इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत अभियान, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं जैसी कई पहल की गई हैं. अवसंरचना का विकास, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप और पर्यटन क्षेत्र विकास को त्वरित गति प्रदान करेंगे. ये क्षेत्र नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करेंगे और बैंक इन क्षेत्रों में सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनेंगे.

यूबीआई द्वारा हाल की पहल : हमारा बैंक पिछले कई वर्षों से भविष्य के लिए तैयार रहने हेतु कई कदम उठा रहा है, चाहे वह डिजिटल क्षेत्र हो या पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना हो. हाल ही में हमने टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी में एक पहल के रूप में, मेटावर्स वर्चुअल लाउंज और ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म लॉ न्च किया था. यह ग्राहकों को बैंक की जमा राशि, ऋण, सरकारी कल्याण योजनाओं, डिजिटल पहल आदि के बारे में वास्तविक दुनिया के समान अनूठे बैंकिंग अनुभव के साथ जानकारी प्रदान करेंगे.

बैंक ने एक अत्याधुनिक डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आईबीएम इंडिया के साथ भी साझेदारी की है. इस ऐतिहासिक सहयोग का उद्देश्य अत्याधुनिक क्षमताओं से सुसज्जित डिजिटल बैंक स्थापित करना है, जो ओम्नी चैनल अनुभव, डेटा-संचालित हाइपर-वैयक्तिकरण और निर्बाध क्रॉस-सेलिंग तथा अपसेलिंग के लिए डिज़ाइन किए गए एक व्यापक वित्तीय सेवा सुपरस्टोर, पर ध्यान केंद्रित करता है. बैंक निवेश निर्णय लेते समय पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) को भी एक महत्वपूर्ण पहलू मानता है.

निष्कर्ष के तौर पर, जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, बैंकों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों के पुनर्निर्धारण, ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादों को डिजाइन करने और अपनी सेवाओं की कुशलता में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर बदले हुए आर्थिक माहौल में प्रासंगिक बने रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. यदि भारत को अगले 25 वर्षों तक तेज गति से विकास करना है, तो बैंकों को उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होगी और अवसंरचना सहित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के विकास में योगदान देना होगा.

अमृत काल की संकल्पना

अमृत काल शब्द पहली बार 15 अगस्त 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन में प्रयोग किया गया था. वर्तमान परिप्रेक्ष में अमृत काल का अर्थ सुख, नए कार्य को आरंभ करने तथा नवीन संकल्प लेने का काल है. अमृतकाल में हर किसी के सुख, समृद्धि, खुशहाली और समावेशी विकास पर बल दिया जाएगा. अमृतकाल भारत के सर्वजन के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को पूरी निष्ठा और सक्षमता से पूर्ण करने और देश की समृद्धि का काल है.

अमृत काल की अवधि - भारत ने वर्ष 2022 में देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है. देश की आज़ादी के 75 वर्षों में हुए देश के सामासिक और समावेशी विकास से आज़ाद भारत की यात्रा की विभिन्न उपलब्धियों और वृत्तांत को देश के नागरिकों के सामने लाने के लिए अमृत महोत्सव मनाया गया. इसी के विस्तार के रूप में देश में अमृतकाल की अवधि 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2047 तक रखी गई. इन 25 वर्षों में भारत अपने विकास और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होकर आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सभी के लिए खुशहाली, संपन्नता, गौरव प्राप्ति के साथ भारत विश्व में एक नए उच्च पटल पर पदस्थापित होगा.

अमृत काल का उद्देश्य - अमृत काल का उद्देश्य देश के नागरिकों के जीवनयापन और देश के निचले पायदान के नागरिक को सभी के समान सुख और सुविधाएं प्रदान करना, निम्न स्तर का विकास कर सभी को समान स्तर पर लाने का प्रयास करना और सभी नागरिकों का देश के समावेशी विकास में जनभागीदारी है. अमृतकाल के कुछ मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :

नागरिकों के जीवन को बेहतर करना

आज देश में गरीब और अमीर के मध्य जीवन के विभिन्न आयामों में अत्यधिक अंतर है. ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 5 प्रतिशत नागरिकों का देश के 60 प्रतिशत संसाधनों पर अधिकार है जबकि भारत के निम्नस्तर के 50 प्रतिशत लोग देश के 3 प्रतिशत संसाधनों के आधार पर अपना जीवनयापन करते हैं. इसी तरह शिक्षा के अवसरों में भी बड़ा अंतर है. गरीबी उन्मूलन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद गरीब शिक्षा के अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते. अमृतकाल ऐसी सभी असमानताओं को कम कर देश के नागरिकों के लिए कौशल विकास, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, नई शिक्षा नीति, महिला सशक्तिकरण, आदि प्रयासों से देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर किया जा सकता है.

ग्रामीण / शहरी विकास के अंतर को कम करना - अमृत काल की अवधि के दौरान ग्रामीण परिवेश में विकास की आधारभूत संरचनाओं, परियोजनाओं को बढ़ावा देना है और गाँव को शहर की भांति सभी सुख-सुविधाओं से सुसज्जित करने का संकल्प है. रोजगार के अवसरों को ग्रामीण परिवेश में विकसित करना ताकि युवा, शिक्षा के बाद, रोजगार के लिए शहरों का रुख न करें और उन्हें अपने ही परिवेश में रोजगार / स्वरोजगार के अवसर मिलने हेतु आधारभूत संरचना में वृद्धि हो. इसके लिए जैविक खेती, कौशल विकास, नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य है.

कारोबार में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना - देश के समावेशी विकास के लिए यह आवश्यक है कि रोजगार, इकाई स्थापन, अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नियम व शर्तों को सरल बनाया जाए एवं विभिन्न मंजूरियों और सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जाए, जिससे युवा उद्यमों के विकास के लिए सरकार की लाभकारी योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से स्वरोजगार और रोजगार के सृजन के लिए सहजता से कार्य शुरू हो सके. किसी कार्य को आरंभ करने के लिए मंजूरी और अन्य स्वीकृति लेने में लगने वाले अत्यधिक समय और परेशानी को कम किया जा सकेगा.

नवीन तकनीक व प्रौद्योगिकी सक्षम विकास - आधुनिक काल में किसी भी देश के सर्वभौमिक विकास में तकनीक की महती भूमिका है. हाल के वर्षों में देश में सभी क्षेत्रों में तकनीक के प्रयोग को बढ़ाया जा रहा है. चाहे वह डिजिटल इंडिया की संकल्पना हो या डीबीटी के माध्यम से सीधे हिताधिकारी को वित्तीय लाभ पहुंचाना हो या सड़क मार्ग पर डिजिटल शुल्क भुगतान हो और अन्य लोक सुविधाओं का प्रयोग हो, तकनीक से योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन हो रहा है और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी कम किया गया है. इंटरनेट के पटलों के प्रयोग का विस्तार हो रहा है. देश में ऊर्जा के सृजन और संसाधनों के बेहतर प्रयोग, शिक्षा और सुरक्षा में भी उच्च तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस अमृतकाल में देश के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए तकनीक व नवोन्मेष के प्रयोग में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है.

डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास - देश में अर्थ के प्रयोग को भौतिक रूप से कम कर डिजिटल रूप में बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. हाल ही में देश के बजट को अमृतकाल का बजट भी कहा गया है. मुद्रा भी डिजिटल मुद्रा के रूप में बनाई जा रही है और इसके कई नए प्रयोग देखे जा रहे हैं. यहाँ तक कि स्वर्ण को भी डिजिटल रूप में आप खरीद सकते हैं. डिजिटल अर्थव्यवस्था से धन के प्रयोग और अनर्थक धनार्जन पर लगाम लगाई जा सकती है. बैंक व वित्तीय

संस्थानों द्वारा वित्तीय उत्पादों के पंजीकरण से लेकर प्रयोग तक में डिजिटल माध्यम को बढ़ावा दिया जा रहा है. आज इंटरनेट बैंकिंग से आगे बढ़ कर मोबाईल बैंकिंग और एसएमएस व वाट्सऐप्प बैंकिंग का प्रयोग व प्रचलन बढ़ा है.

ऊर्जा संरक्षण - देश के सीमित संसाधनों के संरक्षण और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सृजन पर ज़ोर दिया जा रहा है. गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को कम कर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है. पारंपरिक तेल व खनिज पदार्थ व ऊर्जा के अन्य संसाधनों के आयात को कम कर, निर्यात में वृद्धि करने के प्रयास को इस अमृत काल में शीर्ष स्तर पर ले जाने का प्रयास है. आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अधिक से अधिक संसाधनों के सृजन में देश सक्षम हो, यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है. ऊर्जा किसी भी देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. इसके सृजन और निर्यात से देश के विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाया जा सकता है. हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, मीथेनॉल, जलप्रपात ऊर्जा आदि के माध्यम से ऊर्जा विकास को अबाध्य किया जाएगा और नियमित पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग को कम किया जाएगा.

जलवायु संरक्षण सक्षम विकास - पूर्व के दो दशकों में मानवीय कृत्यों और संरचना के अनुचित विकास से पर्यावरण पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे कई जन आपदाएं सामने आई हैं और साल दर साल इनमें बढ़ोत्तरी हो रही है. इस अमृत काल के 25 वर्ष के दौरान जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकास के पथ पर अग्रसर होने पर ज़ोर दिया जाएगा. भूसंपदा के संरक्षण, वृक्षारोपण, आदि से प्रकृति के अनुकूल विकास करना, जैव विविधता को बनाए रखना और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सभी नागरिकों की जनभागीदारी आवश्यक है.

अमृत काल की प्राथमिकताएं - 25 वर्ष की अवधि में देश को विश्व पटल पर एक समृद्ध विकसित देश बनाने के लिए इस अमृत काल में कई प्रथमिकताएं नियत की गई हैं

1. **पीएम गतिशक्ति** - देश में व्यवसाय और उद्योगों के विकास के लिए सड़क, जल और वायु मार्ग का सशक्त और उच्च स्तरीय होना आवश्यक है. आवागमन में लगने वाले समय को न्यूनतम करने के लिए नए एक्स्प्रेसवे, मेट्रो, तीव्रगति ट्रेन आदि का निर्माण युद्धस्तर पर किया जा रहा है, जिससे निर्माण और सेवा क्षेत्र का उनकी सक्षमता के अनुरूप देश की प्रगति में प्रयोग किया जा सके. इसमें सड़क, रेलवे, विमानपत्तन, बंदरगाह, जलमार्ग, जल ऐरोड्रोम, मालढुलाई, आदि साधनों को बेहतर करना व संख्या में वृद्धि पर बल दिया जाएगा. इससे देश में निर्मित सभी तरह के जनोपयोगी उत्पादों का देश व विदेश में आवागमन बिना गुणवत्ता में गिरावट के किया जा सके.
2. **समावेशी विकास** - देश में समावेशी विकास की अवधारणा पर पूर्व में काफी समय से बल दिया जा रहा है और इसके लिए कई लाभकारी योजनाएं भी वर्तमान में लाभ प्रदान कर रही हैं. देश के प्रत्येक नागरिक को आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार, कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराते हुए देश के समावेशी विकास पर बल दिया जाएगा. जनोपयोगी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए डिजिटल माध्यम का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है ताकि इन योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुँच सके.
3. **उत्पादकता वृद्धि और निवेश** - भारत में युवा वर्ग विश्व में सर्वाधिक है और इनके कौशल विकास और नवीन तकनीकी के प्रयोग से निर्माण और सेवा क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देना है. देश के सकल घरेलू उत्पाद दर को बढ़ाने और नागरिक की आय वृद्धि पर बल दिया जा रहा है, ताकि उनकी खरीद क्षमता बढ़ सके. गतिशक्ति के माध्यमों और आधारभूत संरचना के विकास से निजी निवेश को भी बढ़ाया जाए. निजी निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. तकनीकी नवोन्मेष से उत्पादकता में वृद्धि होगी. विभिन्न स्टार्टअप और नवोन्मेषी कार्य इस दिशा में कार्य कर रहे हैं.
4. **प्रगति के समान अवसर उपलब्ध कराना** - देश की प्रगति में देश के हर एक नागरिक की उसके स्तर और सक्षमता के आधार पर भागीदारी हो. उनके विकास के लिए शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएं. गरीब और अमीर के विभिन्न मदों में हुए आंकलन के अंतर को कम किया जाए. पुरुष और महिलाओं को उनके कौशल विकास और शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि देश की प्रगति में सभी कदमताल करते हुए आजादी के 100 वर्षों की पूर्णता पर एक समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें.
5. **निजी निवेश का वित्तपोषण** - देश में नई परियोजनाओं, स्वरोजगार के अवसरों, औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने हेतु नए निवेश के वित्तपोषण पर ज़ोर दिया जाएगा. बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषण के नियमों और शर्तों को सरल बनाया जाएगा. कई योजनाओं में नई इकाई में किसी कारण कार्यशील पूंजी या उत्पादक न होने पर अर्थ की हानि से नागरिक को बचाने के लिए ऋण की गारंटी सहित ऋण की उपलब्धता की जा रही है. इससे युवा सरलता और निडरता के साथ अपने नवोन्मेष और प्रयोगों से देश के सार्थक विकास में योगदान कर सकें.

अमृत काल में सभी क्षेत्रों के विकास पर उपरोक्त प्रयासों से विश्व स्तरीय बनाया जाएगा. भारत आजादी के अपने 100 वर्ष पूर्ण करने पर हमारे सपनों के भारत की संकल्पना को पूरा करेगा और यह हम सभी के संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति से ही संभव होगा.

रूपेश कुमार वर्मा
अंचल कार्यालय, दिल्ली

अमृत काल में भारतीय अर्थव्यवस्था

अमृत काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विज़न में प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है, जो मजबूत लोक वित्त और एक सशक्त वित्तीय क्षेत्र से युक्त होगी. इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक सूची निम्न तीन प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगी:

- नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यापक अवसरों को उपलब्ध कराना;
- प्रगति और रोजगार सृजन के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराना
- वृहद आर्थिक सुस्थिरता को स्थापित करना

अमृत काल का यह विजन सात प्राथमिकताओं द्वारा मार्गदर्शित है, जो सप्तऋषि की भांति एक दूसरे को सम्पूर्ण करती हैं.

1. समावेशी विकास
2. आखिरी व्यक्ति तक पहुंच
3. अवसंरचना एवं निवेश
4. क्षमता का विकास
5. हरित विकास
6. युवा शक्ति
7. वित्तीय क्षेत्र

बजट में इंडिया @100 तक पहुँचने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान:

- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
- पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)
- मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा
- हरित विकास

अमृत काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति आगामी दशकों के लिए असीम संभावनाओं एवं सुनहरे भविष्य की ओर इशारा कर रहा है. भारतीय अर्थव्यस्था से संबंधित मुख्य बातों का उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में किया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण बजट दस्तावेज होता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए रोडमैप तैयार करता है. यह सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा संचालित आर्थिक मामले विभाग के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा विकसित किया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न आर्थिक कारकों में रुझानों का विश्लेषण कर निवेश पर प्रकाश डालता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं और सुधारों पर ध्यान आकर्षित करता है. यह आने वाले वर्षों में डेटा के साथ-साथ आर्थिक पूर्वानुमान भी प्रस्तुत करता है.

भारत का मध्यमकालिक विकास परिदृश्य: भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक ढांचागत एवं गवर्नेंस सुधार लागू किए गए, जिनके कारण वर्ष 2014-22 के दौरान इसकी समग्र दक्षता बढ़ने से अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्व मजबूत हुए. बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्रों की बेहतर तुलन पत्र के कारण नए सिरे से ऋण चक्र शुरू किया जा चुका है, जो कि विगत महीनों के दौरान बैंक ऋणों में दर्ज की गई दहाई अंकों की वृद्धि दर से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है. भारतीय अर्थव्यवस्था इसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक औपचारीकरण, वित्तीय समावेश के बल पर बढ़ती दक्षता और डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक सुधारों से सृजित आर्थिक अवसरों से लाभान्वित होने लगी है.

राजकोषीय घटनाक्रम: राजस्व में तेज उछाल : केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान काफी सुदृढ़ हो चुकी है जो कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ने, प्रत्यक्ष करों एवं जीएसटी से होने वाले राजस्व में तेज उछाल और बजट में यथार्थवादी अनुमान लगाए जाने से ही संभव हो पाया है. अप्रैल-नवम्बर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जो कि प्रत्यक्ष करों और जीएसटी में दमदार वृद्धि से संभव हुआ. सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी जिससे आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी अनुपात को एक दायरे में सीमित रखना संभव हो पाएगा.

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: आरबीआई ने अप्रैल 2022 में अपनी मौद्रिक नीति को सख्त बनाना शुरू किया था और उस समय से लेकर अब तक रेपो रेट में 225 आधार बिन्दु की वृद्धि हुई है, जिससे अधिशेष चलनिधि में कमी आई है. तुलन पत्र को दुरुस्त करने से वित्तीय संस्थानों के ऋणों में वृद्धि हुई है. ऋणों के उठाव में दर्ज की गई वृद्धि के आगे भी जारी रहने की आशा है और इसके साथ ही निजी पूंजीगत व्यय बढ़ने से लाभप्रद निवेश चक्र शुरू हो जाएगा.

सामाजिक अवसंरचना और रोजगार : सामाजिक क्षेत्रों पर सरकारी खर्च में व्यापक वृद्धि देखने को मिली है. स्वास्थ्य क्षेत्र पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 (बीई) में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2022

(आरई) में जीडीपी का 2.2 प्रतिशत हो गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी का 1.6 प्रतिशत ही था. सामाजिक क्षेत्र पर व्यय वित्तीय वर्ष 2016 के 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 (बीई) में 21.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है.

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन : कृषि व संबंधित क्षेत्र का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों से लगातार मजबूत हो रहा है. फसल एवं मवेशी उत्पादकता में वृद्धि, समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को निश्चित आमदनी सुनिश्चित करने, फसलों में विविधता को बढ़ावा देने, किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना के माध्यम से बाजार अवसंरचना में सुधार लाने तथा कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से ढांचागत सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई उपाय किए गए हैं, तथा

- वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश 9.3 प्रतिशत बढ़ा.
- वर्ष 2018 से सभी अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत का 1.5 गुणा निर्धारित किया गया.
- वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण लगातार बढ़कर 18.6 लाख करोड़ हो गया.
- भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई और वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 315.7 मिलियन टन हो गया.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों के लिए मुफ्त खाद्यान्न.
- योजना के अंतर्गत अप्रैल-जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में लगभग 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया.
- कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल पश्चात समर्थन और सामुदायिक खेती के लिए 13,681 करोड़ रुपए मंजूर.
- राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों के साथ ऑनलाइन, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी निविदा प्रणाली लागू.
- परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है.
- अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

निरंतर सुधार करते उद्योग: औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य संवर्धन (जीवीडब्ल्यू) में 3.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई (वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए), जो पिछले दशक के पूर्वार्ध के दौरान हासिल की गई 2.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक है. वर्ष की पहली छमाही के दौरान निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में मजबूत वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन, संवर्द्धित सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और मजबूत बैंक एवं कॉरपोरेट तुलन पत्र के कारण निवेश की मांग में वृद्धि. बढ़ी हुई मांग के प्रति उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया मजबूत रही है. जुलाई 2021 से 18 महीनों के लिए पीएमआई विनिर्माण विस्तार क्षेत्र में कायम रहा है. औद्योगिक विस्तार सूचकांक में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण में जनवरी 2022 से औसतन लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बड़े उद्योगों में अक्टूबर 2022 से दहाई के आंकड़े में वृद्धि देखी गई है.

सेवाएं- सुदृढ़ता का स्रोत : वित्तीय वर्ष 2022 में 8.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र के 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है. जुलाई 2022 से पीएमआई सेवाओं, जो कि सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का संकेतक है, में जबरदस्त विस्तार देखा गया. भारत 2021 में शीर्ष दस सेवा निर्यात करने वाले देशों में शामिल था, विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2015 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 4 प्रतिशत हो गई. कोविड-19 महामारी के दौरान और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच डिजिटल समर्थन, क्लाउड सेवाओं और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की उच्च मांग द्वारा प्रेरित भारत का सेवा निर्यात सशक्त बना रहा.

निष्कर्ष : भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने को स्थापित कर चुका है. भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी ज्यादा है. वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है. माननीय प्रधानमंत्री ने 31 मई 2023 को कहा कि 2022-23 की जीडीपी वृद्धि के आंकड़े वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को रेखांकित करते हैं. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यह माना है कि आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा. दरअसल, वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि 9.1% रही थी, और वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7.2% रहने की संभावना जताई है, जो पूरी दुनिया के प्रमुख देशों की तुलना में काफी ज्यादा है.

पूर्व में योजनाबद्ध तरीकों से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बनी कार्ययोजना और उसके सफल कार्यान्वयन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्वपटल पर स्थापित करने का कार्य किया है. अमृत काल के दौर मे नयी उर्ज़ा व नए संकल्पों से हमारी जीवंत अर्थव्यवस्था नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है.

शैलेश कुमार
यूनियन ज्ञानार्जन अकादमी, बेंगलूरु

अमृत काल और फिनटेक

आत्मनिर्भर भारत होने के क्रम में, हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए, भारत एशिया में फिनटेक (FinTech) के सबसे बड़े बाज़ार के रूप में उभरा है. विश्व के दूसरे सबसे बड़े फिनटेक हब (अमेरिका के बाद) के रूप में उभरने के बाद भारत में 'फिनटेक बूम' अर्थात् फिनटेक का तीव्र और व्यापक विकास देखा गया है. वर्तमान समय में फिनटेक अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक संपन्न क्षेत्रों (व्यापार वृद्धि और रोज़गार सृजन दोनों मामलों में) में से एक है. फिनटेक, वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ वित्तीय समायोजन एवं अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक रहा है.

क्या है फिनटेक : फिनटेक, 'फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी' का संक्षिप्त रूप है. वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है.

दूसरे शब्दों में यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन है. फिनटेक शब्द का प्रयोग उन नयी तकनीकों के संदर्भ में किया जाता है, जिनके माध्यम से वित्तीय सेवाओं का प्रयोग, इसमें सुधार और स्वायत्तता लाने का प्रयास किया जाता है. डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऋण, बैंक टेक, इंश्योर टेक, रेगटेक, क्रिप्टोकरेंसी आदि फिनटेक के कुछ प्रमुख घटक हैं.

तथापि वर्तमान में फिनटेक के तहत कई अलग-अलग क्षेत्र और उद्योग जैसे-शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, निधि जुटाना और गैर-लाभकारी कार्य, निवेश प्रबंधन आदि भी शामिल किए जा रहे हैं.

फिनटेक नवोन्मेष के सक्रिय क्षेत्र:

ब्लॉकचेन तकनीक: इसके तहत किसी केंद्रीय बहीखाते की बजाय कंप्यूटर नेटवर्क पर लेन-देन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है.

स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसके तहत कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से (अक्सर ब्लॉकचेन का उपयोग करते हुए) खरीदारों और विक्रेताओं के बीच करारों को स्वचालित रूप से निष्पादित किया जाता है.

ओपन बैंकिंग: ओपन बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत बैंक नए एप्लीकेशन और सेवाओं को विकसित करने हेतु तीसरे पक्ष को अपने 'एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस' (एपीआई) की सुविधा प्रदान करते हैं. ओपन बैंकिंग के तहत कार्यरत बैंकों को फिनटेक के साथ प्रतिस्पर्द्धा की बजाय साझेदारी करने का अवसर प्राप्त होता है.

इंश्योर टेक: इसके तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से बीमा उद्योग को सरल और कारगर बनाने का प्रयास किया जाता है.

रेगटेक: रेग टेक, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है. इसका उपयोग व्यवसायों द्वारा कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से औद्योगिक क्षेत्र के नियमों का पालन करने में सहायता के लिए किया जाता है.

साइबर सुरक्षा: देश में साइबर हमलों के मामलों में वृद्धि और विकेंद्रीकृत डेटा के कारण फिनटेक तथा साइबर सुरक्षा के मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.

भारत में फिनटेक के विकास के प्रमुख घटक:

- व्यापक पहचान औपचारीकरण (आधार के माध्यम से): 1.2 बिलियन नामांकन.
- जन-धन योजना जैसे प्रयासों के माध्यम से बैंकिंग पहुँच में वृद्धि: 1 बिलियन से अधिक बैंक खाते.
- व्यापक स्मार्टफोन पहुँच: 1.2 बिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोक्ता.
- भारत में व्यय योग्य आय में वृद्धि.
- भारत सरकार द्वारा यूपीआई और डिजिटल इंडिया जैसे प्रमुख प्रयास.
- मध्यम वर्ग का व्यापक विस्तार: वर्ष 2030 तक भारत की मध्यम वर्गीय आबादी में 140 मिलियन नए परिवार और उच्च-आय वर्ग की आबादी में 21 मिलियन नए परिवार जुड़ जाएंगे, जो देश के फिनटेक बाज़ार में मांग और विकास को गति प्रदान करेंगे.

फिनटेक से जुड़ी संभावनाएँ:

व्यापक वित्तीय समावेशन: वर्तमान में भी देश की एक बड़ी आबादी औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर है. वित्तीय प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के माध्यम से पारंपरिक वित्तीय और बैंकिंग मॉडल में वित्तीय समावेशन से जुड़ी चुनौतियों को दूर किया जा सकता है.

एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना: वर्तमान में देश में सक्रिय 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)' के अस्तित्व के लिए पूंजी का अभाव सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है. 'अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम' की रिपोर्ट के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र के लिए आवश्यक और उपलब्ध पूंजी का अंतर लगभग 397.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आँका गया है. ऐसे में एमएसएमई क्षेत्र में फिनटेक का महत्व बढ़ जाता है, जिसमें इस क्षेत्र में पूंजी की कमी को दूर करने की क्षमता भी है.

कई फिनटेक स्टार्टअप द्वारा आसान और त्वरित ऋण उपलब्ध कराए जाने पर एमएसएमई को कई बार बैंक जाने और जटिल कागज़ी प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी.

ग्राहक अनुभव और पारदर्शिता में सुधार: फिनटेक स्टार्टअप सहूलियत, पारदर्शिता, व्यक्तिगत और व्यापक पहुँच तथा उपयोग में सुलभता जैसी महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जो ग्राहकों को सशक्त बनाने में सहायता करते हैं. फिनटेक उद्योग द्वारा जोखिमों के आकलन के लिए अद्वितीय और नवीन मॉडल का विकास किया जा रहा है.

बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ऋण जोखिम के निर्धारण हेतु वैकल्पिक डेटा का लाभ उठाकर और सीमित क्रेडिट इतिहास वाले ग्राहकों के लिए क्रेडिट स्कोर विकसित कर देश में वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार लाने में सहायता प्राप्त हो रही है.

चुनौतियाँ:

साइबर हमले: प्रक्रियाओं का स्वचालन और डेटा का डिजिटलीकरण फिनटेक प्रणाली को हैकरों के हमलों के प्रति सुभेद्य बनाता है.

हाल ही में कई डेबिट कार्ड कंपनियों और बैंकों में हुए साइबर हैकिंग के हमलें इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हैकर्स कितनी आसानी से महत्वपूर्ण प्रणालियों तक पहुँच प्राप्त कर इनमें अपूरणीय क्षति का कारण बन सकते हैं.

डेटा गोपनीयता की समस्या: उपभोक्ताओं के लिए साइबर हमलों के साथ-साथ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा का दुरुपयोग भी एक बड़ी चिंता का कारण है.

विनियमन में कठिनाई: वर्तमान समय में तेज़ी से उभरते फिनटेक क्षेत्र (विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी) का विनियमन भी एक बड़ी समस्या है. वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में फिनटेक के विनियमन हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं, ऐसे में विनियमन के इस अभाव ने इस क्षेत्र में घोटाले और धोखाधड़ी की घटनाओं को बढ़ावा दिया है. फिनटेक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की विविधता के कारण इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए कोई एकल और व्यापक समाधान तैयार करना बहुत ही कठिन है.

आगे की राह:

साइबर अपराधियों से सुरक्षा: वर्तमान में भारत साइबर हमलों के विरुद्ध सुरक्षात्मक और आक्रामक दोनों क्षमताओं के लिए लगभग पूरी तरह आयात पर ही निर्भर है. देश में विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता और इसकी पहुँच में व्यापक वृद्धि को देखते हुए भारत के लिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है.

उपभोक्ता जागरूकता: तकनीकी सुरक्षा उपायों की स्थापना के साथ फिनटेक के लाभ और साइबर हमले से बचाव के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए ग्राहकों को शिक्षित और प्रशिक्षित किए जाने से भी फिनटेक के लोकतांत्रिकीकरण में सहायता प्राप्त होगी.

डेटा सुरक्षा कानून: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रभावों की समीक्षा के लिए फिनटेक सैंडबॉक्स की स्थापना का निर्णय लिया जाना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है. तथापि देश में एक मज़बूत डेटा सुरक्षा ढाँचे की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है. इस संदर्भ में 'व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2019' को व्यापक विचार-विमर्श के बाद पारित किया जाना चाहिए.

निष्कर्ष: वर्तमान समय की ज़रूरतों के अनुरूप फिनटेक भारतीय आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों के लिए उपयुक्त समाधान उपलब्ध कराते हैं. फिनटेक में बीमा, निवेश, विप्रेषण जैसी अन्य वित्तीय सेवाओं में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता है. हालाँकि इस क्षेत्र में विनियमन के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी प्रयास इसके विकास में सहायक होना चाहिए न कि बाधक.

रूपेश कुमार उपाध्याय
क्षे. का., अहमदाबाद

अमृत काल के पंच प्रण और बैंकिंग

अमृत काल का संकल्पना में पंच प्रण समाहित हैं यथा 'विकसित भारत', 'गुलामी से मुक्ति', 'विरासत पर गर्व', 'एकता और एकजुटता' और 'नागरिकों का कर्तव्य'.

1. विकसित भारत: 'पंच प्रण' में पहला बड़ा संकल्प है- विकसित भारत. छोटे-छोटे संकल्प का अब समय नहीं है. आने वाले 25 वर्षों में हमें विकसित भारत चाहिए. स्वच्छता अभियान, कोरोना वैक्सीनेशन अभियान, ढाई करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन, खुले में शौच से मुक्ति, गैर परंपरागत ऊर्जा, हम सभी मानकों पर संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं. इन्हीं से भारत के विकसित देश बनाने की नींव डाली गई है.

लगभग चालीस करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं. विगत आठ वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार,मोबाइल जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए देश के दो लाख करोड़ रुपए को गलत लोगों के हाथों तक जाने से रोक दिया गया है. आत्मनिर्भर अभियान भी भारत को विकसित बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है. इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. पीएलआई योजनाओं के माध्यम से, हम दुनिया के विनिर्माण ऊर्जाघर बन रहे हैं. लोग "मेक इन इंडिया" के लिए भारत आ रहे हैं.

महिला एवं बाल विकास में निवेश किसी भी राष्ट्र के बेहतर भविष्य के निर्माण की कुंजी है. बच्चों के मूल्य, शिक्षा और स्वास्थ्य देश के सामाजिक और आर्थिक संकेतकों को सीधे प्रभावित करते हैं और इसके वैश्विक स्तर को भी आकार देते हैं. इसलिए, यह अवश्यंभावी है कि बच्चों की नागरिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षा; स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और नवीनतम विकास के सर्वत्र क्षेत्रों (वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, कला, शैक्षिक आदि) तक पहुंच हो. हालांकि भारत में शिशुपालन में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, फिर स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के बच्चों के लिए, काम किया जाना बाकी है.

इसी तरह, परिवार इकाई के भीतर और बाहर महिलाएं किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक हैं. भारतीय संदर्भ में, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई मोर्चों पर स्पष्ट प्रगति के साथ, महिलाओं का आंदोलन एक लंबी यात्रा तय कर चुका है. यह प्रगति कड़ी मेहनत से अर्जित की गई है जो कि इस मुद्दे पर समस्त मोर्चों के प्रयासों का परिणाम है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाएं और योजनाएं, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत रूप से शामिल महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने साहस और निरंतर प्रयासों से भारत के ताने-बाने को बदल दिया है.

2. गुलामी से मुक्ति: 'पंच प्रण' में दूसरा संकल्प 'गुलामी से मुक्ति' है यानी हमारे मन के भीतर किसी भी कोने में गुलामी का एक भी अंश न बचा रहे. यदि जरा भी गुलामी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है, उसे उखाड़ फेंकना है. सैकड़ों वर्षों की गुलामी से जिसने हमें जकड़कर रखा था, हमें 100 फीसदी मुक्ति पानी ही होगी. गुलामी किसी भी देश को दीमक की तरह धीरे-धीरे खा जाती है, जिसका लंबे समय बाद पता चलता है.

12 मई 2020 को, माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान (आत्मनिर्भर भारत अभियान) की शुरुआत करते हुए राष्ट्र को एक स्पष्ट आह्वान किया और भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की.

इसका उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को हर मायने में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है.

♦ **कैसे होगा भारत आत्मनिर्भर:**

- **आधारभूत संरचना:** भारत की आधारभूत संरचना की प्रगति और उसके मील के पत्थर बनने का उत्सव मनाना और यह कि कैसे यह विकास और आत्मानिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है.
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अभिगम्यता:** पेमेंट एप्लिकेशन, फूड ऑर्डरिंग, किराना खरीददारी, टेली मेडिसिन, टेली लॉ आदि - जो इस बात पर ध्यान आकृष्ट करता है कि डिजिटल एक्सेस कैसे आत्मनिर्भरता को सक्षम बना रहा है.
- **युवा और उद्यमिता, स्टार्टअप:** उद्यमशीलता की मानसिकता को विकसित करने के लिए कार्यक्रम, समूह आधारित शिक्षा और परामर्श के अवसर, प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आदि, वैश्विक विकास और प्रगति में योगदान देने वाले भारत के अभिनव स्टार्टअप.
- **क्षेत्रीय सुधार और आत्मनिर्भरता:** क्षेत्रीय सुधारों, प्रभाव आकलन, परिवर्तन और सुधार के लिए अभियान, व्यापार करने में सुगमता आदि के माध्यम से मूल्यांकन करना.
- **सक्षम मानव संसाधन:** कौशल विकास और मानव संसाधन का प्रशिक्षण. नए रोजगरों के विकल्प और चयन .
- **मजबूत वित्तीय प्रणाली:** सरलीकरण के माध्यम से महिलाओं, ग्रामीण लक्ष्य समूहों और अन्य के लिए धन प्रबंधन कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा शिविरों तक पहुँच.
- **लोकल हेतु वोकल:** कम आयात, बढ़ा हुआ निर्यात, जमीनी स्तर पर अभियान जो स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार का समर्थन करते हैं, आत्मनिर्भरता की दिशा में स्थानीय पहलों को विशिष्ट

रूप से दर्शाने वाली ग्रामीण परियोजनाएं.

- **सहयोगात्मक प्रयासों से आत्मानिर्भरता को बढ़ावा देना:** ऐसे पहल और कार्यक्रम जो संसाधनों और उत्पादन की बेहतर क्षमता प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों, उद्योगों, संस्थानों के बीच के अवरोधकों को तोड़ते हैं.

- **भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र:** इस संदर्भ में अभियानों, उपलब्धियों को उजागर करना. (उदाहरण - मेड इन इंडिया आई. फोन)

3. **विरासत पर गर्व:** भारत कई संस्कृतियों का देश है, यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो 4,000 साल से भी अधिक पुरानी है. इस कालावधि के दौरान कई रीति-रिवाज और परंपराएं साथ-साथ उभरकर आईं, जो इस देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाती हैं. हमें अपने देश की विरासत पर गर्व होना चाहिए. हमें अपने सामर्थ्य पर भरोसा होना चाहिए. इसी विरासत ने भारत को कभी स्वर्ण काल दिया था. हमें अपनी पारिवारिक व्यवस्था पर भी गर्व करना है. हमारी विरासत को विश्व मान रहा है. भारत की जीवनशैली से विश्व प्रभावित है. सबके सुख और सबके आरोग्य की बात करना हमारी विरासत की प्राथमिकता है. हम वे लोग हैं जो जीव में शिव देखते हैं. हमें विश्व से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं. देश को अपना एक मानक बनाना होगा. हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, तभी ऊंचा उड़ेंगे. हमारे पास विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है. भारत के पास अनमोल क्षमता है.

एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत होने से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रवर्तक होने तक, यह देश किसी सीमा से बाधित नहीं है. यह कहना उचित होगा कि इस देश के लोगों को अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व है और वे लगातार अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.

लोकप्रिय हिंदी सूक्ति 'कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी' भारत की भाषाई विविधता को परिभाषित करती है. भारत जैसी बहु-जातीय भूमि में, एक साझा भाषा हमारी एकजुटता की सूत्रधार एवं हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा के दौरान हमारी भव्य विरासत स्मारकों के दर्शन किया जा सकता है. लोग गर्व से अपनी संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन, बोली और पोशाक को अपना रहे हैं.

- **भारतीय साहित्य का प्रचार**: क्षेत्रीय प्रकाशन संस्थाओं को मान्यता देना, भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति और अन्य देशों की भाषाओं पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता; ऐतिहासिक पुस्तकालयों आदि के बारे में जागरूकता.

- **कलारूप:** गीत, नृत्य, रंगमंच, संगीत, लोक परंपराओं, चित्रों और लेखन के सबसे बड़े संग्रहों में से एक जिसे 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' के रूप में जाना जाता है, भारत से संबंधित है.

- **राष्ट्रीय पहचान:** देश प्रगति कर रहा है और युवा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं.

- **भाषा सीखने के विभिन्न तरीकों का प्रसार:** बोलना, सुनना, लिखना; ऐप-आधारित शिक्षा के बारे में जागरूकता (उदाहरण के लिए, शिक्षा मंत्रालय का भाषा संगम ऐप); प्रौद्योगिकी और भाषाओं के बीच संबंध; स्पीड लर्निंग की गतिविधियाँ; भाषा आदि सीखने के लिए क्षेत्रीय समाचार पत्रों का उपयोग करना.

- **भूगोल और अंतरिक्ष:** भारत एक वैविध्यपूर्ण भूगोल और जलवायु युक्त देश है. उत्तरी भारत हिमालय की बर्फीली पर्वत शृंखला और विशाल थार रेगिस्तान द्वारा संरक्षित है. दक्षिण भारत में, उष्णकटिबंधीय जंगल, वर्षावन, तटीय मैदान, द्वीप और समुद्र तट पाए जाते हैं.

4. **एकता और एकजुटता:** हमें अपनी देश की विविधता को बड़े उल्लास से मनाना चाहिए. लैंगिक समानता, फर्स्ट भारत, देश के श्रमिकों का सम्मान इसी कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है. जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, तभी हम ऊंची उड़ान भरेंगे तभी विश्व को समाधान दे पाएंगे. क्योंकि किसी देश की सबसे बड़ी ताक़त उस देश की एकता और एकजुटता में होती है. अगर ये न हों तो देश के पतन की शुरुआत होने लगती है.

5. **नागरिकों का कर्तव्य:** नागरिकों का कर्तव्य देश और समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करता है. बिजली की बचत, खेतों में मिलने वाले पानी का पूरा इस्तेमाल, केमिकल मुक्त खेती, हर कीमत पर भ्रष्टाचार से दूरी आदि हर क्षेत्र में नागरिकों की जिम्मेदारी और भूमिका बनती है. किसी देश का प्रत्येक नागरिक अगर अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाने लगे तो देश हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है. आने वाले 25 वर्ष के लिए हमें भी इन पंच प्रण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा. हमें पंच प्रण को लेकर वर्ष 2047 तक चलना है, जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे.

आज़ादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नज़रिया बदल चुका है. समस्याओं का समाधान समूचा विश्व भारत की धरती पर खोजने लगा है. विश्व का यह बदलाव, विश्व की सोच में यह परिवर्तन 75 वर्ष की हमारी यात्रा का परिणाम है. 'पंच प्रण' के माध्यम से आने वाले 25 वर्षों का एक ब्लू प्रिंट तैयार कर दिया गया है, जो यदि सफलतापूर्वक पूरा हो जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा.

चारु शर्मा
क्षे. का., बेंगलूरु (उत्तर)

कौशल विकास में बैंकों का योगदान

बैंकों का कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है जो आर्थिक विकास और सामरिकता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कौशल विकास राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है. बैंकों के माध्यम से कई कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो युवाओं और सामान्य लोगों को आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करते हैं.

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: बैंकों द्वारा चलाए जाने वाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम लोगों को वित्तीय मामलों की समझ और वित्तीय प्रबंधन का कौशल सीखने में मदद करते हैं. ये कार्यक्रम बैंकिंग सेवाओं का प्रचार करते हैं, निवेश करने की समझ प्रदान करते हैं और बचत और व्यय की आयोजना को सुनिश्चित करते हैं. इसके माध्यम से बैंक संस्थानों द्वारा वित्तीय साक्षरता के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अक्सर सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं. इन कार्यक्रमों में वित्तीय शिक्षा और ज्ञान सुविधाजनक और सुलभ ढंग से प्रदान किया जाता है. ये कार्यक्रम आमतौर पर लघु अवधि के होते हैं और व्यक्तियों को वित्तीय दक्षता प्राप्त करने में सहायता करते हैं. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में विभिन्न पाठ्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है. इनमें वित्तीय अवधारणाएं, वित्तीय योजनाएं, बैंकिंग सेवाएं, बचत, निवेश, पेंशन योजनाएं, कर, बाजार अनुसंधान, निवेश विचारधारा और व्यापारिक मानदंड आदि शामिल हो सकते हैं. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे लोगों का वित्तीय स्वाधीनता प्रदान करने में मदद करते हैं. इनके द्वारा लोग व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने, सही निवेश करने, अच्छे कारोबारी फैसलों को लेने, वित्तीय संकटों से निपटने और व्यापारिक संबंधों में सक्षम बनने की क्षमता विकसित कर सकते हैं. यह कार्यक्रम आमतौर पर वित्तीय संस्थाओं, निगमित संगठनों, बैंकों, शिक्षा संस्थानों और सरकारी निकायों द्वारा संचालित किए जाते हैं. इन कार्यक्रमों में आम जनता, उद्यमी, छात्र, व्यापारियों, किसानों, और बच्चों को शामिल किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उन्हें वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाना है.

उद्यमिता विकास: बैंकों द्वारा संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रम नए और मजबूत उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं. ये कार्यक्रम उद्यमियों को विभिन्न व्यापारिक कौशल, वित्तीय योजनाएं, व्यापार के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया, विपणन और नवाचारों के बारे में जागरूकता प्रदान करते हैं. इससे उद्यमियों को व्यवसाय की शुरुआत से लेकर स्थायित्व तक का समर्थन मिलता है. बैंकों को आमतौर पर अपनी सेवाओं और वित्तीय संरचना के माध्यम से उद्यमियों को सहायता प्रदान करने का विशेष दायित्व होता है. वे उद्यमियों को आर्थिक समर्थन, कार्यनीति सलाह और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उनके व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं. बैंक उद्यमियों को उचित वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके व्यवसाय का समर्थन करते हैं. यह ऋण, संयुक्त ऋण योजनाएं, सामग्री वितरण व्यवस्था और उद्यमी को वित्तीय समाधानों के बारे में सलाह प्रदान करने के माध्यम से हो सकता है. बैंकों द्वारा उद्यमियों को उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन किया जाता है जो उन्हें व्यावसायिक ज्ञान, नवाचार और कौशल प्रदान करते हैं. ये प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्यमी को व्यापार निर्माण, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और अन्य नवीनतम उद्योग रचनाएं सीखने में मदद करते हैं. बैंकों के विशेषज्ञ सलाहकारों द्वारा उद्यमियों को सलाह प्रदान की जाती है. यह सलाह उद्यमी को व्यवसाय मॉडल, विपणन, वित्तीय नियोजन और उचित निवेश द्वारा उनके व्यवसाय की प्रगति में मदद करती है. बैंकों की उद्यमिता विकास प्रक्रिया कारगर तरीके से उद्यमियों को समर्थित करती है और व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को संभव बनाती है. यह आर्थिक स्थिरता, नया रोजगार सृजन और समुदाय के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है.

डिजिटल कौशल विकास: बैंकों द्वारा डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनका मकसद लोगों को डिजिटल तकनीकों की समझ और उपयोग में सुविधा प्रदान करना होता है. ये कार्यक्रम इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सेवाएं और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता प्रदान करते हैं. इससे लोगों को आधुनिक तकनीकी कौशलों की प्राप्ति होती है, जिससे वे डिजिटल युग में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. बैंकों द्वारा उद्योग, व्यापार और ग्राहकों को डिजिटल लेन-देन विकल्प प्रदान किए जाते हैं. यह इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई-वॉलेट, डिजिटल भुगतान और अन्य डिजिटल मुद्रा समाधानों के उपयोग से हो सकता है. बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को ई-व्यापार के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है. यह ऑनलाइन वित्तीय सेवाएं, वित्तीय प्रबंधन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विकल्प और ई-कॉमर्स लाभ के रूप में हो सकता है. बैंकों द्वारा ग्राहकों के बीच संबंधों के निर्माण के लिए डिजिटल साधनों का उपयोग किया जाता है. यह ऑनलाइन वीडियो चैट, इंस्टैंट मेसेजिंग, ईमेल समाधान और सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है. बैंकों द्वारा ग्राहकों की सुरक्षा और गोपनीयता के मानकों का ध्यान रखा जाता है. यह साइबर सुरक्षा, डेटा एन्क्रिप्शन, बायोमेट्रिक उपयोगकर्ता पहचान और डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के उपयोग से हो सकता है. डिजिटल कौशल विकास द्वारा बैंक उद्योग, व्यापार और व्यक्तिगत ग्राहकों को आधुनिक तकनीकी उपायों को अपनाने में सहायता प्रदान करते हैं. इससे उद्योग की प्रगति, डिजिटल वित्तीय समावेश और आर्थिक सुविधाओं के समर्थन में सुधार होता है.

कृषि और ग्रामीण कौशल विकास: बैंकों द्वारा कृषि और ग्रामीण कौशल विकास का समर्थन एक महत्वपूर्ण पहलू है. बैंकों द्वारा कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो किसानों और ग्रामीण समुदायों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं. बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने और उनके कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण दायित्व होता है. इसमें कृषि तकनीक, विपणन, सहकारिता, वित्तीय प्रबंधन, खेती और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास शामिल होते हैं. इसके माध्यम से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विपणन की समझ, समृद्धि के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया, नवाचारी तकनीकों का उपयोग और सामुदायिक विकास के बारे में जागरूकता प्राप्त होती है. बैंकों द्वारा किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सलाह प्रदान की जाती है. ये उन्हें उचित निवेश, ग्रामीण उद्यम संचालन, कृषि विपणन और वित्तीय प्रबंधन के मामले में मार्गदर्शन करते हैं. बैंकों द्वारा कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन किया जाता है. इसमें किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को नवीनतम कृषि तकनीक, विपणन, संगठन व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और उचित प्रशासनिक कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की स्थापना, किसानों के लिए खाता खोलना, स्वरोजगार ऋण, मुद्रा कार्ड, और डिजिटल बैंकिंग समाधान शामिल हो सकते हैं. बैंकों द्वारा कृषि और ग्रामीण कौशल विकास से किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय स्वायत्तता, उचित निवेश, विपणन सुविधाएं और अधिक समृद्धि का अवसर मिलता है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार, सामाजिक विकास और स्थायित्व की प्राप्ति होती है.

व्यापारिक कौशल विकास: बैंकों द्वारा व्यापारिक कौशल विकास का समर्थन एक महत्वपूर्ण पहलू है. बैंकों को व्यापारिक कौशल विकास कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता होती है जो व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करते हैं. ये कार्यक्रम व्यापारिक कौशलों, बाजार विचार, विपणन, प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और व्यापार संचालन के बारे में जागरूकता प्रदान करते हैं. इससे व्यापारिक क्षेत्र में नवीनतम कौशलों की प्राप्ति होती है और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाता है. बैंकों द्वारा व्यापारियों को वित्तीय सलाह और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है. यह उन्हें व्यवसायिक निवेश, वित्तीय नियोजन, कारोबारी ऋण, और स्थिरता के मामले में मदद करता है. बैंकों द्वारा व्यापारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन किया जाता है और उद्यमियों को विभिन्न व्यापारिक कौशलों तथा विपणन, प्रबंधन, बिक्री, उत्पादन, और नवाचार का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं. बैंकों द्वारा उद्योग के विकास का समर्थन किया जाता है और उद्यमियों को नए उत्पाद तथा सेवाओं के विकास, नवीनतम तकनीक के अनुसरण और उद्यमिता के प्रोत्साहन के माध्यम से उनके व्यापार की प्रगति में मदद करते हैं. बैंकों द्वारा ग्राहकों की सेवा और उनकी आवश्यकताओं को समझने पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें उचित उत्पादों और सेवाओं की पहचान, मार्गदर्शन और ग्राहकों के साथ संबंध निर्माण में मदद करते हैं. व्यापारिक कौशल विकास के माध्यम से बैंकों द्वारा व्यापारियों का स्वायत्तता, सुगमता और उच्चतम उत्पादकता की संभावनाएं प्रदान की जाती हैं. इससे व्यापारियों की सफलता बढ़ती है, नए रोजगार के अवसर बनते हैं और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है.

इन सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक न केवल लोगों को आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं. ये कार्यक्रम लोगों को स्वावलंबी बनाने, रोजगार के अवसर प्रदान करने, उच्चतम उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति में मदद करते हैं. इसके अलावा, ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता और विकास को प्रोत्साहित करते हैं और अधिक सशक्त समुदायों का निर्माण करने में मदद करते हैं.

प्रभात मोहराणा
दासरहल्ली शाखा, बेंगलूरु (उत्तर)

बैंकिंग में ज्ञानार्जन और विकास का महत्व

बैंकिंग कारोबार विश्वास की आधारशिला पर निर्भर है. बैंकिंग संस्थाएं समाज के विभिन्न पहलुओं को संचालित करने, आर्थिक विकास सुनिश्चित करने व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. बैंकिंग में ज्ञानार्जन व विकास का महत्त्व न केवल आर्थिक वर्ग वरन समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनिवार्य है. जब हम ज्ञानार्जन और विकास की चर्चा करते हैं तो शिक्षाविदों के विचार अनायास ही स्मृति पटल पर उभर आते हैं:

"सबसे अच्छा ज्ञानार्जन वह होता है जो आपको अपनी सोच को बदलने और नए संभावनाओं को देखने के लिए प्रेरित करता है."

- स्वामी विवेकानंद

ज्ञानार्जन व विकास बैंकिंग में शिक्षा, जागरूकता और सूचनाओं को संकल्पित करता है. जब सभी बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूक होते हैं तो वे आर्थिक योजनाओं को समझने, वित्तीय निर्णय लेने और बैंकिंग सेवाओं के उचित उपयोग करने हेतु सक्षम हो जाते हैं. ज्ञानार्जन के माध्यम से कार्मिक स्वतंत्र व सटीक निर्णय लेते हुए अपने आर्थिक दृष्टिकोण को सशक्त बनाते हैं. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाज व शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रत्येक वित्तीय संस्था को ज्ञानार्जन के साथ व्यक्तित्व विकास के महत्त्व को समझना ही होगा.

बैंकिंग उद्योग का सेवा उद्योग से अधिक आई.टी. उद्योग के रूप में स्थापित होना: बैंकिंग उद्योग की भारतीय व वैश्विक अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है तथापि, वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य में तकनीकी प्रगति के साथ बैंकिंग कारोबार में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व बहुत तेजी से बढ़ा है. आज का बैंकिंग परिवेश सामान्य सेवा से ऊपर उठकर सूचना तकनीकी व कंप्यूटर की दुनिया में समाती जा रही है. आज बैंक के प्रत्येक ग्राहक को तकनीकी सक्षम सेवा प्रदान करना आवश्यकता बन चुकी है. बैंकों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज्ञानार्जन द्वारा विकास का सहारा लेना ही होगा.

व्यावसायिक सहयोगी की भूमिका में ज्ञानार्जन और विकास: बैंकिंग उद्योग बहुत तेजी से बदल रहा है, साथ ही नवीनतम तकनीकी और नित नए प्रक्रिया परिवर्तनों के कारण नित नई कठिनाइयों का भी सामना कर रहा है. इस विकट स्थिति में बैंकों को अपने कर्मचारियों हेतु नवीनतम जानकारी और कौशल प्रदान करने हेतु संरचित और मजबूत 'ज्ञानार्जन और विकास' कार्यक्रम की आवश्यकता है. इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें नवीनतम बैंकिंग प्रक्रियाओं, सेवाओं और नियमों से अवगत कराते हैं. बैंकिंग व्यवसाय में ज्ञानार्जन और विकास के एक विभाग के रूप में काम करने से संस्था को कारोबारी सहयोगी के रूप में सीधा लाभ पहुंचता है. ज्ञानार्जन और विकास बैंक के कर्मचारियों को नवीनतम उत्पादों और सेवाओं के लिए जागरूक बनाने के साथ तुलन पत्र के प्रत्येक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है.

आस्क (ASK एटीट्यूड, स्किल व नॉलेज) की निरंतर प्रक्रिया: यह निरंतर विकास का उपाय है, जिसका उपयोग व्यावसायिक व व्यक्तिगत विकास में किया जाता है. प्रवृत्ति (एटिट्यूड) कौशल (स्किल) और ज्ञान (नॉलेज) इन तीन महत्वपूर्ण तत्वों को संजोने के लिए इस चक्र का उपयोग किया जाता है. इसका उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास को समायोजित और सुगम बनाना है. ऑस्क चक्र के उपयोग द्वारा व्यक्ति अपनी प्रवृति, कौशल और ज्ञान को संतुलित रूप से विकसित कर समृद्धि, सफलता और आत्म-प्रगति की ओर उन्मुख हो सकता है. व्यक्ति के समग्र विकास हेतु इन कौशलों को ज्ञानार्जन द्वारा विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है.

प्रवृत्ति: प्रवृति व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोचने के तरीके और व्यवहार को निर्धारित करता है. सकारात्मक प्रवृत्ति संचार, सहयोग, समस्या समाधान की क्षमता को प्रोत्साहित करता है. प्रवृत्ति व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार का आधार है, जो दृष्टिकोण व व्यक्तित्व को प्रभावित करती है. सकारात्मक प्रवृत्ति समस्याओं का सामना करने, लक्ष्यों को पार करने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करती है.

कौशल: कौशल व्यक्ति की कार्य प्रणाली को संचालित करने और उच्चतर स्तर का प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है. यह कार्य-क्षमता, समस्या समाधान, संगठन कौशल और नवीनता को विकसित करने में मदद करता है. कौशल विकास द्वारा ही व्यक्ति प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है. कौशल व्यक्ति को एक सक्षम और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है.

ज्ञान: ज्ञान व्यक्ति की जानकारी तथ्य, विचार और संसाधनों का संग्रह होता है. यह व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए संसाधनों तक पहुंचने और नवीनतम विकास को समझने में मदद करता है. ज्ञान से व्यक्ति नए कौशल, अवसरों का पता लगाने और स्वयं को समृद्ध करने का रास्ता बनाता है. ज्ञान, शिक्षा, अनुभव, अध्ययन और संदर्भों से अर्जित किया जाता है. ज्ञान हमारी बुद्धिमत्ता, समझ और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है. ज्ञानार्जन बैंक कर्मियों को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी, नवीनतम वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में अद्यतित रखता है.

उपरोक्त, तीनों तत्वों को संयुक्त रूप से विकसित कर हम स्वयं को प्रगति, सफलता और संतुष्टि के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं.

संस्कृति निर्माण में ज्ञानार्जन और विकास का महत्व: बैंकिंग संस्थाओं की संस्कृति निर्माण में ज्ञानार्जन और विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. संस्था के अपने मिशन और विज़न पर आगे बढ़ने की दिशा व दशा उसके कर्मचारियों का ज्ञानार्जन ही तय करता है. ज्ञानार्जन और विकास कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से स्थायी और अवकाशी प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और अन्य शिक्षानुभवों के माध्यम से कर्मियों के प्रदर्शन को सुधारता है.

निरंतर बदलाव की प्रक्रिया को सफल बनाने में सहायक: ज्ञानार्जन और विकास बैंकिंग संस्थाओं में नवीनतम परिवर्तनों के साथ आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करता है और निरंतर बदलाव की प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इससे न केवल कार्मिकों का व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि संगठन की संगठनात्मक क्षमता भी मजबूत होती है. आज अद्यतन शिक्षा, नवीनतम तकनीक, वित्तीय उपाय और उद्योग के नियमों के साथ समंजस्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए संगठन अपने कार्मिकों को नवीनतम ज्ञान और उद्योग मानकों के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगठनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है.

अध्ययन और अनुसंधान में ज्ञानार्जन और विकास का महत्व: नए बाजार रुचियों, ग्राहकों की प्राथमिकताओं और उच्चतम अभिकर्षक अभियांत्रिकी की अवधारणाओं का अध्ययन और अनुसंधान करना बहुत महत्वपूर्ण है. यह संगठन को अपने उत्पादों और सेवाओं को अद्यतित रखने और नवीनतम ट्रेंड्स और उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्ञान और सूचना प्राप्त करने में मदद करता है.

बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने में ज्ञानार्जन और विकास का महत्व: बैंकिंग उद्योग में धोखाधड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या है और इससे बैंकों, ग्राहकों और आर्थिक प्रणालियों को बहुत नुकसान होता है. ज्ञानार्जन और विकास द्वारा बैंक कर्मियों को धोखाधड़ी के लिए जागरूक रहने, उन्हें पहचानने और रोकने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाते हैं. ज्ञानार्जन व विकास उन्हें धोखाधड़ी के खिलाफ नवीनतम तकनीकी उत्पादों और सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूक रहने में मदद करता है. इसके अलावा, ज्ञानार्जन उन्हें संगठनात्मक संरचना, नियमों और प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए बदलाव करने में मदद करता है ताकि धोखाधड़ी की संभावना कम हो सके. इस प्रकार, ज्ञानार्जन और विकास बैंकिंग संस्थाओं को उनके कर्मियों को धोखाधड़ी से बचने के लिए तैयार करते हैं और उन्हें धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम में सक्षम बनाते हैं.

व्यावसायिक शिष्टाचार एवं ग्राहक संतुष्टि में ज्ञानार्जन और विकास का महत्व: बैंकिंग में व्यावसायिक शिष्टाचार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. अग्रिम पंक्ति में यह व्यावसायिक संबंधों, संपर्कों और कारोबारी गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद करता है. ज्ञानार्जन और विकास के माध्यम से संवेदनशीलता और विश्वास, संचार-कौशल, सभ्य एवं आदर्शवादी व्यवहार, व्यक्तिगत ध्यान आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान कर अपने कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि की जा सकती है.

निरंतर सीखते रहने वाली संस्था के रूप में पहचान: बैंकिंग क्षेत्र का निरंतर सीखते रहने वाली संस्था बने रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस प्रकार की संस्था को व्यापारिक मानकों के प्रति समर्पित, नवाचारी और प्रगतिशील संस्थान के रूप में पहचाना जा सकता है. यह उच्चतम गुणवत्ता के उत्पादों और सेवाओं की पेशकश कर ग्राहकों के लिए अपूर्व अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है. एक निरंतर सीखते रहने वाली संस्था ज्ञानार्जन और विकास के माध्यम से ही संभव है, जो निम्नलिखित गुणों की अभिव्यक्ति कर सकती है:-

प्रगतिशीलता: यह संस्था नवीनतम तकनीक, वित्तीय उपाय और व्यापारिक उद्योग में आविष्कार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहती है. यह नए विचारों, उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है, जो ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है.

ग्राहक-मार्गदर्शन: एक निरंतर सीखते रहने वाली संस्था अपने ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवा को प्राथमिकता प्रदान करती है. यह ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करती है ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके. इससे संस्था के लिए वफादार ग्राहक आधार बनाने में मदद मिलती है.

कर्मचारी विकास: एक निरंतर सीखते रहने वाली संस्था कर्मचारियों के प्रगतिशील विकास और उनके कौशल को विकसित करने हेतु तत्पर रहती है, जो संगठन की उन्नति और ग्राहक सेवा में मददगार होती हैं.

नैतिकता और संवेदनशीलता: निरंतर ज्ञानार्जन करते रहने वाली संस्था नैतिकता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के पैमानों पर खरी उतरती है और अपने ग्राहकों को एक अद्वितीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है.

प्रशिक्षण प्रणाली में ज्ञानार्जन और विकास: प्रशिक्षण तंत्र नए लीडर के चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है. एक सशक्त लीडर किसी भी टीम के नेतृत्व के लिए आवश्यक होता है. प्रशिक्षण प्रणाली उन्हें आधुनिक कौशल व अद्यतन जानकारी प्रदान करता है. टीम नेतृत्व, संचालन, जोखिम प्रबंधन, संचार कौशल, समस्या निवारण, रणनीति निर्माण आदि क्षेत्रों में उन्हें पारंगत करता है. प्रशिक्षण प्रणाली नए लीडरों को विचारशीलता, नवाचार और संगठनात्मक सोच को संवारने के लिए प्रेरित करता है, जो सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक होती है.

उपसंहार: बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय सुविधाओं को गरीब और अशिक्षित लोगों तक पहुंचाने से समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलती है. बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, अभियांत्रिकी और नवीनतम तकनीकी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती हैं. बैंकिंग क्षेत्र में ज्ञानार्जन और विकास अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आर्थिक सुविधाओं को विस्तारित कर आर्थिक समानता को प्रोत्साहित करने में मदद करता है.

सचिन बंसल
यूनियन लर्निंग अकादमी, बेंगलूरु

कृषि बैंकिंग का बदलता स्वरूप

भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है. कृषि क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) और रोजगार में का एक बड़े हिस्से का योगदान देता है. इस प्रकार यह भारतीय आबादी की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है.

पिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में हर स्तर पर जबरदस्त वृद्धि हुई है. यह क्षेत्र, जो कार्यबल का सबसे बड़ा नियोक्ता है, इने देश के सकल मूल्य वर्धन (जी वी ए) में 18.80% (2021-22) का योगदान दिया. पशुधन, डेयरी और मत्स्यपालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि इस क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख चालक रहे हैं. भारतीय कृषि अब जनसंख्या आधारित नहीं रही अपितु वर्तमान में यह उपभोग आधारित है. भारतीय किसान बहु कुशल हैं और हमारे छोटे खेत बहु-कार्यात्मक हैं. कृषि उत्पादन के कुल मूल्य में मापे जाने पर भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है. हालांकि हम कैलोरी सामग्री के मामले में चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े खाद्य उत्पादक हैं.

इतिहास: औपनिवेशिक शासन ने हमारे उत्पादन को वाणिज्यिक फसलों (चाय, कॉफी, रबड़, कपास आदि) पर केंद्रित रखा, जबकि खाद्य फसलों को उपेक्षा का सामना करना पड़ा. स्वतंत्रता के बाद, कम उत्पादकता, स्थिर खाद्य फसल क्षेत्र और खराब ग्रामीण बुनियादी ढांचे के कारण खाद्य आत्मनिर्भरता को एक प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्य बनाने के कारण खाद्य आयात करने की आवश्यकता थी.

पंच वर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में ज्यादा परिणाम नहीं मिले क्योंकि श्रम गहन छोटे पैमाने के उत्पादन से लेकर बड़े पैमाने पर पूंजी गहन भारी उद्योग पर जोर था. इस प्रकार हमें खाद्य उत्पादन में संकट का सामना करना पड़ा. हरित क्रांति की शुरुआत के बाद शानदार परिणाम सामने आए और हम चावल, गेहूं, दालें, फल और सब्जियों जैसी कई कृषि वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गए. खाद्य पदार्थों के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक में बदलने का श्रेय भारतीय किसानों और भारतीय कृषि इनपुट उद्योग को जाता है.

कृषि के उक्त विकास को आगे बढ़ाने में बैंकों का योगदान सबसे अधिक है. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंक कृषि की मुख्य धारा से और भी ज्यादा गहराई से जुड़ते जा रहे हैं. बैंक हमेशा से ही कृषि आवश्यकताओं के अनुसार नए-नए ऋण उत्पाद ले कर आते रहे हैं, जिससे किसानों की ऋण आवश्यकताएं कम ब्याज दर के साथ पूरी हो सकें. नाबार्ड की किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एकमत से स्वीकार किया गया, किसान के फसल ऋण के लिए जीवन रेखा के समान है. पहले कृषि ऋण योजनाओं का स्वरूप सीमित था, जैसे- फसल ऋण, पशुपालन हेतु ऋण, पंप एवं सिंचाई सुविधा हेतु ऋण, फार्म मशीनीकरण हेतु ऋण आदि. परंतु वर्तमान में आधुनिक किसानों की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार ऋण योजनाएँ भी बदली हैं.

आज का किसान न सिर्फ सुदृढ़ हुआ है बल्कि अब कृषि ने कृषि उद्योग का दर्जा भी हासिल कर लिया है, जिसके द्वारा उन्नत किसान अपने प्रयासों से अच्छी आय प्राप्त कर रहा है तथा अपना जीवन स्तर भी सुधार रहा है.

विभिन्न कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं ऋण प्राप्त कर सकती हैं :

- किसान, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) सहित व्यक्ति.
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर, काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार जिनकी जोत का हिस्सा लघु और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित सीमा के अंदर है.
- स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म और सहकारी समितियां.
- कॉर्पोरेट किसान, स्टार्टअप, कृषि उत्पादक संगठन / कंपनियां (एफपीओ) / (एफपीसी), वैयक्तिक किसानों की कंपनियां.

कृषि बैंकिंग के बदलते स्वरूप के फलस्वरूप नई ऋण योजनाओं का जन्म हुआ है जो कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है:

कृषि के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण: नई, मौजूदा खाद्य और कृषि आधारित प्रोसेसिंग इकाइयां इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं. व्यक्ति, स्वामित्व, साझेदारी फर्म, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और सीमित देयता साझेदारी संस्था इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.

एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस केंद्रों की स्थापना: कृषि स्नातकों और अन्य तकनीकी रूप से योग्य उद्यमियों द्वारा कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इस ऋण का मूल उद्देश्य है. इस योजना के तहत नाबार्ड के माध्यम से अनुदान भी प्राप्त किया जा सकता है.

भंडारण संरचना परियोजनाओं का निर्माण: वैज्ञानिक भंडारण क्षमता अर्थात गोदाम, सूखे वेयरहाउस, शीत भंडारण, कोल्ड चेन,

साइलो और मार्केट यार्ड के निर्माण के लिए यह ऋण योजना बैंकों में उपलब्ध है. व्यक्तिगत किसान, किसानों/उत्पादकों का समूह, पंजीकृत, साझेदारी/स्वामित्व फर्म, कंपनियां और निगम, एनजीओ और एसएचजी, सरकारी स्वायत्त निकाय, सहकारिता, सहकारिता विपणन संघ, राज्य सरकार के विभागों और स्वायत्त संगठन/राज्य के स्वामित्व वाले निगमों जैसे कृषि उत्पाद बाजार समितियों और विपणन बोर्डों, राज्य भंडारण निगमों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों आदि सहित राज्य एजेंसियां, ये सभी इस ऋण का लाभ उठा सकते हैं.

वेयर हाउस रसीद के बदले में वित्त पोषण: किसानों को चलनिधि प्रदान करने के लिए गोदाम/शीत भंडार की रसीद के बदले ऋण उपलब्ध कराया जाता है और यह उन्हें कटाई के समय उनकी उपज की बिक्री की विवशता से बचाता है. बैंकों के मौजूदा/भावी ग्राहक जैसे किसी संस्था के स्वामी/साझेदार संस्थाएँ /कंपनी/ कृषि जिंसों का व्यापार करने वाले व्यक्ति, ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में आढ़तिया अनाज तथा कृषि आधारित प्रोसेसिंग इकाइयाँ जो कृषि जिंसों का कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रही हैं, ये सभी इस ऋण योजना के अंतर्गत ऋण लेने हेतु पात्र होती हैं.

किसानों को अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तपोषण एजेंसियों का वित्तपोषण: सभी व्यक्ति, उद्यमी, संगठन, संस्थान, निगम जैसे कृषि उद्योग निगम, मार्केट यार्ड या मार्केट यार्ड, गोदामों, पंचायतों और कृषि सेवा केंद्रों में अधिकृत लाइसेंसधारी, जो इस प्रकार की गतिविधियों को करने में सक्षम हैं तथा किसानों को कस्टम सेवाएं प्रदान करते हैं, ये सभी इस ऋण योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं.

कृषि भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तपोषण: फार्म हाउस सह आवास इकाइयों सहित विभिन्न फार्म भवन संरचनाओं के निर्माण के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मूल उद्देश्य है. फार्महाउस सह आवासीय इकाई के निर्माण के लिए किसानों के पास किश्तों को चुकाने के लिए पर्याप्त आय सहित अपनी ज़मीन होनी चाहिए.

किसानों को चार पहिया वाहन हेतु ऋण: किसान को कृषि प्रबंधन गतिविधियों में उपयोग के लिए जीप, एसयूवी, स्टेशन वैगन, ग्रामीण परिवहन वाहन आदि सहित कोई भी नया चार पहिया वाहन खरीदने के लिए चार पहिया ऋण का वित्तपोषण किया जा सकता है.

किसानों को आधुनिक नर्सरी एवं हाई टेक कृषि हेतु वित्तपोषण: ग्रीन हाउस/पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक सुरंगों और वॉक-इन सुरंगों, पक्षी-रोधी/ओला-रोधी जालों, प्लास्टिक मल्चिंग, हाइड्रोपोनिक्स के तहत परियोजनाओं, एक्वापोनिक्स के तहत परियोजनाओं, एरोपोनिक्स के तहत परियोजनाओं के लिए भी इस योजना के अंतर्गत ऋण दिया जा सकता है. उत्पादन और फसल के उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) से सब्सिडी प्राप्त करने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध है.

संपीडित बायो गैस प्लांट की स्थापना: वर्तमान परिदृश्य में जब ऊर्जा के अनवीनीकृत साधन जैसे पेट्रोल, डीजल आदि समाप्ति की ओर अग्रसर हैं, ऐसे में ऊर्जा के नवीनीकृत किए जा सकने वाले साधनों जैसे: पानी, हवा, सौर ऊर्जा आदि का महत्व और भी अधिक हो जाता है. बायो गैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा जैविक कचरे को उपयोगी बायो गैस में बदला जाता है. चूंकि इस गैस का उत्पादन जैविक प्रक्रिया द्वारा होता है, अत: इसे जैविक गैस कहा जाता है. मीथेन गैस इसका प्रमुख घटक है. इस प्रकार के गैस प्लांट की स्थापना के लिए ऋण लेने पर सरकार ने अनुदान लाभ का प्रावधान भी रखा है.

कृषि ड्रोन खरीदने के लिए ऋण: कृषि ड्रोन वर्तमान कृषि परिदृश्य में क्रांतिकारी तकनीक है. इसके द्वारा एक उन्नत किसान खेतों की निगरानी के साथ-साथ खेतों में उर्वरकों, दवाओं, कीट नाशकों आदि का भी सफलतापूर्वक छिड़काव कर सकता है.

किसान उत्पादक संगठन/ किसान उत्पादक कंपनी को वित्तपोषण: किसान उत्पादक संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों द्वारा बनाया गया एक समूह है, जिसमें किसान ही किसानों की मदद करते हैं. यह किसानों का एक ऐसा समूह है, जो कृषि उत्पादन कार्यों में लगा हो या कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधि को आगे बढ़ा रहा हो. किसानों को समूह बनाने के बाद कंपनी एक्ट में पंजीयन भी करवाना होता है.

उक्त योजनाएं कृषि बैंकिंग के बदलते हुए आधुनिक स्वरूप को व्यक्त करती हैं. उक्त योजनाएँ कृषि ऋण की पुरानी परंपरागत योजनाओं के साथ ही चलाई जा रही हैं, जिससे उन्नत कृषि तथा परंपरागत कृषि करने वाले, दोनों प्रकार के कृषकों की आवश्यकता पूर्ण होती है तथा भारत की कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और भी ज्यादा सुदृढ़ होती है. अत: हम यह कह सकते हैं कि कृषि बैंकिंग का बदलता स्वरूप विकासात्मक दृष्टिकोण वाला तथा कल्याणकारी है.

नरेंद्र कुमार चौबे
क्षे. का., रायपुर

उद्यमिता विकास - आर्थिक विकास का आधार

"सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है. एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से बदल रही है, जोखिम न लेना ही एकमात्र रणनीति है जिसके विफल होने की गारंटी है." - मार्क ज़ुकरबर्ग

उद्यमी न केवल अपने लिए व्यवसाय बनाते हैं और व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करते हैं, बल्कि रोजगार सृजन, नवाचार और नए बाजारों, उत्पादों और सेवाओं के विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं. आइए देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका की चर्चा करें :

1. **जीवन स्तर में सुधार:** जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक विकास में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उद्यमशीलता के कारण नए उद्योगों की स्थापना होती है जिसके परिणामस्वरूप नए पदों और धन की सृष्टि होती है, जिससे व्यक्तियों और समाज के जीवन स्तर में काफी सुधार होता है. इतना ही नहीं, उद्यमशीलता के कारण लोगों को ऐसे नए उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध होते हैं जो किफायती, अधिक सुरक्षित और जीवन में मूल्य जोड़ने वाले होते हैं. साथ ही, ऐसे आवश्यक नए उत्पाद और सेवाओं का भी निर्माण होता है जिनकी भारी कमी महसूस की जाती है.

2. **आर्थिक स्वतंत्रता:** कड़ी मेहनत और नवाचार के माध्यम से उद्यमिता देश और उद्यमी दोनों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है. यह आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर देश की निर्भरता को कम करती है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है. निर्मित वस्तुओं और सेवाओं को विदेशी बाजारों में भी निर्यात किया जा सकता है, जिससे देश के व्यापार का विस्तार होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, विदेशी मुद्रा का अंतर्प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है. भारत में उद्यमिता और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' पहल से घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है, आयात पर निर्भरता कम हुई है और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला है. स्टार्टअप्स या नव-उद्यमों के पास उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, उद्योगों की कार्यप्रणाली को बदलने और अभूतपूर्व उत्पादों या सेवाओं को पेश करने के लिए आवश्यक लचीलापन और तत्परता होती है.

3. **नई फर्मों और व्यवसायों के लाभ:** नए उद्यमी बाजार की जरूरतों की पहचान करते हैं और अपना उद्यम शुरू करने के लिए अपने नए उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से समाधान विकसित करते हैं. नई फर्मों और व्यवसायों को शुरू करके, उद्यमी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में न केवल सहायता प्रदान करते हैं बल्कि उसे अधिक गतिशील और वैविध्यपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उद्यमिता जोखिम को बढ़ावा देती है, जिससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलता है. फलस्वरूप नए और बेहतर उत्पादों और सेवाओं का विकास होता है, जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं.

4. **रोजगार सृजन:** उद्यमिता रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण चालक है. नए व्यवसायों को चलाने और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में नए रोजगार उत्पन्न होते हैं. उद्यमिता नवाचार और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देती है, जो अन्य उद्यमियों और निवेशों को प्रेरित करती है, जिसके परिणामस्वरूप विनिर्माण और उत्पादन से लेकर सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक उद्योगों की एक विस्तृत शृंखला में नई नौकरियां उत्पन्न होती हैं.

5. **पूंजी निर्माण:** पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें नए व्यापारिक उपक्रमों को निधि उपलब्ध कराने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसाधनों, जैसे बचत और निवेश को एकत्रित किया जाता है. उद्यमिता निवेश को आकर्षित करके पूंजी निर्माण के इस कार्य में सहायक होती है. इसके अलावा, नए व्यवसायों का निर्माण और मौजूदा व्यवसायों का विकास अधिक वैविध्यपूर्ण और गतिशील अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है, जो पूंजी निर्माण में सहायक होता है और निवेश के नए अवसरों की एक विस्तृत शृंखला के द्वार खोलता है. जैसे-जैसे उद्यम समृद्ध होते हैं, उद्यमी अपने मुनाफे का पुनर्निवेश करते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं. वर्ल्ड ईकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि उद्यमिता घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित कर सकती है, जिससे पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास हो सकता है. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार नए व्यवसाय वेंचर पूंजी और एंजेल निवेश को आकर्षित करके पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

6. **गरीबी उन्मूलन:** उद्यमिता में रोजगार पैदा करके और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की क्षमता होती है. उद्यमिता स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास में भी योगदान देती है और समग्र जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) इस बात पर जोर देता है कि गरीबी कम करने और सतत विकास के लिए उद्यमिता महत्वपूर्ण है. बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक

की माइक्रोफाइनेंस पहल और उद्यमिता के लिए समर्थन ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है. उद्यमशील व्यक्ति न केवल स्वत: अपने जीवन स्तर को सुधारता है, बल्कि अपने उद्योग में अन्य लोगों को काम देकर उन्हें भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है. देश के बाज़ार के विकेंद्रीकरण में भी उद्यमशीलता का बड़ा योगदान होता है. देश की पूंजी का किन्हीं व्यापारिक घरानों तक सीमित रहना सामाजिक और आर्थिक असमानता को जन्म देता है जो जनता के असंतोष का कारण हो सकता है. बड़ी संख्या में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से राष्ट्र की पूंजी और संसाधनों का विकेंद्रीकरण होता है जिससे क्षेत्रीय असमानता को भी दूर किया जा सकता है. वंचित क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करके सरकारें समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं और क्षेत्रीय असमानताओं को पाट सकती हैं. स्टार्टअप इनक्यूबेटर, कौशल विकास कार्यक्रम और विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों और क्षेत्रों को लक्षित करने वाली वित्तीय सहायता योजनाएं जैसी पहल अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग कर सकती हैं, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है. 2022 में, भारतीय स्टार्टअप्स ने रिकॉर्ड 39 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई. इस निवेश का उपयोग नए व्यवसाय और नौकरियां पैदा करने के लिए किया जा रहा है, जिससे आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिल रही है.

7. **सामुदायिक विकास:** उद्यमिता आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करती है और समग्र रूप से जीवन स्तर में सुधार करती है. इस प्रकार, उद्यमी अपने समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कम सेवा वाले क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के विकास के द्वारा उनके जीवन स्तर में सुधार लाते हैं. उद्यमियों के कार्य मजबूत और अधिक सक्रिय समुदायों के निर्माण तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं. जर्नल ऑफ बिजनेस वेंचरिंग में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि उद्यमिता नौकरियां पैदा करके, आय के स्तर में वृद्धि और सामाजिक कल्याण में सुधार करके स्थानीय सामुदायिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालती है. सामाजिक उद्यमिता पहल, जैसे कि माइक्रोक्रेडिट कार्यक्रम और समुदाय-आधारित उद्यमों ने सामुदायिक विकास संकेतकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण सफलता दिखाई है.

8. **संसाधनों का इष्टतम उपयोग:** उद्यमिता बाजार के अवसरों की पहचान करने और सबसे प्रभावी तरीके से संसाधनों को आबंटित करने में मदद करती है. उपलब्ध संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाले नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जर्नल ऑफ बिजनेस वेंचरिंग में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि उद्यमी संसाधन आबंटन में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जिससे उपलब्ध संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग होता है.

9. **सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि:** उद्यमिता सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) में वृद्धि करके आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जीडीपी किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है, जबकि पीसीआई प्रति व्यक्ति औसत आय की गणना करता है. जीडीपी में वृद्धि से पीसीआई में वृद्धि हो सकती है. उद्यमिता नए व्यवसायों और उद्योगों का निर्माण करके जीडीपी में योगदान करती है, जिससे रोजगार सृजन, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और उच्च कर राजस्व प्राप्त होता है.

भारत में भी उद्यमिता का एक लंबा इतिहास है. आज भारत में जो सफल उद्योग या औद्योगिक संस्थान हैं, उनकी शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर हुई थी. धीरुभाई अंबानी की रिलायंस, अजीम प्रेमजी की विप्रो, नारायण मूर्ति की इन्फोसिस, टाटा समूह की टाटा कंपनी, शिव नाडर की एचसीएल, लक्ष्मी मित्तल की अर्सेनलमित्तल, सुनील मित्तल की भारती एंटरप्राइज़, किरण मजूमदार शाह की बायोटेक लिमिटेड, विजय शेखर शर्मा की पेटीएम, कुणाल बहल और रोहित बंसल की स्नैपडील इत्यादि; इन सब ने एक छोटे उद्यम के रूप में अपनी शुरुआत की थी, जो आगे चलकर बड़ी कंपनियाँ बनी और इन्होंने देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया.

उद्यमी वो जो अपनी ताकतों पर विश्वास करता है
निर्णयों के साथ हर चरण को तर्क से भरता है
नए द्वार खोलकर सपनों को हक़ीक़त में बदलता है
उद्यमी वो जो जीवन को नए रंगों से भरता है

उद्यमिता वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है. उद्यमिता वह जगह है जहां सम्भावनाएं पैदा होती हैं और सामान्य से असामान्य का निर्माण कराती है. सफलता का मापदंड केवल धन अर्जन नहीं होता है, बल्कि यह स्वतंत्रता, संतुष्टि और सामर्थ्य का प्रतीक भी होता है. प्रत्येक मानव में अनंत संभावनाएं होती हैं और इन्हें बाहर लाने का कार्य उद्यमिता के माध्यम से होता है. सीमाओं से परे सोचने और कार्योन्मुख होने की शक्ति उद्यमिता से ही प्राप्त होती है जिसका लाभ व्यक्ति, राष्ट्र और समस्त विश्व को होता है. इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसका प्रभाव रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक विकास, संसाधन अनुकूलन और समग्र आर्थिक समृद्धि पर पड़ता है. अत: उद्यमिता का विकास किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार होता है.

देवकांत पवार
अंचल कार्यालय, हैदराबाद

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बैंकिंग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, कृत्रिम रुप से विकसित बुद्धिमता है, ताकि मशीनों को बुद्धिमत्ता के प्रसंग में, मनुष्यों की तरह व्यवहार करने के लिए बनाया जा सके. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कहते हैं, की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई. जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें एआई का जनक माना जाता है. यह कंप्यूटर को एक इंसान की तरह रूप में सोचने, समझने और कार्य करने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया है.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर विज्ञान में हो रही प्रगतियों में से एक है, इसलिए इसे कंप्यूटर विज्ञान की ही एक प्रशाखा के रूप में देखा जाता है. एक मशीन तभी कार्य करती है, जब उसे निर्देश दिया जाता है, लेकिन अगर उसी मशीन में मानव जैसी सोच और विश्लेषण, समस्या को सुलझाने की क्षमता, आवाज पहचानने की क्षमता आदि को स्थापित कर दिया जाए, तो वही मशीन स्मार्ट मशीन बन जाती है.

अत: मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता की विभिन्न विशेषताओं को विकसित करने पर ध्यान देने की दिशा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित किया जा सकता है. इन विशेषताओं को विभिन्न डेटा, बुद्धिमत्तापूर्ण एल्गोरिथम के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, जिन्हें इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है. वर्तमान में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तमाम तरह के उपकरणों से घिरे हुए हैं, उदाहरण के लिए एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, मोबाइल, बायोसेंसर, वीडियो गेम आदि.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बैंकिंग : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक ऐसा क्षेत्र बनकर उभरा है, जो कंप्यूटर विज्ञान और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए कंप्यूटर सिस्टम को बुद्धिमत्ता के साथ समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है. आज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभिन्न क्षेत्रों में लागू हो रही है, जिसमें बैंकिंग भी शामिल है. बैंकिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है, जिसमें उपलब्ध संसाधनों को अधिक समय और दूसरे संसाधनों की आवश्यकता के बिना वित्तीय विश्लेषण किया जा सके.

यह बैंकों को, अपने ग्राहकों को एक बेहतर और तेज सेवा प्रदान करने में मदद करता है. इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्लेषण के अनुभव से नतीजे देता है, जिससे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियों को अधिक उपयोगी निवेश के फैसले लेने में मदद मिलती है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से, बैंकिंग कंपनियों को विभिन्न वित्तीय मॉडल तैयार करने में मदद मिलती है, जो उन्हें बेहतर निवेश फैसले लेने में भी मदद करती है.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ताकत बैंकिंग उद्योग के लिए अधिक समझदार निर्णय लेने में मदद करती है. यह सुझाव देने की क्षमता रखता है, उदाहरण के लिए, किस निवेश का प्रस्ताव सबसे अधिक मुनाफे देगा या किस निवेश से आपको अधिक नुकसान होने की संभावना है.

बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता को कई लेंसों से देखा जा सकता है, विशेष रूप से बैंकिंग के परिचालन परिदृश्य में इसके निहितार्थ और अनुप्रयोगों को, जैसे रोबोटिक्स, कंप्यूटर विज़न, भाषा, वर्चुअल एजेंट और मशीन लर्निंग (डीप लर्निंग सहित) जो इस क्षेत्र में हाल ही में हुई कई प्रगतियों को रेखांकित करता है.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से बैंकिंग में परिवर्तन की लहर

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तेजी से प्रगति हो रही है :

- अग्रणी बैंक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशालाओं और इन्क्यूबेटरों (स्टार्टअप) में निवेश करते हुए आक्रामक रूप से मुख्य एआई अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं.
- ग्राहक अनुभव के मोर्चे पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित बैंकिंग बॉट का उपयोग किया जा रहा है.
- कई बैंक स्वनिर्धारित इन-हाउस समाधानों की ओर बढ़ रहे हैं जो जटिल निर्णयों में परिष्कृत ऑन्कोलॉजी, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, मशीन लर्निंग, पैटर्न पहचान और संभाव्य तर्क एल्गोरिथम का उपयोग कुशल कर्मचारियों और रोबोटों की सहायता के लिए कर रहे हैं.

बैंक आज लागत कम करने, मार्जिन पूरा करने और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इसे सक्षम करने के लिए, बैंकों ने दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित प्रौद्योगिकियों को अपनाना शुरू कर दिया है. मोबाइल प्रौद्योगिकी की शुरुआत, डेटा उपलब्धता और ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर का विस्फोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है. ऐप-संचालित दुनिया की बदलती गतिशीलता बैंकिंग क्षेत्र को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने और इसे व्यावसायिक अनिवार्यताओं के साथ मजबूती से एकीकृत करने में सक्षम बना रही है. डिजिटल व्यक्तिगत सहायकों और चैटबॉट्स ने ग्राहक अनुभव और संचार को बदल दिया है. वे नियमित दैनिक कार्यों को मुक्त करने और ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत अनुभव सुनिश्चित करने में शक्तिशाली समर्थक हैं.

बैंकिंग ग्राहक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग : स्वचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता- ग्राहक सेवा को मजबूत गति प्रदान कर रही है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संबंधित सुविधाएं उपयोगकर्ता के व्यवहार और आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाओं और ऑफ़र प्रदान करती हैं. संज्ञानात्मक मशीन को उपयोगकर्ताओं के डेटा का विश्लेषण करके सलाह देने और संचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वैयक्तिकृत धन नियोजन में क्रांति ला दी गई है. नियमित और बुनियादी संचालन यानी खाता खोलना या बंद करना, धनराशि अंतरित करना, चैटबॉट्स की मदद से सक्षम किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक नई कार खरीदना चाहता है, तो ऐप वर्तमान व्यय और आय के आधार पर प्रस्तावित परिव्यय और ऋण अनुमोदन सीमा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा. चैटबॉट्स को भी ग्राहक सेवा एजेंटों के रूप में कार्य करने

और पूरे दिन लगातार ग्राहकों की सेवा करने के लिए 'नियुक्त' किया जा सकता है.

1. धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन : ऑनलाइन धोखाधड़ी व्यवसायों के लिए बड़े पैमाने पर चिंता का विषय है, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण कर रहे हैं. इंटरनेट पैमाने पर जोखिम प्रबंधन को मैन्युअल रूप से या परंपरागत सूचना प्रणालियों का उपयोग करके प्रबंधित नहीं किया जा सकता है. अधिकांश बैंक वास्तविक समय में सभी लेनदेन की जांच करने के लिए मशीन और पूर्वानुमानित विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं. इस दिशा में मशीन लर्निंग, बैंक में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. जोखिम को रोकने के लिए प्राथमिक उपयोगों में वास्तविक समय में संदिग्ध पैटर्न के लेनदेन को स्कैन करके धोखाधड़ी को कम करना, ग्राहकों की साख को मापना और सही अनुशंसाओं के साथ जोखिम विश्लेषकों को सक्षम करना शामिल है.

2. व्यापार और प्रतिभूतियाँ : रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) फ्रंट ऑफिस में सक्षम ट्रेडों के साथ बैक ऑफिस में जानकारी के सामंजस्य और सत्यापन के माध्यम से सुरक्षा निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्रक्रिया के माध्यम से धन्यवाद पत्र, नेफ्ट समाधान, खाता फ्रीज एवं बॉण्डों का संचालन जैसी सुविधाएँ मैन्युअल प्रक्रिया की तुलना में सुगम और कम समय में पूरी कर सकते है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यापार संवर्धन, पुष्टिकरण और निपटान की समग्र प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है. बैंकों ने ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव और विदेशी मुद्रा लेनदेन के मामले में सामंजस्य के लिए और नकदी एवं चलनिधि प्रबंधन में लक्ष्य संतुलन तथा अनुमानित पूलिंग के लिए सक्रिय रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना शुरू कर दिया है.

3. क्रेडिट आकलन : ऋण देना बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के लगभग सभी हिस्सों को प्रभावित करता है. मूल रूप से उधार को एक बड़ी डेटा समस्या के रूप में देखा जाता है और उसमें महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, ऋण मांगने वाले व्यक्तियों या व्यवसायों की साख का सत्यापन. उधारकर्ता के बारे में जितना अधिक डेटा उपलब्ध होगा, आप उनकी साख का उतना ही बेहतर आकलन कर सकते हैं. आमतौर पर, ऋण की राशि, संपार्श्विक के मूल्य और भविष्य की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए आकलन से जुड़ी होती है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता यह है कि यह एक सुसंगत निर्णय लेने के लिए इन सभी डेटा स्रोतों का एक साथ विश्लेषण कर सकती है.

4. श्रेणी प्रबंधन : बैंक अपने निवेशकों और ग्राहकों की ओर से बेहतर, रियल टाइम निवेश निर्णय लेने के लिए मशीन लर्निंग पर भरोसा कर रहे हैं. डेटा उनके यह निर्णय लेने का एक अभिन्न अंग बन जाता है. यह उन्हें परिसंपत्तियों की अधिक विविध श्रेणी पर विचार करने हेतु अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, विभिन्न रणनीतियों के साथ प्रयोग करने में सक्षम बनाता है.

बैंक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग-आधारित प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो ग्राहकों की निवेश सीमा, पैटर्न और प्राथमिकताओं के आधार पर अनुकूलित पोर्टफोलियो प्रोफाइल बनाने में सहयोग करते हैं.

5. ग्राहक सहायता और हेल्पडेस्क : ह्यूमनॉइड चैटबॉट इंटरफेस का उपयोग दक्षता बढ़ाने और ग्राहक सहायता के लिए किया जा सकता है, जिसकी मदद से हम ग्राहकों को 24X7 सेवाएँ मुहैया करा सकते हैं.

6. बैक-ऑफिस प्रोसेसिंग में डिजिटलीकरण और स्वचालन : ओसीआर का उपयोग करके दस्तावेज़ के डेटा को कैप्चर करना और फिर उसी डेटा से निष्कर्ष उत्पन्न करने के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना, बैक-ऑफिस प्रोसेसिंग के समय को काफी कम कर सकता है.

7. एटीएम : धोखाधड़ी/अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए डीप लर्निंग एवं छवि/चेहरे की पहचान जैसी उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों का उपयोग करके, जालसाज़ की पड़ताल की जा सकती है.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बैंकिंग में लागू करने में चुनौतियाँ : सबसे बड़ी चुनौती प्रशिक्षित मानव संसाधन (सही डेटा विज्ञान कौशल वाले व्यक्तियों) की कमी है. मौजूदा कार्यबल नवीनतम उपकरणों और अनुप्रयोगों से परिचित नहीं है. बैंक को कुशल डेटा वैज्ञानिकों को विकसित करने के साथ-साथ, डेटा विज्ञान कौशल पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ काम करने की आवश्यकता है.

दूसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता मनुष्य में आलस्य का कारण बन सकती है. अलग-अलग बीमारियों को न्यौता देने के साथ-साथ आपके काम करने की एवं सोचने की क्षमता भी वक़्त के साथ कम होती जाती है. इसलिए किसी को इन उपायों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए. कृत्रिम बुद्धिमत्ता जब उचित तरीके से उपयोग की जाती है, तो इसके अच्छे परिणाम आते हैं, लेकिन अगर मशीन को दिए गए निर्देश नकारात्मक या विध्वंसक हैं, तो इससे समुदाय को नुकसान हो सकता है.

निष्कर्ष : इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी उन्नति, मानव जाति के विकास में एक सहायक रणनीति साबित हो रही है. यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उन्नत स्तर पर विकसित किया जाता है, तो उससे काफी अधिक तकनीकी सहायता मिलेगी. रोबोटिक्स, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक विकासशील प्रशाखा है, इसका उच्च योगदान हो सकता है. इसलिए कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बैंकिंग को लाभान्वित करने की दिशा में है, यदि उसका उपयोग उचित और सकारात्मक तरीके से किया जाए.

मनु
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

अमृत काल - विकासशील से विकसित देश का सफर

नवम्बर 2019 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत के पास अपनी स्थिति को बदलकर विकसित देशों की कतार में शामिल होने के लिए सिर्फ एक दशक का वक्त है. इसके लिए भारत को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी. अगर वह इस मोर्चे पर विफल हुआ तो देश की युवा आबादी का लाभ नुकसान में बदल जाएगा. रिपोर्ट में कहा गया था कि नीति-निर्माताओं को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि भारत के पास विकसित देश का सेहरा पहनने के लिए बहुत थोड़ा समय है, जिसमें यह अपना दर्जा बढ़ा सकता है या फिर हमेशा के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में अटका रहेगा. साथ ही डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में निवेश करना चाहिए.

विकसित भारत का सपना : विकसित भारत का सपना एक व्यापक और गहरा विषय है. यह सपना व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक विकासशील भारत के रूप में व्यक्त होता है. इस सपने का उद्भव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ था और स्वतंत्रता के बाद से इसे प्राप्त करने के लिए प्रयासों और सरकारी योजनाओं का हिस्सा बना है.

विकसित भारत के सपने को पूरी तरह से प्राप्त करने का सफर संघर्षपूर्ण है असंभव नहीं. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अभाव, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, जनसंख्या वृद्धि आदि कई समस्याएं हैं जो इस सपने को प्राप्त करने में बाधाएं पैदा करती हैं. विकसित भारत के सपने के लिए उच्चतम शिक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी अद्यतन, ग्रामीण विकास, गरीबी के खिलाफ लड़ाई, बाल संरक्षण, सामाजिक न्याय, औद्योगिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आदि कई क्षेत्रों में कार्य किया जाना चाहिए.

यह महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. समय के साथ, भारतीय समाज में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं और यह सपने को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी कम करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने, जल संसाधन का बेहतर उपयोग करने आदि के क्षेत्रों में प्रगति दिख रही है.

अब तक हम कितने विकसित हैं: अपने 75 साल के इतिहास में, भारत ने अपार प्रगति की है और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया है. भारत की आज़ादी के बाद, देश ने स्वतंत्रता के माध्यम से अनेकों क्षेत्रों में विकास के साथ-साथ गहनता दिखाई है. इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इस्रो) है, जो देश को गर्व के साथ विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष मिशनों में सफलता दिलाने में सक्षम हुआ है. इस्रो ने चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, और गगनयान मिशन जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से विश्व में अपनी पहचान बनाई है. इसके अलावा, भारत ने जीपीएस प्रणाली, वैज्ञानिक उपग्रहों, उपग्रह-आधारित संचार और मौसम समीक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अद्भुत प्रगति की है. देश ने आईआईटी और नैनोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है. भारतीय वैज्ञानिकों ने विश्व में अपनी पहचान बनाई है और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है. इसके साथ ही, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग ने भी बहुत उपलब्धियों को हासिल किया है, जिसकी वैश्विक बाज़ार में अपनी अनन्य प्रतिष्ठा है.

भारतीय अर्थव्यवस्था भी इस 75 साल की अवधि में विशेष रूप से विकसित हुई है. देश ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गति प्राप्त की है और गरीबी के स्तर को कम करने का प्रयास किया है. भारत ने भूतपूर्व तथा समकालीन राष्ट्रीय निर्माण परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनमें बांध, पुल, सड़क, रेलवे, विमानतल और नगर निर्माण शामिल हैं.

भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने में शिक्षा की भूमिका: शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास और प्रगति की मुख्य आधारशिला होती है. भारत में शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है, लेकिन यह दु:खद है कि भारत में एक तिहाई जनसंख्या अब भी

अनपढ़ है. इस मुद्दे को समझने के लिए हमें भारतीय शिक्षा प्रणाली, कारणों और संभावित समाधानों पर विचार करना आवश्यक है.

भारतीय शिक्षा प्रणाली कई समस्याओं का सामना कर रही है. सबसे पहले शिक्षा असमानताओं से प्रभावित होती है. ग्रामीण क्षेत्रों और उपनगरों में शिक्षा की आपूर्ति में कमी होती है और इसलिए लोगों को शिक्षा के लिए दूर यात्रा करनी पड़ती है. दूसरे, शिक्षा की गुणवत्ता में भी अंतर होता है. शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थानीय संस्थानों का संचालन अच्छा होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अस्तव्यस्त और अपूर्ण होता है.

शिक्षा में असमानता का एक और कारण आर्थिक संकट है. कई परिवारों के लिए शिक्षा की लागत अब भी असहज होती है और इसलिए वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में समर्थ नहीं होते हैं. विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें अक्सर पुरुषों की तुलना में शिक्षा के कम अवसर पर होते है.

इसके अलावा, शिक्षा के महत्व को जनसाधारण के बीच बढ़ावा देना भी आवश्यक है. सामुदायिक संगठन, गैर सरकारी संगठन और व्यक्तिगत अभियांत्रिकी/प्रयासों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. साथ ही, लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाने और शिक्षा के समर्थन में उनके साथ काम करना चाहिए.

भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने में तकनीक की भूमिका : भारत में तकनीकी प्रगति बहुत महत्वपूर्ण है और इसका योगदान देश के विकास में महत्वपूर्ण होगा. भारत विश्व में तकनीकी क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी अग्रणी स्थिति बनाने के लिए प्रयासरत है. यहां कुछ मुख्य क्षेत्र दिए जा रहे हैं जिनमें भारत तकनीकी में अपनी पहचान बना रहा है:

1. **सूचना प्रौद्योगिकी:** भारत दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है. देश में कई आईटी कंपनियां, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आउटसोर्सिंग सेवाएं मौजूद हैं. भारतीय इंजीनियरिंग और आईटी पेशेवरों की क्षमता, आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग को नई ऊंचाईयों तक ले जा रही है.

2. **रचनात्मक उद्योग:** भारत रचनात्मक उद्योग क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित हो रहा है. यहां आधुनिक डिजाइन और विकास कार्यालय, मॉडलिंग और टेक्नोलॉजी के केंद्र, तकनीकी सलाहकार और उद्योगों के लिए इंजीनियरिंग और निर्माण के तत्व हैं. रचनात्मक उद्योग के माध्यम से, भारत में अद्यतित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अपार निर्माण गतिविधियों को संभव बनाने में सहायता मिलती है.

3. **बायोटेक्नोलॉजी:** भारत बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है. देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, औषधीय उत्पादों के विकास, जैव पदार्थों के उत्पादन और जैव प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में कई प्रमुख केंद्र स्थापित हैं.

4. **अंतरिक्ष अनुसंधान:** भारत अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति कर रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इस्रो) ने मंगल यान मिशन, चंद्रयान मिशन, गगनयान मिशन और आदित्य मिशन जैसे महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है. इससे भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में विश्वस्तरीय मान्यता प्राप्त हुई है.

भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की भूमिका : भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो देश के विकास में बड़ी बाधा हो सकती है. यहां कुछ मुख्य समस्याओं पर चर्चा की गई है जो भारत को विकसित होने के मार्ग में बाधा पहुंचा सकती हैं:

1. **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं:** भारत में अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे की आय वाले हैं और उन्हें उच्च-गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. इसके परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर व मातृमृत्यु दर बढ़ी हुई हैं तथा एचआईवी/एड्स और टीबी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है.

2. **जनसंख्या वृद्धि:** जनसंख्या के बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है. अधिकांश लोग अब भी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं.

3. **बाधाएं प्रभावित करने के लिए कुशलतापूर्वक मार्गदर्शन की कमी:** भारत में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें उच्च गुणवत्ता और योग्यता सुनिश्चित करते हुए लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है. असंतुलित विकास, कटौती और कुशलतापूर्वक मार्गदर्शन की कमी के कारण उच्च-तकनीकी स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती हैं.

4. **अवसंरचना की कमी:** भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त अवसंरचना की कमी है. कई गांवों और छोटे शहरों में अस्पतालों, डॉक्टरों, और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, जिससे लोग उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूरी की मुश्किलों का सामना करते हैं.

5. **लोगों में जागरूकता की कमी:** भारत में अधिकांश लोगों में स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, पोषण और हाइजीन के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी होती है. जनसंख्या के बढ़ने के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने की जरूरत है.

विवेक भानुदास सावंत
क्षे.का., पुणे मेट्रो

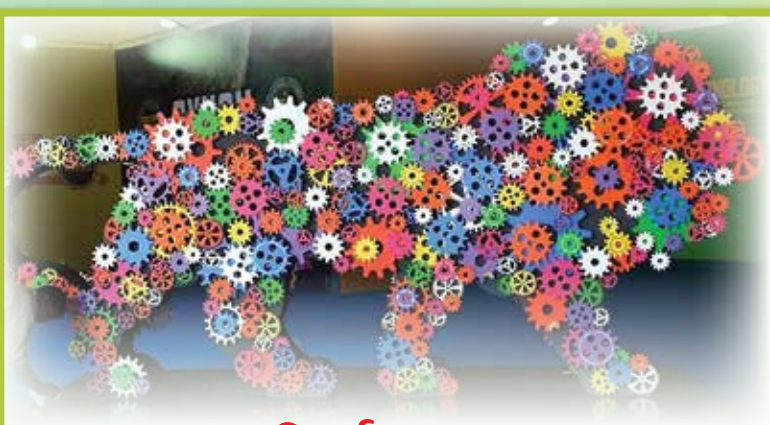

आत्मनिर्भरता पहल

एक देश का सबसे बड़ा गुण होता है आत्मनिर्भरता. एक आत्मनिर्भर देश अपनी जनता और दूसरे देशों का सहारा बन सकता है. इसी दिशा में 12 मई, 2020 को भारत सरकार द्वारा "आत्मनिर्भर भारत अभियान" की परिकल्पना की गई थी. यह पहल कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता, लचीलेपन और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना था. आत्मनिर्भरता अभियान का उद्देश्य न केवल भारत की आवश्यकताओं को पूरा करना है बल्कि निर्यात के लिए भी रणनीति तैयार करना है.

सच ही कहा गया है 'आपदा को अवसर में बदली जा सकता है', और हमने इसकी पहल 2020 में कर दी. इतिहास में हमारे भारत देश को "विश्वगुरु" एवं "सोने की चिड़िया" जैसे अलंकारों से संबोधित किया गया है. हमारे देश पर कई आक्रमण और हुए जिससे हमारे देश का आर्थिक बल तो कम हुआ ही साथ ही जनता की मानसिकता को भी गहरा आघात पहुंचा. अब समय आ गया है कि हम विश्व में अपना गरिमामय स्थान बनाएं. यही वजह है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद इस तरह की पहल की गयी.

आत्मनिर्भर भारत का सपना मुख्यत: पांच तत्वों पर निर्भर करता हैं. वे इस प्रकार हैं -

- **अर्थव्यवस्था:** अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं लाती बल्कि क्वांटम छलांग लगाती है.
- **आधारभूत संरचना:** आधारभूत संरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बनेगी.
- **प्रणाली:** एक ऐसी प्रणाली जो अब अतीत के नियमों और रीति-रिवाजों पर आधारित नहीं है बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली है. इस प्रणाली को प्रौद्योगिकी आधारित बनाने की आवश्यकता है.
- **जीवंत जनसांख्यिकी:** विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र. जीवंत जनसांख्यिकी हमारी ताकत है. यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के हमारे प्रयासों की ऊर्जा का स्रोत है.
- **माँग:** हमारी अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का चक्र एक परिसंपत्ति है. हमें इसका भरपूर उपयोग करना है.

आत्मनिर्भर भारत योजना

आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार द्वारा की गई विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. **आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज:**

12 मई 2020 को, भारत में COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की गई जो भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है. पैकेज ने महामारी से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत और सहायता प्रदान की. पैकेज में चलनिधि प्रवाह, क्रेडिट गारंटी, कर राहत और विशिष्ट उद्योगों के लिए समर्थन जैसे उपाय शामिल थे.

2. **वोकल फॉर लोकल:**

इस पहल में स्थानीय उत्पादों और "मेड इन इंडिया" ब्रांड को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर उत्पादित सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और घरेलू विनिर्माण और उद्यमिता को बढ़ावा देना है. सरकार ने घरेलू उद्योगों के फलने-फूलने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की मांग की.

3. **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं :**

सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 क्षेत्रों को कवर करते हुए पीएलआई योजनाएं शुरू की. इसने ₹45,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया है. इससे जीडीपी में इन क्षेत्रों का योगदान बढ़ेगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और नौकरियों का भी सृजन होगा.

4. **आधारभूत संरचना विकास:**

यह पहल देश भर में आधारभूत संरचना के विकास को बढ़ाने पर केंद्रित है, विशेष रूप से सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में. सरकार ने लॉजिस्टिक्स में सुधार और परिवहन लागत को कम करने के उद्देश्य से कई परियोजनाओं और सुधारों की घोषणा की.

5. **व्यापार करने में आसानी:**

सरकार ने नियामक सुधारों को लागू करके, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और नौकरशाही बाधाओं को कम करके, भारत को विश्व पटल पर एक देश के रूप में प्रस्तुत किया है जो व्यापार एवं व्यापारी दोनों को सहयोग देता है. इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित

करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना है. व्यापार करने में आसानी के मामले में भारत की रैंक 2018-22 के दौरान 14 वें स्थान से सुधर कर 2023-27 में 10 वीं हो गई है.

6. नवाचार और अनुसंधान:

आत्मनिर्भर भारत पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना है. सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप और नवाचार-संचालित उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित किया है.

7. विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाना:

एफडीआई तीव्र आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करता है. इसलिए भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ा दी है. उदाहरण के लिए रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी, सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत 74% एफडीआई और सरकार की मंजूरी के माध्यम से 100% की अनुमति दी.

8. सीमा शुल्क में वृद्धि:

सरकार आयात को हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ा रही है और इस तरह भारत में स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है. इस तरह स्थानीय उत्पाद आयातित उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे.

9. विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाएँ:

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न योजनाएं कुछ इस प्रकार हैं :- आयुष्मान भारत (दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना), राष्ट्रीय आयुष मिशन (लागत प्रभावी आयुष सेवा के लिए), पीएमएफएमई योजना (क्रेडिट लिंक्ड के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना का समर्थन करने के लिए सब्सिडी), सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम विकसित करने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था), भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एनएबीएफआईडी की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन (आधुनिक/प्रौद्योगिकी संचालित शहरी नियोजन के माध्यम से 100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है), पीएम आवास योजना, शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि, उड़ान योजना (हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार का लक्ष्य 2024 तक 100 हवाई अड्डों को विकसित करना है) मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी), फेम, 'देखो अपना देश' पहल, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम (पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीमावर्ती गांवों में), यूनिटी मॉल (राज्य की राजधानियों या प्रमुख पर्यटन केंद्रों में स्थापित किए जाएंगे), मित्र पार्क, भारतमाला परियोजना, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना, सागर माला कार्यक्रम (बंदरगाह आधारित विकास और रसद-गहन उद्योगों के विकास की दृष्टि के साथ), जेएएम ट्रिनिटी, डिजिटल इंडिया पहल (सरकार ने एक खुली एपीआई नीति अनिवार्य की है, जिसे इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है.), गिफ्ट-आईएफएससी, आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र, प्रधानमंत्री जी-वैन योजना, किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) योजना, संशोधित रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के माध्यम से स्वदेशी बाजार से पूंजीगत सामान प्राप्त करना, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों की शुरूआत (आईडीईएक्स) योजना, एमएसएमई के साथ भारतीय उद्योग द्वारा 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए 'सृजन' जैसे स्वदेशीकरण पोर्टल का शुभारंभ, आयुध निर्माणी बोर्ड का सात नई रक्षा कंपनियों में पुनर्गठन और कई अन्य.

निष्कर्ष : उपरोक्त चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र को नवाचार के पथ पर चलाने और एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कई पहल की हैं. ये पहल हमारी अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, सिस्टम, मांग और जनसांख्यिकी (आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ) पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2024 के लिए विकासोन्मुख बजट, "पूंजीगत व्यय, ग्रामीण और कृषि विकास और स्वच्छ ऊर्जा के पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित", भारत की आत्मनिर्भर देश बनने की आकांक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. इसके अलावा, यह नवाचार से व्यावसायीकरण तक के कदम के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और उद्योग को विभिन्न वित्तीय रियायतें प्रदान करता है. इन सभी प्रयासों से देश जल्द ही वैश्विक नवाचार और ज्ञान केंद्र बन जाएगा.

इसके अलावा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भर भारत पहल एक सतत प्रक्रिया है और सरकार को अपने उद्देश्यों के अनुरूप नीतियों और सुधारों को लागू करना जारी रखना चाहिए. मजबूत सुधारों ओर योजनाओं से ही भारत आर्थिक लचीलेपन को मजबूत, आयात पर निर्भरता कम और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर रहेगा और आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकेगा.

आशीष बंसल
यूनियन लर्निंग अकादमी, गुरुग्राम

विकास पथ पर नारी का योगदान

एक देश के विकास को प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता की दर, इत्यादि द्वारा मापा जाता है.

किसी भी देश के लिए विकास का अर्थ है उसके सभी नागरिकों, संसाधनों, संरचनाओं में एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध, प्रगतिशील परिवर्तन का होना. सरल अर्थों में विकास को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है. जैसे कि आर्थिक, सांस्कृतिक, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के स्थायित्व व किसी देश का कुशल प्रबंधन व संचालन आदि मुद्दे में उत्तरोत्तर विकास ही एक बहुमुखी विकास को परिभाषित करता है, क्योंकि केवल आर्थिक विकास वह विकास है, जो कि सरलता से मापा जा सकता है किन्तु जीवन की गुणवत्ता व पर्यावरण की संवहनीयता जैसे नए सूचकांकों के प्रयोग की भी आवश्यकता है. अत: देश में विकास की अवधारणा सभी के लिए अलग-अलग सूचकांकों पर निर्भर करती है.

सर्वप्रथम आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान को देखते हैं. भारतीय महिलाओं का देश की जीडीपी में गणनात्मक योगदान 18% बताया जाता है. किन्तु इसमें घरेलू महिलाओं द्वारा जो योगदान दिया जाता है, उसकी गणना पूर्ण रूप से नहीं की जाती है. अंतरराष्ट्रीय संस्था के अनुमान के अनुसार भारतीय महिलाओं द्वारा देश की जीडीपी का लगभग 3% योगदान घर के कार्य के जरिए किया जाता है. साल 2019 में महिलाओं के घर के काम की कीमत लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी जो कि वैश्विक स्तर की कई बड़ी कंपनियों की कुल आमदनी से ज्यादा है. इसलिए कई अर्थशास्त्री भी मानते है. कि महिलाओं द्वारा किए गए घर के काम को भी एक उत्पादन की तरह ही देखा जाना चाहिए. यदि हम एक नर्स की सेवाओं को राष्ट्रीय आय में गिनते हैं तब गृहिणी के कार्य को भी राष्ट्रीय आय में गिना जाना चाहिए. यदि महिलाएँ घर का काम बंद कर दें तो परिवार नष्ट हो जाएंगे, जिसके कई गंभीर परिणाम आज कई विकसित देश देख रहें हैं. केवल एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है. कोविड-19 के समय घर के पौष्टिक भोजन व डब्बा बंद भोजन के स्वास्थ्य पर क्या परिणाम हुए यह बात किसी से छिपी नहीं है. अत: विकास के पथ पर प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद में गृहणी भी एक मूक सिपाही की भूमिका में अपना योगदान देती नजर आती है. शायद इसीलिए भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव श्री रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, 'हमारे लिए महिलाएँ न केवल घर की रौशनी हैं, बल्कि इस रौशनी की लौ भी हैं'.

अब बात करते हैं गणनात्मक योगदान की. इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, महिला उद्यमी 2030 तक लगभग 150-170 मिलियन नौकरियों का सृजन कर सकती हैं. इसी प्रकार अर्थ जगत के अन्य शीर्ष स्तंभों को भी कई महिला प्रधान/प्रमुखों ने संभाल रखा है. इनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम हैं सुधा बाल कृष्णन (भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी), नादिया चौहान (पारले एग्रो की संयुक्त प्रबंध निदेशक व मुख्य विपणन अधिकारी), रोशनी नादर मल्होत्रा (एच सी एल टेक्नोलॉजी की सी.ई.ओ.) किरण मजूमदार (बायोकोन लिमिटेड की अध्यक्ष) शोभना भारतीय (एच.टी.मीडिया की अध्यक्ष). यह तो हुई शीर्ष स्तर की बात, यदि हम सम्पूर्ण सेवा क्षेत्रों में देखें तो महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत कामकाजी है, किन्तु राष्ट्रीय डेटा संग्रहण एजेंसियाँ भी इस तथ्य को मानती हैं कि श्रमिकों के रूप में महिलाओं की भागीदारी को लेकर आँकड़ों में एक गहरा अंतराल है. शहरी भारत में महिला श्रमिकों की एक बड़ी संख्या मौजूद है. एक उदाहरण के तौर पर सॉफ्टवेयर उद्योग में 30% कर्मचारी महिलाएँ हैं. वे पारिश्रमिक और कार्यस्थल पर अपनी स्थिति के मामले में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ बराबरी पर हैं.

इसी प्रकार ग्रामीण भारत में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में कुल महिला श्रमिकों के अधिक-से-अधिक 89 % तक किसी न किसी प्रकार से अपनी सेवा उपर्युक्त क्षेत्र में दे रहीं हैं. एक अनुमान के मुताबिक कुल कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 50% से 60% तक है. विश्व बैंक की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेयरी उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी कुल रोजगार का 94% है और वर्तमान परिवेश में भी यह आँकड़ा कुछ भिन्न नहीं है. वन-आधारित लघु-स्तरीय उद्यमों में महिलाओं की संख्या कुल कार्यरत श्रमिकों का 51 % है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्वामित्व में भी महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़कर लगभग 20% हो गया है.

अब देश के सांस्कृतिक विकास व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को पहचान दिलाने वाली कुछ महिला हस्तियों के बारे में जानते हैं, जो कि संगीत, खेल, फिल्म आदि क्षेत्रों में देश के विकास में योगदान दे चुकी हैं व दे रही हैं, जैसे कि भारत रत्न से सम्मानित संगीतकार श्रीमती एम एस सुब्बुलक्ष्मी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भारत देश का नाम देश-विदेश में रौशन किया. इनके अलावा कुछ चर्चित नाम हैं. एंजोलि इला मेनन (मशहूर पेंटर), सोनल मानसिंह (भारत नाट्यम), एकता कपूर (भारतीय टेलीविज़न एवम फिल्म की सफल निर्माता व निर्देशक) मेरी कॉम (बॉक्सिंग), सीमा पूनिया व कृष्णा पूनिया (डिस्कस थ्रोअर), मिताली राज, स्मृति मंधाना, साक्षी मालिक (क्रिकेट), दीपा करमाकर (पहलवानी) हिना सिद्धू (निशानेबाजी), दीपिका कुमारी (तीरंदाजी), सानिया मिर्जा (टेनिस), साइना नेहवाल, व पी वी सिंधु (बैडमिंटन), झूलन गोस्वामी (क्रिकेट), कर्णम मल्लेश्वरी (भारोत्तोलक) साक्षी मालिक (कुश्ती) गीता फोगाट (पहलवानी) आदि यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि साक्षी मालिक व पी वी सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में दो ओलंपिक पदक भी जीते थे एवं इनमें से कई महिला खिलाड़ियों के जीवन पर फिल्मों का निर्माण किया गया है. इनके अलावा भी कई उभरती हुई प्रतिभाएँ है जो कि भविष्य में भारत को नई ऊँचाइयों तक लेकर जाने के लिए बिलकुल तैयार हैं. आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान देखे तो भारत के इतिहास में भी यह देखा गया है कि कई महिला योद्धाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है. कुछ चर्चित नाम हैं रानी लक्ष्मी बाई, रानी रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती. वर्तमान में भी यह योगदान जारी है. भारतीय सेना में 6807 से अधिक महिलाएँ काम

कर रही हैं. वहीं भारतीय वायुसेना में महिलाओं की संख्या लगभग 1607 है. अगर पुरुषों और महिला अधिकारियों के कुल अनुपात को देखें तो सबसे अधिक महिलाएँ नौसेना में अपनी सेवा दे रही हैं. नौसेना की कुल क्षमता का लगभग 6.45 फीसदी महिलाएँ हैं और तीनों सेनाओं में कुल मिला कर भारतीय महिलाओं की संख्या देखें तो यह 9,118 है. सेना के अलावा पैरा मिलिट्री, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखती है, इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में महिलाओं की संख्या लगभग 16000 के आस-पास है. अत: केवल देश विकास में ही नहीं अपितु देश के विकास को एक स्थायित्व देने में भी महिलाओं का विशेष योगदान है.

यदि बात करें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तो वर्ष 2023 की प्रशासनिक सेवा परीक्षा में लगभग 34% महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया है, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या कुल संख्या का लगभग 13% है, वर्ष 2022 में आई ए एस में सचिव स्तर पर 14% महिलाएँ थी.

इसी प्रकार भारतीय राजनीति, जो कि किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है. यदि महिला सांसदों के सदन में प्रतिशत को देखें तो लोकसभा व राज्य सभा में यह प्रतिशत क्रमश: 14.36% व 10% है. राज्य की विधान सभाओं में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व औसतन 9% है. आशा है कि भविष्य में भी यह बढ़त जारी रहेगी.

पर्यावरण की रक्षा भी सार्वभौमिक विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है. जिसकी रक्षा हेतु शुरुआती आंदोलनों में महिलाओं ने भी भाग लिया और आज भी पर्यावरण रक्षा के लिए प्रयासरत हैं.

यदि गहराई से सोचा जाए तो हमें ज्ञात होता है कि स्त्री को ही ईश्वर ने जीवन सृजन हेतु क्यों चुना. उसमें सहनशीलता पुरुष से अधिक है. यह तो सामान्य बात हुई, महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तित्व की पूर्णता ही इसका मूल कारण है. इसी प्रकार बौद्धिक स्तर पर स्वतंत्र स्त्री देश को विकसित करने में अग्रिम भूमिका निभाएगी क्योंकि इनकी मूल भावना में मांगना नहीं देना है और न ही एक सम्पूर्ण स्त्री किसी पुरुषत्व की नकल करने में या उससे प्रेरित होने में भरोसा रखती है. आइए हम उन्हें आगे बढ़ने और फलने-फूलने में मदद करें ताकि महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए 'अमृत काल' इन्हें समर्पित हो. उपर्युक्त सभी मोर्चों पर देश को विकसित बनाने में भारतीय महिलाएं अपना अमूल्य योगदान देती आई हैं व अमृत काल के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी देश की सभी महिलाएँ प्रतिबद्ध हैं. अत: समाज को नारी की शिक्षा व सम्पूर्ण विकास पर ध्यान देने योग्य वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि वह अपनी परिपूर्णता को प्राप्त कर सकें.

जगमोहन दुबे
क्षे.का. ग्वालियर

भंडारा शाखा, क्षे.का. नागपुर के स्टाफ श्री संदीप कारेमोरे की सुपुत्री सनाया कारेमोरे ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल सर्च कोलैबोरेशन (आईएएससी) और नासा (नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिसट्रेशन) के संयुक्त उपक्रम "एस्टेरॉयड सर्च कैम्पेन" में प्रतिभागी बनी तथा 3 प्रिलिमिनरी एस्टेरॉयड की खोज की और नासा के 'पृथ्वी के निकट वस्तु' पहचान कार्यक्रम में एक बड़ा योगदान दिया.

सेंट जोश डि एरियल शाखा की सहायक प्रबन्धक श्रीमती दीप्ति हेगड़े के सुपुत्र कुमार अथर्व साईश हेगड़े ने 25 जून 2023 को अखिल गोवा राज्य तायक्वोंडो प्रतियोगिता में 18 किलो से कम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है.

परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक श्री नेहाली भांबूरे के सुपुत्र, शांतनु भांबुरे ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन से ''इंटरनैशनल मास्टर'' की उपाधि हासिल की है.

विज़न 40 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था

भारत की आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक हमारा भारत देश 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि आने वाले कई दशकों तक ऐसा ही बना रहेगा. हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हमारे पास युवा जनसांख्यिकीय लाभांश है जिसे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में पहचाना जा रहा है. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भी अगर देश की कामकाजी उम्र की आबादी को लाभकारी रूप से रोजगार दिया जाए तो भारत की जीडीपी 2047 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है. रिपोर्ट, 'हार्नेसिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर बूस्टिंग ग्रोथ' में कहा गया है कि देश की कामकाजी आबादी 2020 से 2050 के बीच बढ़ेगी और आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक होगी. हालाँकि 2047 तक 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य महत्वाकांक्षी लग सकता है, लेकिन हितधारकों के सही हस्तक्षेप से इसे प्राप्त किया जा सकता है.

पृष्ठभूमि : आज के समय में सम्पूर्ण विश्व के अर्थशास्त्री भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति तथा बड़ी अर्थव्यवस्था मान रहे हैं. सैकड़ों वर्षों की गुलामी के पश्चात अपने आर्थिक ढाँचे में मूलभूत सुधार कर विकसित देशों को टक्कर देते हुए एक महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की यह राह आसान नहीं थी. भारत ने आजादी के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नीतियाँ अपनाई, चाहे राष्ट्रीकरण की हो या हरित क्रांति, उदारीकरण एवं निजीकरण के विषय हों. शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति व राष्ट्र प्रगति के विषय में स्वयं को केन्द्रित करने की चाह ने आज हमारे भारत देश को एक तेजी से उभरती हुई आर्थिक सुपरपॉवर के रूप में खड़ा किया है. अंतरराष्ट्रीय महत्व के सोच समझकर उठाए गए कदमों के कारण ही आज हमारा भारत देश जिसकी जनसंख्या विश्व की सबसे बड़ी आबादी के विकास के साथ-साथ इसे एक समस्या न समझकर विकास का हथियार बनाकर अधिक उत्पादन तथा कम लागत व मजदूरी की नीति के चलते विकास के नए आयामों को स्थापित करने में सफलता अर्जित की है. आज से तक़रीबन 30 साल पहले तक भारत सुरक्षा, तकनीक तथा कई अन्य विषयों पर विदेशी सहायता तथा आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था. लेकिन आत्मनिर्भर भारत मिशन ने बहुत बड़ा बदलाव लाया और भारत दुनिया में उत्पादन का एक नया केंद्र बन गया है.

उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति ने वैश्विक नजारा बदल कर रख दिया, अब तक भारत को जनसंख्या के बोझ से दबा व पिछड़ा देश माना जाता था. इन्हीं नीतियों के सकारात्मक परिणामों के कारण भारत अब एक उभरती हुई शक्ति के रूप में उभर रहा हैं. अब चीन ही भारत का प्रतिद्वंदी नजर आता है. भविष्य में भारत का विकास, तकनीक, सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चीनियों से मुकाबला होना संभावित है. आज के समय में जापान, फ्रांस, रूस तथा सुपर पॉवर अमेरिका जैसे देश भी भारत से दोस्ती करना चाहते हैं.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : आज भारत को विश्व के अधिकांश देश व कम्पनियां एक बड़े बाजार के रूप में देख रही हैं. हर देश आज भारत के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करने को लालायित है. पिछले कुछ सालों के दौरान पूरे विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है. भारत में विदेशी कम्पनियों को निवेश से ज़रा भी संकोच नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ विश्व के सभी देश आर्थिक मंदी से गुज़र रहे हैं, तब भारत अपनी विकास दर के मुताबिक़ आगे बढ़ रहा है. दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. भारत ने विकास दर के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. इज ऑफ डूइंग बिज़नेस, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, पीएलआई जैसे अन्य पहल इस दिशा में अहम हैं. आयात की क्षमता रखने वाले देशों में भारत अग्रणी राष्ट्र है. हाल ही के वर्षों में हमने सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और व्यापार आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है. इसमें कोई शक नहीं है, कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और इसी वर्ष रूस, अमेरिका तथा फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत के व्यापारिक समझौतों ने इस बात पर मुहर लगा दी है. इन विदेशी निवेश से भारत के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही उनके जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आएगा. आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत एक याचक राष्ट्र की भूमिका से बड़े राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होने वाला देश बन चुका है. अमेरिका जैसे देश की सभी बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय कम्पनियों के मालिक व महत्वपूर्ण अधिकारी भारतीय अमेरिकी हैं. मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा इस देश के बड़े कारोबारी हैं, जो भारत सहित विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक हैं. इन्होंने देश में रहकर तकनीकी तथा अन्य संरचनात्मक ढाँचे में मजबूती देकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है एवं विदेशी निवेश की संभावनाएं बढ़ाई हैं. वित्तीय वर्ष 2023 में कुल एफडीआई प्रवाह 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.

जनसंख्या और जनशक्ति संसाधन: जनसंख्या को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है. इस संबंध में जनसंख्या आर्थिक विकास में उत्प्रेरक और बाधा दोनों के रूप में काम कर रही है. सबसे पहले, जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में श्रम और उद्यमिता प्रदान करती है. जनशक्ति संसाधनों से देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन किया जा सकता है. उचित मानव पूंजी निर्माण, बढ़ती गतिशीलता और श्रम विभाजन के साथ, जनशक्ति संसाधन आर्थिक विकास में उपयोगी सहायता प्रदान करते हैं. दूसरी ओर, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर उपभोग के साधन के रूप में वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाती है, जिससे उपभोग आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, निवेश और निर्यात के लिए कम संतुलन, कम पूंजी निर्माण, व्यापार का प्रतिकूल संतुलन, सामाजिक और आर्थिक मांग में वृद्धि होती है. सरकार के विभिन्न पहल जैसे

स्किल इंडिया मिशन सम्पूर्ण विश्व के लिए रोजगार हेतु युवाओं को तैयार करते हैं. भारत के इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि प्रोफेशनल की मांग सम्पूर्ण विश्व में है.

कृषि : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जीवीए 20.1% था, 2021-22 में यह 19% था और यह फिर से घटकर 18.3% हो गया. 2022-23. एक समय भारत के राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सबसे बड़ा योगदान था. फलों और कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद में अच्छा योगदान देता है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमूल नामक सहकारी संस्था है जो डेयरी उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है. कोरोना काल में जब सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी तब भारत के कृषि क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला ही नहीं बल्कि नयी ऊंचाईयों पर पहुंचाया एवं विदेशों मे भी आपदा के समय भारतीय खाद्य सामग्री की आपूर्ति किया है.

औद्योगिक उत्पादन : वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं. 'मेक इन इंडिया' योजना का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना भी है. इससे विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी और निर्यात के लिए अधिक सामान उपलब्ध होगा. बढ़ा हुआ निर्यात और बढ़ा हुआ उत्पादन सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं. 'मेक इन इंडिया' योजना की सफलता ने हमारी जीडीपी ने 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छुआ है, जो 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर था. आगे की वृद्धि में भी इसके इसी तरह की भूमिका निभाने की उम्मीद है. इस क्षेत्र में रासायनिक उद्योगों का बड़ा योगदान है. भारत बड़ी मात्रा में फार्मास्यूटिकल्स, उपकरण, धातु और अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात करता है. रत्नों, बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों का खनन भी देश की बढ़ती जीडीपी में बहुत योगदान देता है.

सेवाएँ : भारत का तेजी से बढ़ता सेवा उद्योग इस बात का उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे आधुनिक आर्थिक विकास मॉडल पारंपरिक रूप से स्थापित मॉडलों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. सेवा क्षेत्र भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जो देश की जीडीपी में 50% से अधिक का योगदान दे रहा है. इस क्षेत्र में 2021-22 की पहली छमाही में 10.8% की वृद्धि देखी गई है और पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वित्तीय वर्ष 23 में 9.1% बढ़ने का अनुमान है. भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि अन्य देशों के विपरीत, जहां आर्थिक विकास के कारण कृषि से उद्योगों की ओर बदलाव हुआ है, भारत ने कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव दर्ज किया है. सेवा क्षेत्र की वृद्धि से आईटी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, परिवहन और वित्त जैसे विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ है. सेवा क्षेत्र की उल्लेखनीय वृद्धि को कई कारकों द्वारा समर्थित किया गया है जैसे शिक्षित और कुशल श्रमिकों की बढ़ती संख्या, मध्यम वर्ग की आबादी में वृद्धि और डिजिटल अर्थव्यवस्था का उद्भव आदि.

वित्तीय सेवा क्षेत्र: वित्तीय सेवा क्षेत्र को सरकारी अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है. यह भारत से संबंधित वित्तीय सेवाओं की ऑन-शोरिंग को सक्षम करने में मदद करता है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान में वैश्विक वित्तीय केंद्रों से प्रदान किया जा रहा है. इससे वित्तीय सेवाओं और उच्च-कौशल वाली नौकरियों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. पिछले वर्षों में, वित्तीय क्षेत्र की वृद्धि स्थिर रही और वैश्विक वित्तीय केंद्रों से इन सेवाओं को प्रदान करने की आवश्यकता पैदा हुई है. वित्तीय सेवाओं के साथ प्रौद्योगिकी की भागीदारी ने भारत में इस क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है. भारत वर्तमान में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है और दुनिया भर में सेवाएं प्रदान करता है. भारत में 2,000 से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त फिनटेक स्टार्ट-अप हैं जो देश की जीडीपी में तुलनात्मक रूप से अधिक योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं. 2023 तक, भारत में फिनटेक क्षेत्र में प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और राजस्व 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है. इस क्षेत्र के 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. भारत 87% की फिनटेक अपनाने की दर के साथ अग्रणी है, जो वैश्विक औसत 64% से काफी अधिक है. सरकार ने वित्तीय सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2014 में प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना है. इस योजना ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास बिना किसी न्यूनतम सीमा के बैंक खातों तक पहुंच हो इस प्रकार से इसने वित्तीय सेवाओं का आनंद लेने के लिए और अधिक लोगों को जोड़ने में योगदान दिया.

राजनीतिक स्थिरता एवं विज़न: किसी भी देश की प्रगति के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है. वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न फॉर न्यू इंडिया का निर्णय भारत की प्रगति में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा. हाल ही में जी20 बैठक की मेजबानी भी हमारे देश ने की है. विश्व पटल पर कोई भी राजनीतिक मुद्दा हो या कोई नयी पहल हो सभी देश आज भारत की ओर देखते हैं. कोरोना काल में भारत ने बहुत सारे देशों को वैक्सिन एवं अन्य मेडिकल सहायता मुहैया कारवाई.

निष्कर्ष : अत: भारत की जीडीपी 8-9% की तेज दर से बढ़ रही है और आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक हमारा भारत देश 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा. हमारा भारत देश विश्व पटल पर अपना परचम लहराएगा.

सुनील कुमार
अंचलीय ज्ञानार्जन केंद्र, गुरुग्राम

अमृत काल में दिव्यांग वर्ग का उत्थान : बैंकों की भूमिका

अमृत काल की अवधारणा बहुत व्यापक है और इसमें सबका साथ एवं सबका विकास का मूल्य निहित है ही, इसके साथ ही राष्ट्र को विकास के उस सर्वोच्च स्थान पर ले जाने की उच्च भावना है, जहाँ पर पहुंचकर देश के नागरिकों में सामाजिक, राजनैतिक, लैंगिक, वर्णगत, सूचनागत एवं आर्थिक क्षेत्र में अंतर न्यूनतम होगा. इस हेतु हमारे पास 25 वर्ष की अवधि है, जो कि देखने में बड़ी अवश्य लगती है किंतु मानव के विकास क्रम में ढाई दशक का काल कुछ भी नहीं हुआ करता है.

देश की स्वाधीनता के समय दिव्यांगजन की जनसंख्या का कोई आधिकारिक आँकड़ा नहीं था. 2001 एवं 2011 में दिव्यांगजन को राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना में स्थान दिया गया. यदि 2011 की जनगणना को आधार मानें तो हम पाएंगे कि देश में 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांगता से प्रभावित थे. इससे आगे यदि हम 2016 में आए दिव्यांगता विषयक अधिनियम की बात करें तो पाते हैं कि हमारे देश में दिव्यांगता की श्रेणी में बढ़ोत्तरी कर अब कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता दे दी गई है और आगे इस सूची को बढ़ाया जा सकता है. हालाँकि इसमें बहुत-सी बीमारियों को भी दिव्यांगता की तरह स्वीकार किया गया है.

हमें यदि अमृत काल में राष्ट्र को संपन्नता के शिखर पर ले जाना है, देश को स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी बनाना है तो हमें प्रत्येक वर्ग में इस भावना को जगाना होगा. दिव्यांगजन को प्रोत्साहन एवं आर्थिक रूप से संपन्न बनाने पर हम अपनी अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक सशक्त पाएंगे. साथ ही अपने देश को मानव संसाधन के रूप में एक बड़ा उपहार दे सकेंगे. देश में 'जितने हाथ-उतने काम' यदि प्रदान किया जा सके तो ही सारे राष्ट्र को विकास की उच्च श्रेणी में ले जाया जा सकता है. इसके साथ ही यदि दिव्यांगजन को मुख्य धारा से जोड़ दें तो संभवत: हम आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान की उस व्यवस्था को बढ़ावा देंगे जिससे सारे देश को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

कहा गया है कि कोई भी स्वाधीनता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना अधूरी होती है. बात बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज के प्रत्येक कार्य पर धन संपत्ति का दबदबा सदैव बना ही रहता है. यह प्रत्येक युग और काल में होता आया है. आज जब हम देश को विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा करने के स्वप्न संजो रहे हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी दिव्यांग जनसंख्या को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं. इसमें बैंक एवं वित्तीय संस्थान महती भूमिका अदा कर सकते हैं. आइए हम इस प्रश्न पर विचार करें कि आखिर किन कारणों से बैंकों को दिव्यांगजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा अपनी विभिन्न योजनाओं में उन्हें भी सम्मिलित करना चाहिए.

दिव्यांग वर्ग का अर्थव्यवस्था में योगदान

सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से दिव्यांगजन की वित्तीय गतिविधियाँ सीमित रही हैं, किंतु अब परिस्थिति बदल रही है. शिक्षा एवं रोजगार के नए अवसरों तथा प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा दिव्यांगजन भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं. इसके साथ ही चलिष्णुता की कठिनाई उन्हें एक स्थान पर रहकर अपने काम को अधिक ध्यानपूर्वक तरीके से करने के लिए प्रेरित किया है. देश में बहुत से उच्च पदों पर आज दिव्यांगजन हैं. कई दिव्यांगजन तो आरबीआई जैसे वित्तीय नीति निर्माता संस्थान में भी हैं तथा नीति निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं. इतना ही नहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में भी वे अधिकाधिक सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं. बैंकों की यदि बात करें तो हम पाते हैं कि हमारे अपने सहकर्मी के रूप में भी दिव्यांगजन अच्छा कार्य कर रहे हैं. ऐसे में दिव्यांगजन से हमें अधिकाधिक उत्पादकता की आशा करनी चाहिए. आखिर विकसित अर्थव्यवस्था वही हो सकेगी जहाँ पर प्रत्येक वर्ग के पास योग्यता के अनुसार काम हो तथा आर्थिक उन्नयन में उस वर्ग की भूमिका हो.

कैसे बने हमारे दिव्यांग साथी मुख्यधारा का अभिन्न अंग

बहुत से ऐसे लाभ हैं जो दिव्यांगजन हमारी अर्थव्यवस्था को प्रदान कर सकते हैं जैसे कि अन्य वर्ग करते हैं. प्रश्न यह उठता है कि आखिर बैंक ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे दिव्यांगजन की भूमिका को मजबूती के साथ सुनिश्चित किया जा सके. आइए कुछ बिंदुओं पर दृष्टि डालें -

1. **बैंकिंग सुविधाएं सब के लिए** : विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सरकार एवं आरबीआई द्वारा सभी को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं, फिर भी कई बार जोखिम प्रबंधन एवं अन्य सुरक्षा विषयक भय के चलते दिव्यांगजन को बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं. दृष्टि दिव्यांगजन की बात करें तो कई बार यह सुनने को मिलता है कि उन्हें अपना एटीएम अथवा चैकबुक जैसी सुविधा नहीं मिलती है. ऐसे में इस विषय पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है. इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम दिव्यांगजन में बैंक उत्पादों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें. ग्राहकों को प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है. इसी तरह सुगम्यता भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर प्रत्येक बैंकिंग संस्थान को काम करना चाहिए क्योंकि

परिसर में पहुंचने से लेकर वेबसाइट एवं मोबाइल बैंकिंग के उपयोग में सुगम्यता की आवश्यकता होती है. इतना ही नहीं वेबसाइट्स तथा मोबाइल बैंकिंग में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव भी सुगम्यता को प्रभावित करते हैं. ऐसे में बैंकिंग सुविधाएं पढ़े-लिखे दिव्यांग वर्ग तक भी नहीं पहुंच पाती है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक्सेसिबिलिटी सेल एक अच्छी पहल है, जिसे बैंकिंग उद्योग द्वारा अनुकरण करते हुए अपनाना चाहिए. इतना ही नहीं देश में सबसे पहले बोलने वाले एटीएम तथा पूर्णत: बाधा रहित संपूर्ण एटीएम हमारे बैंक द्वारा ही स्थापित किए गए थे.

सुगम्यता ऐसा विषय है जिससे हमारे अपने दिव्यांग कार्मिक तो प्रभावित होते ही हैं, हमारे ग्राहकों को भी इससे बहुत अधिक फर्क पड़ता है. इसलिए आवश्यक है कि काम करने का वातावरण तो सुगम्य हो ही, हमारे उत्पाद भी सुगम्य बनें.

2. दिव्यांगजन की शिक्षा एवं बैंकों की भूमिका : आधुनिक समय में मुख्यधारा से जुड़ने में शिक्षा महती भूमिका अदा करती है. ऐसी परिस्थिति में हम सामान्य वर्ग की शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान कर रहे हैं, पर दिव्यांगजन की शिक्षा के संबंध में हमारे पास कोई पृथक योजना नहीं है. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) अवश्य कुछ कार्य कर रहा है, किंतु ऐसे कार्यों को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह संस्था बहुत ही सीमित क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा उसके विभिन्न बैंकों के साथ करार भी नहीं हैं, जिसके कारण किसी भी योजना का लाभ दिव्यांगजन तक पहुंचने में कठिनाई होती है. दीर्घ अवधि के ऋण यह संस्था स्वीकृत नहीं कर पाती है. अत: आवश्यकता इस बात की है कि बैंक आगे आएं तथा दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्रदान करने में पहल करें. इस हेतु ब्याज दर कम रखी जाए तथा दीर्घावधि ऋण देने की व्यवस्था हो. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम से सभी बैंकों का एक साझा करार हो, जो सभी पर समान रूप से लागू हो.

3. पुनर्वास एवं बैंकों की भूमिका : जब कोई सामान्य व्यक्ति किसी दुर्घटना अथवा अन्य कारणों से दिव्यांग हो जाता है, तो ऐसे में उसे आवश्यकता होती है विशेष प्रशिक्षण एवं आत्मविश्वास अभिवृद्धि की, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने की आवश्यकता होती है. ये कार्यक्रम कुछ माह से लेकर कुछ वर्ष की अवधि तक के हो सकते हैं. ऐसे कार्यक्रमों को अधिकांश मामलों में स्वयंसेवी संस्थाएं चलाती हैं जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी होती है. ऐसे में बैंकों द्वारा प्रशिक्षण, प्रशुक्षुओं के लिए तथा संस्थाओं के लिए वित्तपोषण व्यवस्था करनी चाहिए ताकि समाज के इस वर्ग को सशक्त कर राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को सुनिश्चित किया जा सके.

4. दिव्यांगजन हेतु स्वरोजगार एवं उसमें बैंकों की भूमिका: राष्ट्रीय दिव्याांगजन वित्त विकास निगम द्वारा इस हेतु ऋण प्रदान किए जाते हैं, किंतु वे पर्याप्त नहीं हैं. आज भी दिव्यांगजन को मुख्य धारा में दिये जाने वाले स्वरोजगार विषयक ऋण प्रदान नहीं किये जाते हैं या बहुत कठिनाइयों के पश्चात् उन्हें ये ऋण मिल पाते हैं. ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि दिव्यांगजन को भी साधारण श्रेणी के ऋण प्रदान किए जाएं. इसके साथ ही दिव्य कला मेला जैसी अवधारणओं को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाए ताकि प्रत्येक दिव्यांग उद्यमी अपने उत्पादों को आम जन तक पहुंचा सके. इस हेतु प्रशिक्षण व अन्य सहगामी गतिविधियों हेतु वित्तपोषण की आवश्यकता रहेगी.

5. बैंकों में नियोजन : आज बैंकिंग कार्य प्रौद्योगिकी आधारित हो गया है. ऐसे में दिव्यांगजन का बैंकों में रोजगार प्राप्त करना आसान हुआ है. दृष्टिबाधित वर्ग की यदि बात करें तो हम पाते हैं कि यह वर्ग पहले कुर्सी बुनाई एवं टेलीफोन ऑपरेटर जैसे कार्य ही कर पाता था, किंतु आज कम्प्यूटर के एक्सेसिबल हो जाने तथा अन्य सुगमताओं के चलते उनके द्वारा बहुत से क्षेत्रों में काम कर पाना सुगम हुआ है, जिससे बैंकों के मानव संसाधन का अधिकाधिक उपयोग हो पा रहा है. आज उच्च प्रबंधन वर्ग में भी दिव्यांगजन को पदोन्नत किया जा रहा है, जो प्रमाण है इस वर्ग के कार्यक्षम होने का.

6. दिव्यांगजन सहयोगी उपकरण एवं बैंकिंग : यदि विशेष उपकरणों की बात की जाए तो इनकी सहायता से दिव्यांगजन की न केवल कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि इनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है. कम्प्यूटर द्वारा संचालित व्हीलचेयर किसी दिव्यांग व्यक्ति को चलिष्णुता सक्षम बनाकर उसकी उत्पादकता को अन्य सहयोगियों के बराबर ला सकती है. इसी तरह से अन्य उपकरण जो प्रौद्योगिकी आधारित हैं, विभिन्न दिव्यांगजन के लिए सहायक हो सकते हैं. अधिकांश मामलों में ये उपकरण आज भी विदेशों से आयात करने पड़ते हैं, अत: इनकी कीमत अधिक होती है, जिसे साधारणत: दिव्यांगजन क्रय नहीं कर पाते. यदि इन्हें आसान किश्तों पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए तो हम अपनी दिव्यांग जनसंख्या को बहुत बड़ा लाभ प्रदान कर सकेंगे.

इस तरह हम पाते हैं कि अमृत काल सबके लिए अमृत तुल्य होने वाला है, अर्थात सबको लाभ पहुंचाकर हमारे राष्ट्र को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने वाला है. ऐसे में देश का दिव्यांग वर्ग बैंकों के द्वारा की जाने वाली आर्थिक पहल के माध्यम से विकास की इस गगनचुंबी इमारत की आधारशिला में कुछ मजबूत ईंटें स्थापित करने में अपनी अग्रगामी भूमिका अदा कर सकता है. आवश्यकता इस बात की है कि हमारे नीति निर्माता इसे पहचानें तथा अपनी योजनाओं में दिव्यांगजन को दया के पात्र के रूप में नहीं, बल्कि सक्रिय मानव संसाधन के रूप में स्वीकार करें.

अर्पित जैन
क्षे. का., नर्मदापुरम

अमृत काल में भारतीय भाषाएं

भाषा संप्रेषण का साधन मात्र नहीं बल्कि एक समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान स्थापित करने का सशक्त माध्यम है. 'विरासत पर गर्व' अमृत काल के पंच प्रण में से एक है. निश्चय ही भाषाएं भारत की समृद्ध विरासत का अभिन्न अंग हैं. भारत की भाषाएं देश की समृद्ध और वैविध्यपूर्ण धरोहर की संवाहक हैं तथा भारतीय संस्कृति और संप्रदाय की परिचायक हैं. भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी इन भाषाओं की अस्मिता बनी हुई है. हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, बंगला जैसी कई क्षेत्रीय भाषाओं ने सदियों से जारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण कई देशों में अपनी अलग पहचान बनाई है. अधिकांश भारतीय भाषाओं की अपनी लिपि तथा साहित्य भी मौजूद है, जिसमें ज्ञान, भक्ति, दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि विभिन्न विषयों के संबंध में आधिकारिक ग्रंथ भी उपलब्ध हैं. साथ ही काव्य रचना की विभिन्न शैलियां इन भाषाओं को और आकर्षक बनाती हैं. क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य रचना को राजाश्रय प्राप्त था जिसके कारण प्रत्येक भाषा में उत्कृष्ट साहित्य का भंडार विद्यमान है. साहित्य सृजन की अविरल यात्रा में कई पड़ाव आए और आधुनिक काल तक आते-आते छंदबद्ध पद्य की तुलना में गद्य विधाएं अधिक लोकप्रिय बनीं. प्रिंटिंग प्रेस के आगमन से क्षेत्रीय भाषाओं की विपुलता में वृद्धि हुई. यहाँ तक कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्षेत्रीय समाचार पत्र, जो कि भारत की जनता की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम थे, पर प्रतिबंध भी लगाए गए. आधुनिक समय में भी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाओं का परिचालन अंग्रेजी की तुलना में बहुत अधिक है.

जन सांख्यकीय डेटा के अनुसार भारत में 196 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है. इन भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा साथ ही इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेज़ी और राजस्थानी भाषा में यानी कुल 23 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है तथा यूपीएससी के उम्मीदवार इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं. क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में संविधान में कई प्रावधान मौजूद हैं. क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन तथा इन भाषाओं के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित अवसर उपलब्ध हैं. अब तक छह भाषाओं यथा- संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड, ओडिया तथा मलयालम को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है. इसका तात्पर्य यह है कि ये भाषाएं पुरातन हैं, इनकी स्वतंत्र लिपि है, 1500-2000 वर्ष का अभिलेखित इतिहास मौजूद है, इन भाषाओं में रचित साहित्य मौलिक है, समृद्ध है और आधुनिक भाषा रूप तथा प्राचीन रूप में क्रमिक परिवर्तन द्रष्टव्य हैं.

संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएं हैं यथा- अरबी, मंदारिन, फ्रेंच, रूसी, स्पैनिश और अंग्रेजी. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय अपने कामकाज के लिए सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच का इस्तेमाल करता है. 2018 से संयुक्त राष्ट्र का हिंदी में ट्विटर अकाउंट और न्यूज पोर्टल विद्यमान है. हर सप्ताह संयुक्त राष्ट्र का एक हिंदी ऑडियो बुलेटिन जारी होता है. भारत सरकार ने यूएन में हिंदी को आधिकारिक मान्यता दिलाने और इसके प्रयोग हेतु यूएन को आठ लाख अमेरिकी डॉलर का सहयोग भी उपलब्ध कराया है. जून, 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत द्वारा प्रस्तावित बहुभाषावाद संकल्प पारित किया. इस संकल्प के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संगठन को सरकारी तथा गैर-सरकारी भाषाओं में महत्वपूर्ण सूचनाओं के संप्रेषण हेतु प्रोत्साहित किया गया है. इसमें पहली बार हिंदी के साथ-साथ उर्दू और बंगला भाषा का भी उल्लेख है. भारत की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया था. यूएन ने पहली बार माना है कि संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी व अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है. भारत के लिए इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

भारतीय भाषाओं की समृद्ध विरासत को कायम रखने और इसकी समृद्धि को बढ़ाने हेतु आवश्यक हो जाता है कि सर्वप्रथम इन भाषाओं के अध्ययन और इन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा हेतु संसाधन और अवसंरचना बनाई जाए. अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने हेतु

जागरूक प्रयास किए जाने चाहिए. अपनी भाषा में वार्तालाप करना और निजी पत्र व्यवहार में अपनी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना एक स्वाभाविक प्रकिया होनी चाहिए. अपनी भाषा में प्राप्त जानकारी अधिक बोधगम्य होती है. अत: मातृभाषा के माध्यम से प्राप्त शिक्षा अधिक प्रभावशाली होती है, विशेष रूप से ऐसे समूहों में जिनकी पहली पीढ़ी शिक्षा प्राप्त कर रही है. साथ ही मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के अवसर प्रदान करने से लोक कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों से संबंधित जानकारी की शृंखला को आगे बढ़ाया जा सकता है. कई राज्यों में स्कूली शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य है. साथ ही देश की विभिन्न भाषाओं को सीखने का प्रयास करना और इनकी लोकप्रियता बढ़ाना आवश्यक है. एक नई भाषा सीखने से न केवल उस भाषा विशेष की संस्कृति के द्वार खुल जाते हैं बल्कि यह संपर्क स्थापित करने की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी बनती है.

भारतीय भाषाओं की विरासत की निरंतरता को बनाए रखने की आवश्यकता को पहचानते हुए नई शिक्षा नीति में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर ज़ोर दिया गया है. नई शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम 5वीं कक्षा तक और अधिमानी तौर पर 8वीं और उच्चतर कक्षाओं में मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई है. इस संबंध में एआईसीटीई ने देश भर में 14 महाविद्यालयों को 11 क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से इंजीनियरी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु अनुमति प्रदान की है. हाल में मध्य प्रदेश की 13 सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के तीन विषयों को हिंदी में पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है. उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित करने की दिशा में भी बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है.

किसी भी भाषाई समुदाय द्वारा यदि अपनी भाषा में संवाद करना कम या बंद किया जाता है तो उस भाषा के अस्तित्व का ह्रास होने लगता है और भाषा लुप्त हो जाती है. संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन विश्व की एक भाषा लुप्त हो रही है. भारतीय भाषाओं को इस दुर्गति से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने फरवरी 2014 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के तत्वावधान में लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण योजना की स्थापना की है. इस योजना के माध्यम से लुप्तप्राय भाषाओं के शब्दकोश, व्याकरण संरचना और इन भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान भंडार को प्रलेखित और संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है. केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा देश के कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ इस मिशन हेतु गठबंधन किया गया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में विलुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. वर्तमान में 117 भाषाओं को इस प्रयोजन से सूचीबद्ध किया गया है.

केंद्र सरकारी संस्थाओं, उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर संघ सरकार की राजभाषा नीति लागू होती है. राजभाषा नीति के अनुसरण में विभिन्न प्रकार के प्रलेखों और कार्य क्षेत्रों में द्विभाषी / त्रिभाषी सूत्र का पालन किया जाना अपेक्षित है. राजभाषा नीति के अनुपालन में क्षेत्रीय भाषाओं को भी उचित महत्व दिया गया है और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जनता को सूचना प्रदान करने और संप्रेषण पर ज़ोर दिया गया है. राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु रिपोर्टिंग, समीक्षा तथा निरीक्षण का सुव्यस्थित तंत्र विद्यमान है. राजभाषा नीति के अनुपालन में उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए कारगर प्रयास किए जाने पर न केवल सांविधिक अनिवार्यताओं की पूर्ति होगी बल्कि जन-मानस के साथ संपर्क भी स्थापित होगा.

बैंकों में जनता की भाषा में संप्रेषण का अपना महत्व है. बैंक अपनी सेवाएं जनता तक पहुँचाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाते हैं. ग्राहक सेवा प्रदान करने वाले अग्रपंक्ति के स्टाफ को स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए. बैंकों द्वारा मुद्रण और सोशल मीडिया माध्यमों से अपने ग्राहकों के साथ स्थानीय भाषा में संवाद स्थापित करने हेतु पहल किए जा रहे हैं. संप्रेषण और विज्ञापन में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग सांविधिक आवश्यकता भी है. साथ ही ग्राहकों से वर्तालाप में सुविधा हेतु स्थानीय भाषाओं में अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.

यद्यपि न्यायालयों की भाषा अब भी अंग्रेजी है, तथापि जनवरी 2023 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का चार क्षेत्रीय भाषाएं यथा- हिंदी, तमिल, गुजराती और ओडिया में अनुवाद किया जाएगा. अब तक लगभग 9500 निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है. उच्च न्यायालयों में भी अनुवाद का कार्य आरंभ हुआ है. इसके साथ-साथ कई न्यायालय अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा में भी अपने निर्णय सुना रहे हैं. इस दिशा में अगला प्रयास यह होगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनूदित प्रतियाँ हर भारतीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएं.

भाषा व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र की पहचान है. देश की एकता, अखंडता, संवृद्धि और गतिशीलता सबके मूल में भाषा की शक्ति काम आती है. क्षेत्रीय भाषाएं भारत की वैविध्यपूर्ण और समृद्ध संस्कृति, धरोहर और ज्ञान भंडार की परिचायक और संवाहक हैं. इनकी जीवंतता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और इसमें व्यक्ति का अपना निजी सम्मान भी निहित है. अमृत काल में भारतीय भाषाओं को संपन्न बनाने हेतु इनमें उपलब्ध प्रचुर साहित्य और ज्ञान का दोहन करने के साथ-साथ नई पीढ़ी में क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने की ललक जागृत करने और नवीन प्रतिभा को तराशने की नितांत आवश्यकता है. भाषाएं संपन्न होंगी तो राष्ट्र सर्वांगीण रूप से संपन्न होगा और विकसित भारत का सपना पूर्ण होगा.

अम्बरीष कुमार सिंह
मानव संसाधन, केंद्रीय कार्यालय

अविस्मरणीय मांडू

पश्चिमी मध्य प्रदेश के मांडू शहर में जहाज महल, हिंडोल महल, जल महल, तवेली महल, झील और रानी रूपमति का महल जैसी सुंदर और प्रेक्षणीय जगह हैं. जहाज महल के परिसर में पहले तवेली महल है. यह तीन मंज़िला महल है जिसके भूतल का उपयोग जानवरों को रखने के लिए किया जाता था. इस कारण इस महल को तवेली महल कहते है. तवेली महल के आगे जहाज महल है. यह सुंदर महल मुंजा झील और कपूर झील के बीचों बीच बनाया हुआ है. इस महल से झीलों का नज़ारा दर्शनीय है. जब इस महल का प्रतिबिंब पानी में दिखाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज पानी पर तैर

रहा हो. हिंडोला महल की टेडी दीवारें बाहर से झुकी हुई दिखाई देने के कारण इसका नाम हिंडोला महल पड़ा है. हिंडोला महल का निर्माण सभा भवन के रूप में किया गया था. इसी परिसर में स्थित शाही परिसर और जल महल का अधिकतर भाग खंडर अवस्था में है. जल महल मुंजा तालाब के बीच में बना हुआ है. रानी रूपमति का महल भी मांडू शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. यह महल पहाड़ी के किनारे बना हुआ है. महल से दूर तक फैला मैदान और पहाड़ दिखता है. रानी रूपमती यहां से नर्मदा नदी का दर्शन किया करती थी. रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर के प्रेम की मिसाल देता यह शहर अपने पर्यटकों को उसके अद्भुत महलों और खंडहरों से अपने समृद्ध इतिहास का परिचय देता है.

अक्षय आंगवलकर
सतर्कता विभाग, केंद्रीय कार्यालय

बैंकिंग का अमृत काल

युगों के साथ बदलती आई है बैंकिंग की गाथा,
अमृत काल ने नया अध्याय जगाया है
बैंकिंग का नया रूप निखर आया है,
देखो साथियों अमृत काल आया है.

बैंकिंग ने खुद को नए कलेवर में सजाया है,
तकनीक के साथ नवीनता का तड़का लगाया है
बैंकिंग का नया रूप निखर आया है,
देखो साथियों अमृत काल आया है.

डिजिटल के तार से संसार को बांध दिखाया है,
पूरे विश्व को एक पटल पर साथ बैठाया है
नेटबैंकिंग और एटीएम एक हाथ में,
दूसरे में क्रेडिट कार्ड का उपहार सजाया है
बैंकिंग का नया रूप निखर आया है,
देखो साथियों अमृत काल आया है.

खाताधारकों को नयी योजनाएँ लुभाती हैं,
निवेशकों को उच्च लाभ की बातें ही समझ आती हैं
लोन और बैंकिंग सेवाओं ने दम दिखाया है,
हर व्यक्ति का कुछ कर गुजरने का जज़्बा सच हो पाया है
बैंकिंग का नया रूप निखर आया है,
देखो साथियों अमृत काल आया है.

चार दीवारी से बाहर निकाल बैंकिंग को लोगो तक पहुंचाया है,
भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का वायदा दिखाया है
आधुनिकता की रफ्तार संग बैंक मोबाइल में समाया है,
एसएमएस और वॉइस बैंकिंग ने इस पर सहजता का टीका लगाया है
बैंकिंग का नया रूप निखर आया है,
देखो साथियों अमृत काल आया है.

बैंकिंग और अमृतकाल का संगम खूब रंग जमाया है
बैंकिंग का नया रूप निखर आया है,
देखो साथियों अमृत काल आया है.

श्रीमती उपासना सिरसैया
क्षे का पंजागुट्टा

मंजर

देखना वह मंजर भी आएगा
रख हौसला और अपनी ज़मीर जिंदा रख,
तू जरूर अपनी सफलता से बुझी शमा जलाएगा,
देखना वह मंजर भी आएगा।
बस अपना जुनून, अपनी आस,
यह प्यास जिंदा रख,
तूफ़ान ख़ुद रहेगी, किस्मत भी पलटेगी
तुझे मंजिल के करीब देख,
तेरा खुदा भी मुस्कुराएगा,
देखना वह मंजर भी आएगा ।।
तूने जो पसीना बहाया है,
वक्त उसकी कीमत जरूर चुकाएगा,
तू अपने ख्वाबों के हकीकत का परचम
फलक तक लहराएगा
देखना वह मंजर भी आएगा ।।
रातों को आंखों में यथार्थ का अरमान लिए
आहिस्ता मंजिल की ओर बढ़ता रह,
याद रख जग तेरी सफलता को
जरूर अखबारों की सुर्खियां बनाएगा
देखना वह मंजर भी आएगा ।।
अपनी कामयाबी की कुर्बानी में
कितने ख्वाहिश तेरे दफन होंगे,
आज खुद की खुशियों की उजाले के मोहताज हो,
कल महाभारत के कर्ण होंगे,
तू क्षितिज के अंतिम छोर पर खड़ा होगा
कोई क्या तुझे आजमाएगा,
देखना वह मंजर भी आएगा।
गवाह है ये हरी-भरी वादियाँ,
ये बर्फीले रास्ते तेरी मुलाज़मत को जुनैद बन
क्या खुशी पाया है
मंजिल बदल लिया अपनी हैसियत को
तू एक दिन पत्थर पर भी फल उगाएगा
देखना वह मंजर भी आएगा ।।
राह में कितने दर्द मिले,
कभी नरम कभी मौसम तक सर्द मिले,
तूने सबसे निभाया तू मुस्कुराते कभी पतझड़
कभी सावन से दोस्ती कर सबको हमदर्द बनाया
ज़माना तेरी मिसाल दे,
तेरी फ़तह का शोर मचाएगा,
देखना वह मंजर भी आएगा ।।

अभिषेक मणी
क्षे.का., बेंगलूरु उत्तर

मेरे सपनों का भारत

आज़ाद हैं हम,
75 साल के आज़ादी की धरोहर को लेकर
मन में समाये ख्वाबों को लेकर
आज़ाद हैं हम, आज़ाद हैं हम
सशक्त मौलिक अधिकारों के सहित
विविधता में एकता की शक्ति
सशक्त सेना, कृषि व विज्ञान
उन्नति के राह में अग्रसर हैं हम
नयी चुनौती नए संकट
आते जाएंगे पर हरा न पाएंगे
अपनी समझदारी और विवेक से
नए अवसर तराशते जाएंगे
उसी पुराने उद्देश्य को लेकर
सर्व सम्मान और अधिकार
संयुक्त राष्ट्र के आग्रह से
स्थापित है शून्य भेदभाव दिवस
वार्षिक प्रथम मार्च की तारीख को
है एक वैश्विक प्रयास
उद्देश्य है अधिकारों की रक्षा
और महिला सशक्तीकरण की
देना है चुनौती भेदभाव को
करने असमानता की हार
व्यक्तियों की जाति, धर्म, या सामाजिक पृष्ठभूमि
की परवाह किए बिना
सहिष्णुता, विविधता और समान अधिकार
प्यारा हमारा भारत देश
विशाल सांस्कृतिक विविधता वाला देश
शून्य भेदभाव की भावना
हो सर्वोपरी एक ही कामना
यह एकता का दिन होगा
प्रतिबद्धता की भावना में
राष्ट्र के लिए जो मूल्य लाएगा
सिर्फ वही स्वीकार्य होगा
समानता होगी आधारशिला
सभी नीतियों व संस्थानों की
होगी सुनिश्चित सर्वोपरी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार
आइए करें इसी उदेश्य से यह उद्यम
हर भारतीय करे मूल्यों की पहचान
सदा रहे भेदभाव मुक्त भारत और
कहते रहे आज़ाद हैं हम.

संदीप कुमार खूंटिया
सीआरसी, केंका

Yes, I am .....

Yes, I am a mortal in flesh and blood
In the world of mortality.
Yes, numerous wishes I have
For long nurtured in my heart
Unfulfilled, unattained, yet alive.
Yes, my ways are biased,
Some I love, others I don't
Can't afford a place for them
in that soft corner.
Yes, I am late to some places
And do have pleasant reasons for that.
My feet assert my presence
I cannot tread lightly.
Yes, I shudder in fear,
When adversities chafe me hard.
I love to live in the moment,
When nuzzled by happiness.
Yes, I succumb to failures
Success turns me haughty
But can't hold, both of them long.
Yes I am.....
Fair, dutiful, timely, fearless,
obstinate.

Arti Sharma
Zonal Office,
Bhopal

The Mermaid

Why do I love the Sea more than ever?
Is it the sound of the waves
embracing the shore,
which resembles chuckle.
Is it the sunset on the horizon,
which resembles a shining nose-ring,
I have started loving the Sea,
because I've started to see a face,
the face of a Beautiful Mermaid.

As we sail across the oceans,
with you on the bow of this boat,
through the blues of the dawn and
twilight of the dusk,
I feel tranquility surrounding us.
Even in the midst of rough tides,
I feel a calm sea inside.

You spoke of a glorious palace,
beneath the green of this sea-
A world so mesmerizing,
You told me it was a paradise,
But oh my beautiful mermaid,
How could you not see
the twinkle in my eye,
the life in my smile?
How could you not hear
the rhythm of my Heart,
This moment as I look into your eyes,
I see paradise, my Mermaid.

Deepak Jayakumar
RLP Ernakulam

A Road of Dreams

A winding road,
stretching far and wide,
Adventure awaits,
with each stride.
Footsteps echo on pavement's embrace,
Guided by dreams,
with purpose and grace.

The road whispers stories
of those who've passed,
Leaving imprints,
memories that last.
A pathway connecting hearts and minds,
Unveiling treasures,
secrets it finds.

Underneath the sun
or shimmering moon,
The road is a companion,
a comforting tune.
It leads us forward,
beyond what we know,
Inviting us to explore,
to freely grow.

With each turn,
a new horizon unfolds,
Unveiling wonders,
tales yet untold.
The road, a canvas,
where dreams take flight,
A passage to discover our inner light.

So let us journey, hand in hand,
On this road,
where destinies expand.
Together we'll walk,
through highs and lows,
Sharing the road,
wherever it goes.

N Durga Prasad Jidugu
FGMO – Vijayawada

Agricultural Trends

Introduction: The contribution and dependence on agriculture has drastically come down in developed nations, however agriculture still plays a crucial role in the development of the Indian economy.

In our country, the share of agriculture in national income has come down since the beginning of planning era in the economy. However it still has a substantial share in the country's Gross Domestic Product/Gross Value Added (GDP/GVA). The contribution of agriculture and allied sector activities in GDP, which was 55.4 per cent in 1950-51, now stands substantially reduced to only around 18 %. This sector provides livelihood to about 70 per cent of the total population and generates employment for 54.6 per cent of the country's work force.

The Government of India has initiated several policy measures to improve the accessibility of farmers to the institutional sources of credit. The emphasis of these policies has been on progressive institutionalization of credit for providing timely support to all farmers. The particular focus being on small and marginal farmers and weaker sections of the society to enable them to adopt modern technology and improved agricultural practices for increasing agricultural production and productivity. The Policy lays emphasis on augmenting credit flow at the ground level through credit planning, adoption of region-specific strategies and rationalization of lending policies and procedures.

The face of agriculture banking has been evolving over the years as technology and the agricultural sector itself continue to advance. Some of the key changes and top 10 trends in agriculture banking are:

Precision Agriculture Financing: Precision agriculture finance refers to the financial aspects and considerations involved in implementing and adopting precision agriculture technologies and practices in the agricultural sector. Precision agriculture, also known as smart farming or precision farming, involves using advanced technologies such as GPS, remote sensing, data analytics, and automation to optimize agricultural processes and increase productivity.

Precision agriculture finance involves careful financial planning, analysis, and risk management to evaluate potential benefits and costs associated with implementing these practices. Farmers can make informed decisions and optimize their financial outcomes in adopting precision agriculture technologies.

Data-driven Lending: With the availability of vast amounts of data, agriculture banks are using data analytics and machine learning algorithms to assess creditworthiness and make more informed lending decisions. By analyzing factors such as historical crop yields, weather patterns, market prices, and farming practices, banks can evaluate the risks associated with agricultural loans better and provide tailor-made financial solutions to farmers.

FPO (Farmers Producers Organisation): Currently a favourable trend being evidenced within the rural economy is that the share of income from non-farming activities has been increasing. Since agriculture forms the resource base for a number of agro-based industries and agro-services, it would be meaningful to view agriculture not as farming alone but as a holistic value chain, which includes farming, aggregating, processing, warehousing (including logistics) and retailing. Parallelly on the demand side, with rapid urbanisation and income growth in the country, there is an increasing dietary transition from cereals to high value processed foods, fruits, and vegetables. In addition, there has now been a shift of focus to nutrition and food safety. Further, the growing integration of global economies presents an opportunity for increased vertical and horizontal integration of production clusters in developing countries with the global consumption market. India, as one of the leading global producers of many fruits and vegetables, has immense potential to benefit from such integration.

Collaboration with Agri- Tech Startups: Agriculture banks are collaborating with agricultural technology startups (Agri-Tech) to leverage emerging technologies for the benefit of farmers. Such partnerships facilitate

the development of innovative financial products and services tailored to the specific needs of the agricultural sector. For example, banks may partner with Agri-Tech companies that provide farm management software, remote sensing technologies, or supply chain optimization solutions to streamline processes and improve farm profitability.

Agri-Value Chain financing: Agri-Value Chain comprises of a set of activities connected with managing inputs, production, infusing technology, post-harvest management, value addition by processing, marketing, financing, exports, mitigating risk, etc., so as to deliver commodities, goods and services in a desired form from the place of their primary production to the end consumers through a sequential set of incremental value addition stages and other related services. An agriculture value chain encompasses three main activities, viz.,

- supply/production;
- processing or manufacturing;
- marketing/distribution and consumption.

Crop Insurance Integration: Crop insurance plays a crucial role in mitigating the financial risks faced by farmers due to unpredictable weather conditions and market fluctuations. Agriculture banks are collaborating with insurance providers to offer integrated solutions that combine financial products and crop insurance. This integration helps farmers manage risk effectively and provides them with comprehensive support in case of crop loss or damage.

Poly House / Green House: Farming by use of poly house/greenhouse technology under protected controlled environmental conditions under the concept of Controlled Environmental Agriculture (CEA) which not only provides fresh vegetables, fruits, flowers but also gives high yields, increased income leading to the better nutritional and improved standard of living. Here tecnologiacal factors like temperature, humidity, soil and fertilizers, etc. are manipulated to get high quality products with maximum productivity. The protected cultivation technology creates a favorable environmental condition to sustain the growth of crops even in adverse climatic conditions. At present, there is a huge demand for quality products in the market which favor adopting maximum utilization of the technology.

Sustainable Financing: Agriculture banks are increasingly focusing on sustainable financing options. They offer discounted interest rates or specific loan programs for farmers adopting environmentally friendly practices such as organic farming, water conservation, or renewable energy use. Sustainable financing aligns with changing consumer preferences and regulatory requirements, providing incentives for farmers to adopt more sustainable agricultural practices.

Financing for Food & Agro processing units: A strong and dynamic food processing sector plays a vital role in reduction in the wastage of agricultural produce, promoting diversification & commercialization of agriculture, generation of employment and enhancing income of farmers. Considering the importance of the Agro & Food Industry in our economy, RBI has classified it under Agriculture. Loans for food and Agro -processing up to an aggregate sanctioned limit of Rs.100 crores per borrower from the banking system are classified as Agriculture. Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) is the agency for formulation and implementation of the policies and programs for the food processing industries. It has also launched a special scheme for promotion of Mega Food Parks in the country.

Agriculture drones: Agriculture drones, also known unmanned aerial vehicles (UAVs) are specifically designed for use in agriculture and farming practices. These drones are equipped with various sensors, cameras, and other technologies to gather data and perform tasks related to crop monitoring, irrigation management, and crop spraying, among other agricultural activities.

We may conclude that the changing face of agriculture banking involves leveraging technology, embracing sustainability, and providing holistic support to farmers beyond traditional financial services. These developments aim to empower farmers, enhance productivity, and enable sustainable and profitable agriculture.

The shift driven by the need for increased productivity, resource efficiency, environmental sustainability, and meeting evolving consumer preferences. As agriculture continues to evolve, it is crucial to strike a balance between productivity, profitability and the preservation of natural resources for a sustainable and resilient future.

Deepak NS
ULA, Rural & FI Hyderabad

Inclusive Banking and Economic Development

The role of the financial system in the inter-linked processes of economic growth and development is theoretically and practically well-established. Theories of economic growth like the much celebrated Harrod-Domer model establish a direct link between the growth rate of savings and the potential rate of economic growth in any economy. Richard Nelson identifies the slow growth rate of savings in under-developed countries, as caused by the absorption of an increase in national income by its population growth, as one of the greatest impediment in the growth process of these countries. Nelson describes this situation as 'developing countries being caught in a low level equilibrium trap'. Scarcity of financial resources increases the cost of borrowing and thereby discourages productive investment which in turn adversely affects the growth prospects of the country. By mobilising savings from surplus units in the economy and channelizing them for the purpose of productive investment financial intermediaries like banks, insurance companies, mutual funds and other non-banking financial companies (NBFCs) play a central role in the process of economic growth. However, in order to ensure that this quantitative growth in national income translates into a qualitative rise in living standards of the country's residents, the percolation of the direct and spill-over benefits of growth to all cross-sections of society and economy is imperative. Therefore when banks mobilise savings, apart from the quantum, its sources are also equally important. Similarly, on the lending and investment front, apart from the productivity and quantum concerns, the avenues are also important. A case in point is the situation of institutional finance in the agricultural sector of the Indian economy in the immediate post-independence period. The constitution of banks was mainly private in nature and they operated with the primary if not exclusive objective of profit-maximisation. This resulted in the concentration of banking services to trade and commerce in urban areas leaving the vast rural areas largely un-served. It is estimated that a meagre 7% of the credit requirement of agriculture and the rural economy was financed by institutional sources of credit in 1951. This implied that the remaining 93% of rural credit had to depend on non-institutional and informal sources of finance. Correction of this situation was necessary for both, achievement of the goal of financial inclusion and also for supporting the government's endeavour to undertake large-scale development projects in areas like infrastructure, mining and manufacturing as envisaged in the 5-year plans. This may be seen as the motivation for nationalisation of the Imperial Bank of India to form the State Bank of India in 1955 , the State Bank Group in 1959, of 14 major scheduled commercial banks in 1969 and a further 6 commercial banks in 1980. The establishment of Regional Rural Banks (RRBs) in 1975 and the introduction of priority sector lending norms that mandated the allocation of at least 40% of aggregate net bank credit (ANBC) to sectors designated as priority sectors in 1972 may also be seen

as a part of public policy to bring hitherto marginalised groups into the folds of the formal economy.

The contribution of public sector banks to achievement of the goal of financial inclusion has been noteworthy. Adherence to priority sector lending norms have ensured a steady flow of funds to designated socially and economically weaker sections of society as also to sectors deemed to be crucial from the viewpoint of nation-building. By mobilising savings across the lengths and breadths of the country and making them available for socially significant sectors like infrastructure development, agriculture and capital-intensive industries, banks have made a noteworthy contribution to long-term physical and social capital formation and thereby to the process of economic development.

While the goal of financial inclusion has ranked high on the priority list of public policy since independence, it has received a major thrust in recent years due to some specific measures taken by the current dispensation. Some of these initiatives may be highlighted here.

The Government emphasized the need to expand the reach and coverage of banking to the poor and those who have been unable to engage in formal banking due to various reasons among others, the lack of officially valid documents. The launch of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) on 28th August 2014 sought to enable people without documents generally accepted as proof of residence and identity by banks to fulfil Know-Your-Customer (KYC) requirements to open accounts with relaxed documentation and simplified procedures. Though these basic savings bank accounts provide limited facilities and placed ceilings on the number and amount of money that can be deposited and withdrawn from the account, their impact was significant. Accounts opened under the aegis of the PMJDY have been instrumental in incorporating a vast section of society that was earlier unable to access banking channels into the fold of formal banking. An overdraft of Rs. 5000/- that was available on Jan Dhan accounts was an additional facility that provided a small amount of credit to these account-holders. By mobilising resources and making them available for productive investment, banks have made a significant contribution to the investment scenario of the economy. Another mention-worthy benefit of the PMJDY campaign is that as part of the Jan Dhan Aadhar Mobile (JAM) trinity it has formed the basis for effective and transparent roll-out of direct benefit transfer (DBT) mechanism. Under this system transfer payments like subsidies, implementation of interest subvention schemes, payment of Government scholarships etc. are credited directly to the bank accounts of the target beneficiaries without human or systemic intervention. This has helped in checking financial misappropriations and incidences of corruption. The aim of re-allocation of resources by the state to reduce income inequalities has now become a reality. Therefore, it would be appropriate to suggest that the PMJDY programme has contributed to the goal of financial inclusion in a direct way. Through its positive externalities like mobilisation of small savings and role in the DBT programme it has made a noteworthy contribution to the macro-economic goals of economic growth and reduction in income inequality and thereby to economic development.

While inclusion on the deposit front has been attempted through the PMJDY, introduction of the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) needs to be seen as an attempt to engineer inclusion on the lending front. It has been a common experience in the Indian economy that several aspiring entrepreneurs have not been able to translate their dreams into reality due to financial constraints aggravated by their inability to borrow funds from institutional sources like banks due to lack of collateral. On their part banks too have been hesitant to finance projects that may not appear financially viable, perhaps rightly so in view of the concerns related to maintenance of asset quality. This has acted as an impediment in the expansion of the private business sector and in giving space and environment to entrepreneurs to realise their full potential. By making finance available to aspiring entrepreneurs without collateral security or third party guarantee with reasonable margin requirements upto Rs 10 lakhs, the PMMY gives tremendous scope for entrepreneurs to organise business and generate income and to that extent it has emerged as an alternative source of livelihood. Since these advances are covered under the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) the inhibitions on the part of bankers are also taken care of. While it may appear that the primary borrowers under the PMMY are also the primary beneficiaries of the scheme, the fact remains that its spill-over benefits for society and the economy are tremendous. It has directly contributed

to reduction in unemployment. It has helped crores of borrowers and their families to experience an upward movement in their household income level and thereby in their living standards.

Another initiative aimed at engineering social and economic inclusion is the start-up India and stand-up India programme. Launched in January 2016, both these programmes are different in their nature and orientation but ultimately have a common objective to provide a boost to entrepreneurial abilities in the country and generate growth. Start-up India aims at providing a conducive environment for start-ups (defined as businesses that are engaged in production of innovative goods or provision of innovative services that are not more than 10 years old since their date of establishment and have not crossed the Rs 100 crore turnover mark) through tax holidays and other relaxations. Stand-up India aims at providing opportunities and financial assistance on soft terms to members of designated socially and economically backward communities and women entrepreneurs for undertaking green-field projects. By acting as an effective instrument for socio-economic mobility these initiatives, (that are mainly routed through the banking sector,) have benefitted not only the primary borrowers but also their spill-over benefits have been felt by society and the economy at large.

Mention may also be made here of the role played by banks in economic stabilisation during the turbulent times of the pandemic. Banks acted as instruments through which relief measures like the guaranteed emergency credit line aimed at providing additional credit to already existing borrowers on soft terms were rolled out by the government. Similarly initiatives like the Pradhan Mantri Swanidhi Yojana (PMSY) that aimed at providing small loans to street vendors were also routed through the banking sector. The quantum of these loans was meagre but their consequences were significant as they served as capital for a section of society that found itself in an extremely vulnerable position during lockdowns.

Extension of the benefits of insurance cover to members of the low income groups has also been a major challenge for policy-makers. Schemes like the Pradhan Mantri Jeewan Jyoti Yojana (PMJJY), the Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojana (PMSBY) and the Atal Pension Yojana (APY) have been introduced by the government to bring members of the low income groups within the folds of insurance. By serving as a medium, banks are playing a noteworthy role in financial inclusion on the insurance front as well. Correspondingly, funds generated through subscription to these schemes are made available by banks for investment in sectors central to socio-economic development.

The field of education entails positive externalities for society at large over and above the benefit accruing to the individual student and is therefore considered to be a vital pillar of economic growth, economic development and needless to say, human development. Education loans that are provided by banks on extremely soft terms with respect to moratorium extended, provision of subsidy, repayment tenure, margin requirements and requirement of collateral security serve as powerful instruments of socio-economic mobility. Similarly, the housing sector is considered as a vital driver of economic activity through its strong backward and forward linkages with other sectors of the economy. Housing loans that constitute an important constituent of banks' retail portfolio play an important role in stimulation of the sector. The launch of the Pradhan Mantri Awaas Yojana (PMAY) in June 2015 has provided a major boost to the sector, helping aspiring Indians to purchase housing units with reduced financial liabilities because of the interest subsidy provided therein. Education and housing loans undoubtedly make a significant contribution to achievement of the goals of social and financial inclusion and thereby to growth and development.

India has made major strides on these fronts and has registered significant achievement so far. This brings in a thought that would get every aspirational Indian interested- Isn't it a real possibility that in a few decades from now the world would discuss, research, analyse and emulate the Indian model of inclusive development? Likewise, every dedicated banker would imagine that the sector's contribution to this model would serve as an example for the global financial system to internalise the reality that there may not actually be a trade-off between achievement of social goals and of cardinally measurable economic goals.

Dr Kalyanlakshmi Chitta
RO., Greater Pune

Contribution of Personal Banking in Economic Growth

When we talk about the economy the first thing that comes to mind is industry. We associate industrial growth with economic growth. It is understandable as industries generate significant revenue for a nation. These are the suppliers of various goods & services but industries can't function if there is no demand for their products.

As industries drive the supply, consumers drive the demand. An economy cannot sustain if a balance is not maintained between supply and demand. For sustained growth we have to increase our supply and we need to be able to utilize these produces effectively. Over supply with limited demand causes value minimization, which negatively affects an economy. For a prosperous economy we must empower consumers and supplement an efficient supply with a healthy demand. Personal banking plays a key role in this aspect.

Personal banking commonly referred to as retail banking directly deals with individuals. The origin of personal banking dates to 1834, with the introduction of savings bank account. People were given an alternative to safely keep their excess funds with the bank, earning interest income in the process. Over the years the scope of personal banking has widened significantly. Today we cater to various needs of an individual customer starting from savings to investments & finances.

The concept of savings bank has undergone several changes and at present is much more than just keeping excess funds. Banks provide a wide range of facilities bunched with accounts like debit cards, mobile banking, internet banking, UPI etc. with the ease of carrying funds and spending. Now with debit cards, UPI & mobile banking the process for transfer of funds is easy. Further introduction of POS machines, payment through QR code, through UPI, AADHAR enabled payment has made it easy to shop. Even small retailers, vegetable vendors are now equipped with QR based payment system. This ease of transactions has resulted in huge growth in spending by individual customers. This is evident from the rapid growth in UPI transactions over the year.

Another important aspect of personal banking is building wealth of individuals. With the introduction of FDs & RDs banks encourage individuals to keep their surplus funds with them and pay good amount of interest on such deposits. This has helped individuals build wealth and banks receive funds for lending. Banks offer a wide variety of investment options ranging from traditional investment options like FDs, RDs & traditional investment plans through bancassurance to more aggressive investment options like Mutual Funds. With the advent of digitization, access to equity market has become easy and banks have taken advantage of the same by offering DEMAT services to their customers. With all these options at their disposal, consumers can invest their money for maximum return. This adds to the regular income of an individual consumer and improves his/her financial standing thus enabling him/her to spend more.

Apart from all these banks directly enable consumers to spend more by providing financial help by way of loans. Retail loans also known as consumer loans are extended for consumption purpose. Whether it is the need for a house or the desire for a car or the need for higher studies banks provide loans to individuals to fulfil their needs. Banks even extend clean loan facilities and credit card facilities to the public, purely for consumption purpose. These loans enable consumers to spend higher amounts, which would otherwise have not been possible for the consumers. This is evident from the fact that automobile sector has seen great growth after banks started providing retail vehicle loans. Today around 80% of SUVs and cars are purchased through bank finance, around 50% of the two-wheelers sold are through finance. Since banks have started giving housing loans, we have seen a boom in the real estate sector. The above are only a few examples of how personal banking has augmented the spending capacity of individual consumers.

Personal Banking plays a role in uplifting demand by enabling the public to spend more and improved demand causes industries to produce more. This interplay of demand and supply is the engine that drives growth of an economy. While wholesale banking fuels the business, personal banking is the fuel that drives consumers.

Debashis Mishra
Zonal Office Hyderabad

Government Schemes for Upliftment of Small Businesses

Small businesses are the backbone of the Indian economy, contributing significantly to employment generation, innovation, and overall economic growth. Small Business plays a crucial role in creating job opportunities, fostering innovation and promoting local economic growth. With 45% contribution of manufacturing products and 40% of the country's export, their role is pivotal for GDP. They act as suppliers for large businesses and help create a vibrant and diverse economy, generating employment opportunities, promoting entrepreneurship and developing rural communities.

Recognizing the importance of small businesses, the government has implemented various schemes and initiatives to support their growth and development. These schemes aim to provide financial assistance, access to markets, and technical support to small businesses across different sectors.

The diverse government schemes for uplifting of small business may be summarized as below:

MUDRA Yojana: The Pradhan Mantri MUDRA Yojana (Micro Units Development and Refinance Agency) was launched in 2015 to provide financial support to micro and small enterprises. Under this scheme, small business owners can avail of loans up to Rs. 10 lakhs through various financial institutions. The loans are classified into three categories: Shishu (up to Rs. 50,000), Kishore (Rs. 50,001 to Rs. 5 lakhs), and Tarun (Rs. 5,00,001 to Rs. 10 lakhs). MUDRA loans have enabled small businesses to expand their operations, purchase equipment, and increase their productivity.

Stand-Up India: Launched in 2016, the Stand-Up India scheme focuses on promoting entrepreneurship among women and individuals belonging to Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs). Eligible borrowers can avail of loans ranging from Rs. 10 lakhs to Rs. 1 crore for starting greenfield enterprises. The scheme also provides support in the form of handholding assistance in business plan preparation and credit guarantee.

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE): The CGTMSE scheme was introduced to facilitate easy access to credit for micro and small enterprises (MSEs) by providing a credit guarantee cover for loans sanctioned under various schemes. It covers collateral-free credit up to Rs. 2 Crore to MSE units, encouraging banks and financial institutions to lend to small businesses without the need for collateral.

Start-Up India: Start-up India is an ambitious flagship initiative launched in January 2016 to foster innovation, entrepreneurship, and job creation in the country. The program aims to create a favourable ecosystem for start-ups to flourish by providing them with access to funding, mentorship, and various other support services.

As of September 2021, the Start-up India initiative had made significant strides, with over 50,000 start-ups recognized and registered under the program. These start-ups span various sectors, including technology, healthcare, finance, and more. Start-up India has played a pivotal role in transforming India into one of the world's leading start-up ecosystems, fostering innovation, and driving economic growth in the country.

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY): India's agriculture sector plays a crucial role in the country's economy. The PMKSY aims to enhance the efficiency of water use and increase the water availability for agricultural purposes. Under this scheme, farmers and small businesses involved in agriculture can access financial assistance for micro-irrigation projects, watershed development, and water storage infrastructure.

Skill India Mission: The Skill India Mission was launched to empower the youth by providing them with necessary skills that are essential for employment or self-employment opportunities. The scheme focuses on providing vocational training to individuals and aligning their skills with industry requirements. By upskilling the workforce, small businesses can benefit from having access to a skilled and productive workforce.

Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP): The Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a significant initiative launched by the Government of India to foster entrepreneurship and generate employment opportunities across the nation. Launched in 2008, the programme operates under the guidance of the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). PMEGP aims to promote self-employment through the establishment of micro-enterprises and small businesses. The programme targets both urban and rural areas, focusing on empowering individuals belonging to economically weaker sections of society and promoting inclusive growth.

The key feature of PMEGP is its financial support mechanism, where eligible entrepreneurs can avail of subsidized loans to set up their ventures. PMEGP has proven to be a catalyst in promoting entrepreneurship, driving economic growth, and creating employment opportunities, thus contributing to India's overall development and poverty alleviation efforts. By supporting small businesses, PMEGP plays a vital role in uplifting local communities and empowering aspiring entrepreneurs to realize their dreams.

Udyog Aadhar Registration: This is a government initiative that simplifies registration process of micro, small and medium enterprises which offers scheme for single window registration allowing entrepreneurs to register business online without any paperwork.

Atal Innovation Mission: This is a government scheme which aims at promoting innovation and entrepreneurship. Scheme offers financial assistance, mentorship and other resources to start ups and entrepreneurs working on innovative projects.

Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi): PM SVANidhi (Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) is a government scheme launched in June 2020 by the Ministry of Housing and Urban Affairs in India. The scheme aims to empower street vendors, who constitute a vital part of the urban informal economy, by providing them with access to affordable working capital loans to revive their businesses that may have been impacted by the COVID-19 pandemic. Eligible street vendors can avail of collateral-free loans of up to INR 10,000. The loans are disbursed through lending institutions, and vendors are encouraged to repay the loans promptly to avail higher loan amounts in the future. PM SVANidhi plays a crucial role in supporting the livelihoods of street vendors, ensuring their economic resilience, and fostering sustainable urban development. By providing access to credit and resources, the scheme aims to uplift the street vending community and enhance their contribution to the Indian economy.

The upliftment of small businesses in India has emerged as a vital driver of economic growth and social progress. Through various government initiatives, significant strides have been made in empowering aspiring entrepreneurs and fostering a conducive ecosystem for their success. The financial support and policy reforms offered to small businesses have helped level the playing field, allowing them to compete in a dynamic market environment. However, continuous efforts are needed to address challenges like access to finance, infrastructure, and skill development. By further strengthening support systems, promoting digitalization, and encouraging private sector participation, India can continue the path of fostering a thriving ecosystem for small businesses, propelling the nation towards sustainable economic development and inclusive growth.

The various government schemes have played a significant role in empowering entrepreneurs, enabling financial inclusion, and promoting economic growth. These schemes provide support in the form of financial assistance, skill development, guarantee cover, and access to markets. However, it is important for small business owners to have awareness about these schemes and actively avail their benefits. By taking advantage of these schemes, small businesses can overcome financial constraints, expand their operations, and contribute to the overall socio-economic development of India.

Sujata Rani Sahu
RO., Bhubaneswar

Importance of Green Revolution in Sustainable Development

Background: The Green Revolution is often seen as epitomising the dawn of scientific and technological advancement and modernity in the agricultural sector across developing countries, a process that unfolded from the 1950s to the 1980s. Despite the time elapsed, this episode of the past continues to resonate today, and still shapes the institutions and practices of agricultural science and technology.

For developing countries' agricultural systems, the Green Revolution is often portrayed as the advent of scientific and technological modernity, helping them to avert famines and revert food deficits. India witnessed an extraordinary period of food productivity growth from food scarcity to self sufficiency in the past 50 years despite land degradation. Although the population is rapidly growing agriculture productivity is increasing year on year. Green revolution was a state led process that involved the roll out of high yielding varieties especially rice and wheat, which were responsive to high inputs of chemical fertilizers and irrigation with the aim of intensifying the production and productivity to address the pressing concerns of hunger, poverty, social stability and industrial development. The Green Revolution remained as a legend to reverberate, inspire and influence the perspective, practices and research in agricultural sciences and technology. The call for "Evergreen Revolution" by M. S. Swaminathan in the 90's is the expression of Green Revolution revivalism.

Impact of Green Revolution:

- It helped to prevent widespread famine and provided a foundation for economic stability and social progress in many developing countries
- In addition to fostering social equity, its emphasis on technological innovation paved the way for further advancements in agriculture and beyond
- The development and adoption of high-yielding crop varieties laid the foundation for subsequent research and engineering efforts, such as genetic modification and precision farming techniques
- These advancements have allowed for more sustainable and efficient agricultural practices, reducing the need for harmful pesticides and fertilizers, optimizing resource utilization, and minimizing environmental impacts
- By embracing innovation and science, the Green Revolution fostered a mindset of continuous improvement
- Another significant impact of the Green Revolution was its contribution to global environmental awareness

Green Revolution opened windows to look for Sustainability in development:

- As agricultural practices intensified, concerns about the environmental consequences of increased chemical usage, eutrophication, chemical residues in the agricultural produce, soil health, land degradation and contribution of agriculture to climate change through green house gases such as methane began to emerge. The recognition of the negative impacts prompted a shift towards more sustainable farming methods, including organic agriculture; natural farming and concept of agroecology took another shape in the developing world towards sustainability.
- The Green Revolution served as a catalyst for recognizing the importance of sustainable land management, biodiversity conservation, and ecosystem protection along with food safety. It helped in initiating conversations and actions around sustainable development, leading to the formulation of environmental policies and the establishment of global frameworks like the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).
- It fostered international collaborations and knowledge sharing. Scientists, policymakers, and experts from different countries came together to exchange ideas, best practices, and technologies. These collaborations helped to bridge the knowledge

gap and facilitated the transfer of agricultural innovations to developing regions, where they were most needed. The Green Revolution demonstrated the power of global cooperation in addressing complex challenges and laid the groundwork for future collaborative efforts in sustainable development.

Need for Sustainable Development with Sustainable Development goals: The negative environmental impacts associated with intensive agriculture and the unequal distribution of its benefits across regions and communities highlights the importance of finding a balance between productivity, environmental stewardship and food safety. This recognition has led to the emergence of concepts like sustainable intensification, circular economies, and regenerative agriculture, which builds upon the lessons of the Green Revolution while addressing its shortcomings.

New chapter of Green Revolution:

Agriculture, being a fundamental pillar of human civilization, plays a crucial role in sustainable development. By adopting sustainable practices in agriculture, we can ensure the preservation of natural resources, protect biodiversity, and promote food security for future generations.

- A modern Green Revolution seeks to increase agricultural productivity while minimizing negative environmental impacts. Sustainable agricultural practices, such as precision farming, integrated pest management, and organic farming can reduce the reliance on chemical inputs and promote ecosystem health.
- By employing agroecological principles, farmers can optimize resource use, conserve soil fertility and reduce water pollution. Additionally, the use of advanced technologies, including remote sensing, drones and data analytics can provide real-time monitoring and decision support, enabling farmers to make informed choices for sustainable productivity enhancements.
- Sustainable land management practices like agroforestry and conservation tillage help prevent soil erosion, maintain soil moisture and preserve biodiversity, contributing to the long-term sustainability of agricultural systems.
- Monoculture farming, a hallmark of the earlier Green Revolution, often led to the loss of biodiversity and the emergence of pests and diseases. By adopting diversified cropping systems, intercropping, and integrated pest management, farmers can enhance biodiversity on their lands while reducing the need for chemical inputs. Protecting and restoring natural habitats, such as wetlands and forests, adjacent to agricultural areas can also provide vital ecosystem services, including pollination, pest control, and water regulation.
- The modern Green Revolution must address the challenges posed by climate change. Developing climate-resilient crop varieties, employing agroforestry systems, and practicing sustainable water management can help farmers adapt to changing climatic conditions. Moreover, sustainable agriculture contributes to climate change mitigation by sequestering carbon in soils, reducing greenhouse gas emissions from agricultural activities, and promoting the use of renewable energy sources on farms. These actions can significantly contribute to global efforts to combat climate change.
- Agriculture should prioritize the well-being of small-scale farmers, rural communities, and consumers. Promoting equitable access to resources, empowering women in agriculture, and enhancing agricultural education and training can foster inclusive and sustainable development. Additionally, strengthening local food systems, promoting fair trade practices, and minimizing post-harvest losses can enhance food security, reduce food waste, and improve livelihoods.

Conclusion: As said by Nobel laureate and father of Green Revolution Norman Borlaug "You can't build a peaceful world on empty stomachs and human misery". Sustainable development offers a roadmap for building a thriving future where environmental stewardship, social equity, and economic prosperity and food safety coexist harmoniously. By embracing sustainable practices and making conscious choices, we can create a more resilient planet for current and future generations. It is our collective responsibility to take action now.

We can achieve a harmonious balance between agricultural progress and environmental stewardship. To realize this vision, collaboration among farmers, policymakers, researchers, and consumers is essential. By collectively working towards a sustainable Green Revolution, we can ensure a prosperous future that nourishes both people and the planet.

Lalita Hanabar
ULA, Rural & FI, Hyderabad

Digital Transformation for Eco-Innovation

Businesses are increasingly focusing on sustainability and eco-innovation to reduce their environmental impact while remaining profitable. They are embracing digital transformation to unlock new revenue streams and drive sustainable growth.

Sustainability emphasizes integrating environmental, social, and economic considerations into business strategy, recognizing that long-term profitability and competitive advantage are linked to addressing sustainability challenges and promoting eco-innovation. Eco-innovation involves developing and implementing new products, services, processes, and business models that contribute to environmental sustainability and resource efficiency. It encompasses practices like renewable energy, circular economy, green supply chain management, and sustainable product design. By embracing eco-innovation, the business can minimize its environmental footprint, discover new revenue opportunities, and gain a competitive edge. Digital transformation is the integration of digital technologies into all aspects of a business, fundamentally changing how organizations operate and deliver value to customers. It plays a crucial role in enabling eco-innovation by leveraging advanced tools and technologies to optimize processes, improve decision-making, and enhance overall business performance.

Implementing digital transformation and eco-innovation can be challenging. Organisations often struggle to determine which actions have the most impact and which investments generate the most value. Therefore, is important to assess the returns on investment and identify the actions that drive significant results.

Finding profitability in sustainability is a strategic approach that combines environmental responsibility with revenue generation. It enables businesses to thrive in today's competitive landscape. By leveraging digital transformation for eco-innovation, companies can unlock new revenue streams, improve operational efficiency, and contribute to building a sustainable future for their business and the planet.

Some measures by which digital transformation can support eco-innovation and drive sustainable business growth are:

i. **Data-driven insights:** Digital transformation allows businesses to collect, analyze, and interpret large volumes of data from various sources, such as sensors and customer interactions. By harnessing data analytics, organisations can gain valuable insights into their environmental impact, resource consumption, and customer preferences. These insights inform the development of innovative products, services, and processes that promote sustainability and generate new revenue streams.

ii. **Automation and process optimization:** Digital transformation drives efficiency and reduces resource consumption through the automation of manual processes and the optimization of workflows. Robotic process automation (RPA) minimizes errors and eliminates time-consuming tasks, freeing up employees for eco-innovation. Advanced manufacturing technologies, like 3D printing, reduce material waste and energy usage, leading to more sustainable production processes.

iii. **Enhanced collaboration and communication:** Digital transformation enables seamless

collaboration and communication across teams, departments, and geographical boundaries. Digital tools and platforms foster a culture of innovation and knowledge sharing, allowing employees to collaborate on eco-innovative projects. Digital communication channels engage customers, suppliers, and stakeholders for feedback, market insights, and continuous sustainability improvement.

iv. **Circular economy and digital platforms:** Digital transformation supports the transition to a circular economy, emphasizing resource efficiency and waste reduction. Online marketplaces and sharing economy platforms enable the monetization of underutilized assets and facilitates sustainable exchange. Embracing the circular economy could unlock significant economic value.

v. **Smart and connected products:** Digital transformation enables the development of smart and connected products that optimize resource usage, monitor performance, and communicate with other devices. Sensors, IoT technology, and AI create eco-innovative products that deliver value to customers while minimizing environmental impact, such as energy-efficient thermostats and connected vehicles.

vi. **Supply chain transparency and traceability:** Digital transformation enhances supply chain transparency and traceability, enabling effective environmental impact management. Technologies like blockchain, IoT, and AI provide real-time visibility, identify areas for improvement, and facilitate sustainable practices. Transparency builds trust with customers and stakeholders, showcasing a commitment to eco-innovation and responsible sourcing.

vii. **Virtual and augmented reality:** VR and AR technologies support eco-innovation in product design, employee training, and customer engagement. Designers can create and test eco-friendly products virtually, reducing the need for physical prototypes. VR and AR also enhance employee skills and knowledge related to sustainability, fostering an eco-innovation culture.

viii. **Artificial Intelligence and Machine Learning:** AI and ML analyze complex datasets, identify patterns, and predict trends, driving eco-innovation. Optimizing energy consumption, predicting equipment failures, and identifying waste reduction opportunities are possible with AI and ML. Personalized and eco-friendly products and services can be developed, catering to environmentally conscious consumers.

To implement profitable sustainability practices through digital transformation, businesses should adopt the following:

- **Clear Vision / Strategy:** Define the organization's sustainability goals and create a roadmap for achieving them through digital transformation and eco-innovation.
- **Culture of innovation:** Encourage employees to embrace new ideas, technologies, and ways of working. Provide them with the necessary tools and resources to experiment and innovate.
- **Invest in digital skills and capabilities:** Develop the digital skills and knowledge of employees throughout the organization. Ensure they have the expertise to contribute to eco-innovation initiatives effectively.
- **Foster collaborations with external partners:** Establish partnerships with technology providers, industry experts, and other stakeholders. These collaborations can provide access to new ideas, resources, and expertise that support eco-innovation efforts.
- **Monitor and measure progress:** Implement robust monitoring and reporting mechanisms to track the organization's progress towards sustainability goals. This helps identify areas for improvement and ensures accountability.

India's business landscape is witnessing a significant shift towards sustainability and eco-innovation as organizations recognize the need to reduce their environmental impact while remaining profitable. The integration of digital transformation in this pursuit is playing a crucial role in driving sustainable business growth.

Jeetendra Yadav
Digitalization vertical, C.O., Mumbai

उच्च कार्यपालक वेतनमान VIII में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई !

एस. वी. बीजू
मुख्य महाप्रबंधक

कबीर भट्टाचार्य
मुख्य महाप्रबंधक

उच्च कार्यपालक वेतनमान VII में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई !

गुणानंद गामी
महाप्रबंधक

जी एन वी रमणा
महाप्रबंधक

बिरजा प्रसाद दास
महाप्रबंधक

बैजनाथ सिंह
महाप्रबंधक

सी वी एन भास्कर राव
महाप्रबंधक

रेणु के. नायर
महाप्रबंधक

सत्यबान बेहेरा
महाप्रबंधक

एन. चेझियन
महाप्रबंधक

अजय कुमार
महाप्रबंधक

प्रमोद कुमार रेड्डी
महाप्रबंधक

हम आपके नेतृत्व में बैंक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं.

उच्च कार्यपालक वेतनमान VI में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई

वि रवि कुमार
उप महाप्रबंधक

पी रामनाथ दिवाकर
उप महाप्रबंधक

मार्कण्डेय यादव
उप महाप्रबंधक

अनुज कुमार सिंह
उप महाप्रबंधक

आशीष मालवीय
उप महाप्रबंधक

अमित कुमार सिन्हा
उप महाप्रबंधक

एम वी एन रवि शंकर
उप महाप्रबंधक

असीम कुमार पाल
उप महाप्रबंधक

राजेश कुमार सिंह
उप महाप्रबंधक

अजीत कुमार लालवानी
उप महाप्रबंधक

देवेंद्र कुमार चौबे
उप महाप्रबंधक

तुषार कांत कर
उप महाप्रबंधक

राजकुमार
उप महाप्रबंधक

श्वेता मिलिंद सावे
उप महाप्रबंधक

निरंजन बारिक
उप महाप्रबंधक

जावेद अहमद जाफरी
उप महाप्रबंधक

एम श्रीधर
उप महाप्रबंधक

संजीव कुमार
उप महाप्रबंधक

सुदीप्त कुमार पार्थसारथी दाश
उप महाप्रबंधक

लखविंदर सिंह पूरी
उप महाप्रबंधक

धर्मेंद्र राजोरिया
उप महाप्रबंधक

हम आपके नेतृत्व में बैंक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं.

एम वी बालसुब्रमण्यम
मुख्य महाप्रबंधक

एल के राजू
महाप्रबंधक

एस. अन्नपूर्णा
महाप्रबंधक

हरिहर पदमानभम् एम
महाप्रबंधक

आर रतीश
महाप्रबंधक

रमाकांत प्रधान
महाप्रबंधक

प्रमोद कुमार सोनी
महाप्रबंधक

आर महादेवन
उप महाप्रबंधक

नवनीत कुमार गुप्ता
उप महाप्रबंधक

के. अजय पॉल
उप महाप्रबंधक

महावीर वर्मा
उप महाप्रबंधक

नंजुंडप्पा टी
उप महाप्रबंधक

एल वासु
उप महाप्रबंधक

पी. सिंहाचलम
उप महाप्रबंधक

ए. कृष्णस्वामी
उप महाप्रबंधक

सुरेश दक्षिणामूर्ति गंजाम
उप महाप्रबंधक

हम आपके सुखद एवं सक्रिय सेवानिवृत्त जीवन की कामना करते हैं.

मेरी अभिलाषा

बचपन में माखनलाल चतुर्वेदी की कविता "पुष्प की अभिलाषा" पढ़ी थी. क्या ही हृदय को छू लेने वाले बोल हैं, पुष्प ने यह नहीं चाहा कि वह बगिया में रंगभरा खिलता रहे और आने-जाने वालों का मन मोहे. पुष्प यह भी नहीं चाहता कि वह सुन्दर बालाओं के केश की सज्जा बने, यह भी इच्छा नहीं रखता कि वह देवों के शीशों पर अर्पित किया जावे ओर अपने को गोरवान्वित महसूस करें. तो फिर क्या उसकी अभिलाषा है? "मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक".

मैं भी जीवन के अन्तिम पड़ाव में हूँ. पचहत्तर वर्ष कम तो नहीं होते.! पन्द्रह वर्ष पहले बैंक से सेवानिवृत्त हुआ कोई भी अजर-अमर नहीं हैं. सबको एक न एक दिन इस संसार से रुख़सत होना ही है. इस संबंध में मैं भी कुछ अभिलाषा रखता हूं जो आपके आत्म चितंन में शायद लाभप्रद हो.

आचार्यपद भगवान श्री शंकराचार्य प्रधान आचार्य ही नहीं बल्कि एक युगप्रर्वतक भी रहे है. उनका नाम ससांर के दार्शनिकों में सर्वअग्रणी हैं, उन्हीं की एक किताब "विवेक चूड़ामणी" से प्रभावित होकर मैंने "मेरी अभिलाषा" लिखी है. सत्संग मेरी पहली इच्छा है, मनुष्य तन दुर्लभ है, सत्संग के बिना न विवेक और न ही राम कृपा मिलती है . रामभक्त हनुमान के एक प्रहार मात्र से लंकिनी के शरीर से रुधिर की धार निकल पड़ी. उसी स्पर्शमात्र से लंकिनी को रामभक्त का अनुभव हुआ और जो लंकिनी राक्षसी हनुमान जी को चबाने व निगलने को आतुर थी, उसे भी रामभक्त हनुमान के सत्संग का अनुभव हुआ ऐसा तुलसीदास के रामचरितमानस के सुंदरकाणड में वर्णित है. लंकिनी ने सहर्ष हनुमानजी को लंका प्रवेश की आदर सहित विनती की तथा रामकार्य हेतु माँ सीता का पता लगाने में सफल होने की कामना की. मैं ऐसे ही सत्संग की अभिलाषा रखता हूँ.

परमार्थ मेरी दूसरी इच्छा है. तरुवर, संतजन सरोवर और मेह (वर्षा) इन चारों ने दूसरों की भलाई के लिए ही जीवन धारण किया है जिससे सब लोगों का भला हो सके.

सन्तुष्ट रहना भी मेरी अभिलाष है, जिसको मैं अपने जीवन में लगभग उतार चुंका हूँ.

चिन्तन करता रहूँ तथा घर, वन व श्मशान में सुख की नींद सोंऊ जैसे- मेघ आकाश का कोई संबंध नहीं है ठीक उसी प्रकार मेरे सुविचारों पर बाहरी तावों का कोई प्रभाव न पड़े.

कर्म से ही देह बनता है, अत: प्रारब्ध को भी उसी का अंग समझना चाहिए. आत्मा को प्रारब्ध मानना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा कर्मों से बनी हुई नहीं है. ऐसा तो करीब-करीब पूर्णतया मैं भी मान चुका हूं.

जैसे जग जाने पर स्वपन के कर्म लीन हो जाते हैं इसीलिए मैं भी स्वपनों से न व्याकुल होऊं और न ही प्रसन्न होऊं जीवन में मुक्ति हो, संसार वासना शांत हो, चित्त चिन्ता से विहीन हो, प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होऊं. मुझे इतना गहरा ज्ञान हो कि मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अंश समाए. मैं ही विश्व हूं और विश्व मुझ में है ऐसा अनुभव मुझे हो देह में अभिमान न हो, हर समय जागृती का अनुभव हो, सत असत में अन्तर देख सकूं ज़्यादा सुनना तथा कम बोलना जीवन का लक्ष्य हो. विषयों में प्रवृत्त न होऊं, कामनायें दूर रहें, आत्मानंद के रस का अनुभव हो, संसार का बंधन न हो, ऐसा हे परमेश्वर जीवन दे!

सूर्य के उदय होने पर अंधकार जैसे गायब हो जाता है वैसे ही वासना अहंकार आदि का अंधेरा मेरे शेष जीवन से दूर हों. किसी पर झूठा इलजाम न लगाऊं, अहंकार को सिर उठाने का अवसर न दूं. इसे जड़मूल से ही नष्ट कर दूं, संसार का बंधन कम से कम हो, मन को विद्या युक्त बनने दूं क्योंकि मन नाम का भंयकर व्याघ्र विषय रूपी वन में घूमता रहता है तथा कभी भी भ्रमित कर सकता है इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मलादि के समूह में विश्वास कर के आत्मा बुद्धि को न छोडूं .

नेत्रों को खुला रखूं, अंधापन या धुंधला दिखना नेत्रों के ही धर्म हैं. इसी प्रकार बहरापन गूंगापन इत्यादि भी शरीर के ही धर्म हैं, ये सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं. अत: इन सबसे एकसा व्यवहार करूं, विषयों की अनुकूलता से सुखी और प्रतिकूलता से दु:खी न होऊं.

सुख और दु:ख अंहकार के ही धर्म हैं, आत्मा के नहीं. चिन्ता और सुख से रहित होकर, बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहता रहूं. जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है. मैं इन सीढ़ीयों के आत्म प्रकाश से मनुष्य जीवन सफल करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है ताकि मैं जीवन रहते आत्मा के भी दर्शन कर सकूं.

महेश चन्द्र राव
सहायक महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त)

इतनी शक्ति हमें देना दाता...
बैंक का प्रार्थना गीत

प्रार्थना ज़ात, धर्म और भौगोलिक सीमा से ऊपर मानवीय जीवन में आत्मविश्वास संचार की दृश्य प्रस्तुति के साथ एक अदृश्य माध्यम है. ऐसी ही एक प्रार्थना है, "इतनी शक्ति हमें देना दाता...". यह सर्व स्वीकार्य प्रार्थना आज यूनियन बैंक के साथ बहुत सारे कॉरपोरेट कार्यालयों के सुबह की सुर गुंजन बन चुकी है. कलाश्री अवार्ड से सम्मानित गीतकार अभिलाष द्वारा रचित, जिसका संगीत कुलदीप सिंह ने दिया तथा दो बहने, 'पुष्पा और पूर्णिमा पागधारे की सुरीली आवाज से सजा यह गीत फिल्म अंकुश'(1986) की प्रस्तुति है.

वर्ष 2004 में मेरा स्थानान्तरण मध्य प्रदेश की राजधानी तथा भारत की हृदय स्थली, एक शांत और सुरम्य शहर, झीलों की नगरी भोपाल में हो गया. मैंने एक दोपहर वहाँ के अंचलीय ऑडिट कार्यालय में प्रमुख के रूप में अपनी शांतिपूर्ण दस्तक दी. हमारे कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक ने मुझे उसी दिन सूचित किया कि अंचलीय कार्यालय सुबह 10 बजे एक सुरमय प्रार्थना के साथ आरंभ होता है, जिसमें समय से भाग लेना अनिवार्य है. अगले दिन समय पर सुबह 10 बजे मैं वहाँ उपस्थित था. सभी लोग हॉल में समय से इकट्ठे हुए. पुष्पा और पूर्णिमा पागधारे की मधुर स्वर में प्रार्थना "इतनी शक्ति हमें देना दाता...", एक टेप रिकॉर्डर पर बजाया गया और साथ ही सभी लोगों ने इस कोरस में शामिल हो कर सुर में अपना सुर मिलाया. पूरा वातावरण इस मधुर सम्मिलित स्वर से गुंजायमान हो उठा. सुबह की इस प्रार्थना सत्र का निर्देशन स्वयं अंचल प्रमुख श्री वी के ढींगरा, उप महाप्रबंधक, कर रहे थे (श्री ढींगरा, यूको बैंक में ई.डी. के पद से सेवनिवृत्त हुए). प्रार्थना के बाद उन्होंने मेरा सभी से परिचय करवाया और बैंक से जुड़ी कुछ आवश्यक घोषणाएं कीं. इस प्रार्थना सभा का विचार मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि प्रार्थना के साथ कार्यालय में हर कोई अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए सुबह की ताज़गी के साथ स्वस्थ मन से इकट्ठा होकर एक निर्विकार आराधना करते थे. यह उपस्थिति और समय की पाबंदी के लिए भी एक बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था थी.

अगस्त 2005 में अपने चेन्नई स्थानांतरण पर, मैं वहाँ भी प्रार्थना सत्र शुरू कराने के लिए उत्साहित था. मेरे सविनय आग्रह पर श्री श्रीराम अय्यर, ने पूरी प्रार्थना का तमिल में अनुवाद कर दिया और उसी धुन में रिकॉर्ड किया. चेन्नई मुख्य शाखा की स्टाफ श्रीमती जयालक्ष्मी ने इसे बहुत ही मधुर स्वर में गाया था. चेन्नई में हम इस प्रार्थना का शुभारंभ वर्ष 2006 में व्यवसाय योजना सम्मेलन में किया गया.

मेरी अगली स्वतंत्र पोस्टिंग विशाखापट्टणम क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्र प्रमुख के रूप में हुई. यहाँ हमने इस सर्व स्वीकार्य प्रार्थना को प्रात: काल बैंक कार्य आरंभ के लिए किया. हमने इसकी अंग्रेजी अनुवाद का प्रिंट आउट भी लोगों को दिया, जो हिंदी के साथ सहज नहीं थे. विशाखापट्टणम में, प्रार्थना संस्कृति ने जड़ें जमा लीं और वे अब भी दिन की शुरुआत प्रार्थना और मुख्य बैंकिंग संदेश से करते हैं, जिसे मैं सेवनिवृति के पश्चात अपने दौरे के दौरान देखकर आत्मविभोर हो गया. अपने लगाए पौधे, परवरिश किए गए बच्चे और आरंभ किए गए कार्य को फलते-फूलते देखना हर इंसान को एक आंतरिक ख़ुशी प्रदान करता है.

वर्ष 2007 में मैं दिल्ली में पदस्थ हुआ. वास्तव में दुनिया गोल है. पुन: हमारी बैंकिंग प्रार्थना के जनक, श्री वी के ढींगरा, महाप्रबंधक, वहां अंचलीय प्रमुख के रूप में पहले से विराजमान थे. उनकी छत्र-छाया में इस प्रार्थना ने कॉरपोरेट प्रार्थना के रूप में अपनी जगह बनानी आरंभ कर दी थी. जब हमने दिल्ली उत्तर क्षेत्र का अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला, तो वहां भी दैनिक कार्य आरंभ से पूर्व उक्त प्रार्थना को दैनिक सम्प्रेषण के साथ आरंभ किया.

वर्ष 2008 में मैं केंद्रीय कार्यालय में उप महाप्रबन्धक के रूप में पदस्थ हुआ. प्रार्थना संस्कृति की अपनी अवधारणा लिए सर्वप्रथम मैंने 7वीं मंजिल पर प्रार्थना व्यवस्था आरंभ करने की योजना बनायी, जहां मेरा विभाग था. हमने सुबह 9.55 बजे एक कंप्यूटर पर प्रार्थना की शुरुआत की. वहां के विभाग 10 बजे काम करना आरंभ करते थे. लगभग चालीस/पचास लोग 7वीं मंजिल पर काम कर रहे थे. हमने प्रार्थना के बाद लोगों को उनके जन्मदिन और वर्षगाँठ तथा उनके बच्चों के जन्मदिन आदि पर बधाई देने की परंपरा की शुरुआत की. हर दिन एक व्यक्ति को सामान्य रुचि से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था. आपका इरादा पक्का और कार्य नेक हो तो बाधाओं को चीर कर सफ़लता मिलती ही है. इस आकर्षक प्रणाली ने अद्भुत काम किया.

मेरे अधीन सहायक सेवाएँ विभाग था, जो केंद्रीय कार्यालय भवन सहित बैंक की सभी सम्पदाओं का प्रबंधन करता है. जब मैंने वहां काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि बैंक के इस केंद्रीय कार्यालय में कई बदलावों की आवश्यकता थी, जिनमें से कुछ को सामान्य प्रयास से संशोधित किया जा सकता था. मैंने केंद्रीय कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन अभियान आरंभ किया; विषय था "हमारे कार्यस्थल को और अधिक जीवंत कैसे बनाया जाए". यह मेरी पहली सक्रिय पहल थी. हमने 19 जुलाई 2008 को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, जो शनिवार था, तीन सर्वोत्तम सुझावों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया था. साठ से अधिक प्रविष्टियाँ आयीं थीं और अधिकांश सुझाव काफ़ी उपयोगी और अनुकरण करने योग्य थे. लगभग 3 बजे, जब कार्यालय का समय समाप्त हो गया तो हमने पुरस्कार वितरण और नाश्ते की व्यवस्था की. विभिन्न विभागों के लगभग सत्तर लोग वहां एकत्रित हुए, जिनमें अधिकतर युवा बैंक कर्मी थे. वे बहुत उत्साही और काफ़ी ऊर्जावान थे. हमने अधिकांश सुझावों पर अमल भी किया था. मेरी अगली

पोस्टिंग हैदराबाद में क्षेत्र प्रमुख के रूप में हुई जहाँ प्रार्थना को शुरू किया गया और कई शाखाओं ने भी इसका अनुसरण किया.

समय का चक्र घूमता रहा और मैं वर्ष 2010 में महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति के साथ कॉर्पोरेट संचार और सहायक सेवाएँ विभागों के प्रमुख के रूप में नामित किया गया. अब वक्त मेरे मन में घूमती अधूरी इच्छाओं को केन्द्रीय कार्यालय में और भी बेहतर तरीक़े से पूरा करने का था. मेरे कार्यभार सँभालने से पहले ही अध्यक्ष के सचिव ने मुझे सूचित किया कि अध्यक्ष श्री एम वी नायर महोदय मेरे साथ पूरे केंद्रीय कार्यालय की इमारत का मुआयना करना चाहते थे.

दिन 27 दिसंबर वर्ष 2010 को अध्यक्ष महोदय ने 16वीं मंजिल से बेसमेंट तक सभी मंज़िलों का दौरा किया और हमने कार्यालयों को अधिक कुशल कार्य संस्कृति के अनुरूप और आकर्षक बनाने के लिए संभावित परिवर्तनों पर विस्तृत चर्चा की. कई बदलाव हमारे द्वारा 2008 में आयोजित अनौपचारिक प्रतियोगिता के समय प्राप्त सुझावों के अनुरूप थे. लगभग चार घंटे तक अध्यक्ष महोदय को परिसर दिखाते हुए, हमने कई बैंकिंग और सामान्य विषयों पर चर्चा की. मैंने समय की पाबंदी के लिए आज़माई हुई प्रबंधन व्यवस्था के रूप में प्रार्थना का उपयोग करने के अपने अनुभव के बारे में बताया. मेरे इस सुझाव को अध्यक्ष महोदय ने सहर्ष स्वीकृति दे दी.

तय किया गया कि 2 जनवरी 2011 से पूरे केंद्रीय कार्यालय में कार्य का आरंभ इस प्रार्थना से किया जाए. चूंकि विभिन्न मंजिलों का समय अलग-अलग था, इसलिए हमने तय किया कि प्रार्थना अलग-अलग समय पर इमारत के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर हर मंजिल पर कार्य शुरू होने के समय के अनुसार होगी. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय 1 जनवरी 2011 को सभी कर्मचारियों को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से संबोधित करेंगे और इस अवसर पर अगले दिन से प्रार्थना शुरू करने की घोषणा करेंगे. यह केंद्रीय कार्यालय और अधिकांश अन्य कार्यालयों में दैनिक प्रार्थना की यात्रा की शुरुआत थी. बैंक की शाखाओं में भी इसे धीरे-धीरे अनुकरण कर बिना किसी प्रशासनिक आदेश के स्वत: अपनाया गया.

हमारे अध्यक्ष महोदय को अपने विचारों को नोट करने के लिए पर्चियों का उपयोग करने और इसे लागू करने के लिए ज्यादातर महाप्रबंधकों के पास भेजने की आदत थी. उनकी एक फ्लाइट में वीडियोकॉन के श्री धूत उनके साथ यात्रा कर रहे थे. ऐसा लगता है कि अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अपने केंद्रीय कार्यालय और अन्य कार्यालयों में प्रार्थना के बारे में बताया होगा. श्री धूत ने शायद पी.पी.एल. के बारे में पूछा होगा. मुंबई लौटने पर अध्यक्ष महोदय ने मुझे श्री धूत के बिजनेस कार्ड के साथ पी.पी.एल. के उल्लेख के साथ एक पर्ची भेजी. पूछताछ करने पर मैंने महसूस किया कि पब्लिक परफॉरमेंस लाइसेंस (पी. पी.एल.) प्राप्त किए बिना कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र या व्यावसायिक स्थान पर कोई भी संगीत नहीं बज सकता है. यह मेरे लिए भी एक नई चौंकाने वाली ख़बर थी. यह हम सभी के लिए आंखें खोलने वाला था, क्योंकि पब्लिक परफॉरमेंस लाइसेंस प्राप्त करना एक कानूनी आवश्यकता थी. किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या सार्वजनिक स्थान या किसी भी कार्यक्रम या शो में किसी भी रूप में कॉपीराइट संगीत का संचार पी.पी.एल. के बिना प्रतिबंधित है. हमने तुरंत 100 से अधिक स्टेशनों के लिए पी.पी.एल. प्राप्त किया. हम जानते थे कि कई शाखाएँ संगीत बजा रही थीं, और सभी अंचलीय और क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ होती थी.

यह तो रही मेरी बात, लेकिन इस प्रार्थना का यूनियन बैंक से बहुत पुराना सम्बन्ध था, जिसकी जानकारी मुझे अपने पुराने मित्र श्री हरीश कुमार गुरनानी से पता चला कि.

मझगांव शाखा में कई वर्षों से इस गीत के साथ प्रार्थना की जा रही थी. किसी को नहीं मालूम कि किसने यह शुरूआत की; लेकिन सब इस प्रार्थना को सकारात्मक रूप में लेते हुए इस संस्कृति को जारी रखे हुए थे.

उन्हें सुश्री इटालिया, जो सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक और पूर्व में मझगांव की शाखा प्रमुख थी, ने बताया कि उन के समय में भी शाखा में यह प्रार्थना होती थी. काफ़ी पहले उस शाखा में एक पारसी शाखा प्रबंधक (जिनका नाम याद नहीं) ने इस प्रार्थना की अनुकरणीय परिपाटी शुरू की थी. तत्पश्चात इसे 2003 में क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण में आरम्भ किया गया.

बाद में इस प्रार्थना की बात तत्कालीन अध्यक्ष श्री लीलाधर जी के संज्ञान में आने पर उन्होंने भी इसे पसंद किया और केंद्रीय कार्यालय के साथ-साथ सभी स्टाफ़ प्रशिक्षण केंद्रों को हिदायत दी गयी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत इस प्रार्थना के साथ करें. यह शायद उनकी पहल का नतीजा था कि यह प्रार्थना बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों में आरंभ की गयी और इसे और लोगों ने भी अपनाया.

इस प्रकार, जबकि मैं श्री वी के ढींगरा जी को अपने बैंक में प्रार्थना के जनक के रूप में मानता हूं, पर शायद मझगांव शाखा के वह गुमनाम पारसी शाखा प्रबंधक इसके वास्तविक जनक हों. मैंने तो बस उनकी दूरदर्शिता-पूर्ण पहल को विस्तारित करने में मदद की और एक विशाल स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसे बढ़ावा दिया. मैं बैंक के बड़े होने, अर्थपूर्ण प्रार्थना के कई और क्षेत्रों तक पहुंचने तथा बैंक के तमिलनाडु प्रतिष्ठानों में कॉर्पोरेट गान के तमिल प्रतिपादन के पुनरुद्धार की आशा करता हूं.

"प्रार्थना मांगना नहीं है. प्रार्थना स्वयं को परमेश्वर के हवाले करना है, और हमारे हृदय की गहराई में प्रार्थना की वाणी को सुनना है."

- मदर टेरेसा

एस. आफ़ताब
महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त)

First Fiscal Budget of Amrit Kaal - An Analysis

In the first budget of Amrit kaal the government has reached out to various sections- be it farmers, the salaried, the tax harried middle class or the poorest of the poor. The country's resilient recovery from the pandemic has offered an opportunity to make all engines of growth press ahead at full steam.

The government has reposed faith in capital expenditure, whose outlay has been increased by 33 per cent to Rs. 10 lakh crore. The focus is on greater spending and making India more attractive for investors in the post Covid period.

Amid a global slowdown, India has already emerged as the world's fastest growing major economy and it is imperative to maintain the momentum. The government is hopeful that investments and job creation go hand in hand. The same was stated by famous economist John Maynard Keynes in his famous 'Theory of Income and Employment'. He believed that more of capital expenditure created more of employment.

The budget has listed seven long-term priorities such as inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing potential, green growth, youth power and the financial sector.

The proposed creation of the agriculture accelerator fund to help agri start ups shows that the Centre is heavily banking on the time tested farming sector for economic dividends. The allocation of Rs. 35,000 crore for the transition to green fuels is a welcome step. The 66 per cent jump in allocation for the Pradhan Mantri Awas Yojna can help improve housing facilities for migrant workers, while the highest ever capital outlay of Rs. 2.4 lakh crore for the Railways is another step that will keep the growth on the right track.

The budget has envisaged an increase of 13.01 per cent in defence expenditure. The total outlay has been proposed to Rs. 5,93, 537.00 crore.

The key project is 'Battery Energy Storage Systems' with 4000 MW capacity under Green Growth. MSMEs and the start ups to be encouraged with collateral free loans. Green hydrogen mission has been allocated Rs. 297 crore. Cheaper CNG is a welcome step.

Artificial Intelligence (AI) is to be developed and revamped. Three AI centres of excellence and new age courses like coding, robotics part of education form part of revamp plan.

The deficit has been kept low at 6.4 percent.

The share of agriculture has reduced to 3.2 percent from 3.8 percent this year from the last year. Aid has not been increased under PM Kisan Yojna.

The Indian Doctors for Peace and Development (IDPD) said in the last year's budget of Rs.39.45 lakh crore, the health expenditure was Rs. 86, 606 crore, implying 2.19 per cent. But this year Health has been allocated Rs. 88,956 crore out of total budget of Rs. 45 lakh crore, which is 1.97 per cent only. Unfortunately our allocation is among the lowest in the world. Minimum 10 per cent allocation of the total budget is desired and required.

Income tax payees were expecting increase in the limits of 80 (C) & 80 (D) up to at least Rs. 2.00 lakh from present limit of Rs. 1.50 lakh making more way for the increased resources for the government as the same covers investments made under Life Insurance, PPF, deposits with post office, deposits made under Senior Citizen Saving Schemes, NSCs, EPF, ELSS, Home Loan Repayments, Contribution to NPS, Unit Linked Insurance Plans and deposits made under Sukanya Samridhi Yojana.

N P S Sohal
AGM (Retd.)

नई प्रतियोगिता / New Contest

फोटो - **राधा मिश्रा**
एसएएमवी, केंद्रीय कार्यालय

शीर्षक लिखें / Write a Title

क्या यह तस्वीर आपके मन में किसी पुरानी याद, किसी गहन भावना या सृजनात्मकता अंकुरित कर रही है? हर तस्वीर एक दास्तां बयां करती है. तथापि, यदि आप अपने भावों को 5-6 शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत करना चाहें तो तुरंत अपनी कलम का जादू दिखाते हुए इस चित्र के लिए उचित शीर्षक लिखें और अपने कार्यालय के संवाददाता के माध्यम से हमें प्रेषित करें

अपनी प्रविष्टि भेजते समय निम्नलिखित का अवश्य ध्यान रखें:

- शीर्षक केवल 5-6 शब्दों का ही हो.
- प्रविष्टि हिंदी या अंग्रेजी में भेजी जा सकती है. परिपत्र सं. 7869 दि: 19.12.2022 के अनुसार दोनों श्रेणियों में अलग-अलग पुरस्कार दिए जाएंगे.
- एक स्टाफ सदस्य एक ही प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो हिंदी या अंग्रे. जी में.
- प्रतियोगिता केवल बैंक के सेवारत कार्मिकों के लिए ही है.
- सभी संवाददाता अपने क्षेत्र से प्राप्त प्रविष्टियों को समेकित कर निर्धारित समय सीमा में uniondhara@unionbankofindia.bank पर प्रेषित करें.
- प्रविष्टियां भेजने कि अंतिम तिथि 10 नवंबर है.
- शब्द संख्या का ध्यान रखते हुए अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रविष्टियों को ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाएगा.

Is this picture evoking some old memory, some deep emotion or sparking creativity? Every picture is worth a thousand words. However, if you want to express yourself feelings in 5-6 words, then let your pen create magic. Write a suitable title for this picture and send it to us through the correspondent of your office.

Please ensure the following while submitting your entry:

- Title should be of only 5-6 words.
- The entry may be sent in Hindi or English. In terms of circular no. 7869 dt. 19.12.2022 separate prizes shall be awarded under each category Both the categories have different prizes.
- A staff member may submit only one entry, either in Hindi or in English.
- This contest is open only for the staff members presently in service of the Bank.
- All correspondents are requested to consolidate the entries of their Region within stipulated time and send them to uniondhara@unionbankofindia.bank .
- The last date for sending entries is 10th november
- Entries, duly, adhering to the specified word limit, received by the last date, shall only be included in the competition.

यूनियन धारा प्रतियोगिता क्रमांक 165 - 'स्लोगन लिखें'

पुरस्कार	हिन्दी श्रेणी	अंग्रेजी श्रेणी
प्रथम	**श्री मनीष कपासिया,** डिजिटाइजेशन वर्टिकल, कें.का	**सुश्री लीना साइकिया,** अंचल कार्यालय पुणे
द्वितीय	**सुश्री अनीता मारकुंडी,** अंचल कार्यालय पुणे	**सुश्री अंजना झाझरिया,** अंचल कार्यालय पुणे
तृतीय	**सुश्री सीमा प्रियदर्शिनी,** क्षे.का. भुवनेश्वर	**सुश्री सुनीता मल्लिक,** क्षे. का. भुवनेश्वर
प्रोत्साहन	**सुश्री स्मिता सेठ,** क्षे. का., काकिनाडा	**श्री पल्लिवेलु,** क्षे. का. सेलम

समाचार केंद्र से

दि. 06.05.23 को मार्च'23 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय परिणामों की घोषणा के अवसर पर सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के साथ कार्यपालक निदेशक गण श्री नितेश रंजन, श्री निधु सक्सेना तथा श्री रामसुब्रमणियन एस.

दि. 14.06.23 को बी.के.सी, मुंबई स्थित सोफिटेल होटेल में आयोजित बैठक में निवेशकों / विश्लेषकों को संबोधित करती हुई सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. साथ हैं कार्यपालक निदेशक गण श्री नितेश रंजन, श्री निधु सक्सेना तथा श्री रामसुब्रमणियन एस.

दि. 16.05.23 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में एयर मार्शल के. अनंतरामन पीवीएसएम वीएसएम श्री प्रवीण शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक, श्री एच.के. दास विभागीय प्रमुख - जीबीआरडी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में भारतीय वायु सेना के साथ वेतन खातों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

दि. 27.04.23 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संख्या के आधार पर उत्तम गारंटी कवरेज की श्रेणी में सीजीटीएमएसई द्वारा बैंक को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे से पुरसकार प्राप्त करते हुए श्री चन्द्र मोहन मीनोचा, मु.म.प्र.

दि. 27.05.23 को दिल्ली में स्कॉच अवाड्र्स द्वारा यूनियन प्रेरणा हेतु बीएफएसआई में स्वर्ण श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री लाल सिंह, मु.म.प्र. साथ हैं सुश्री बीना वाहीद, अं.प्र. और श्री जी एन वी रमणा, उप अं.प्र. दिल्ली.

दि. 17.04.23 को दिल्ली में बिजिनेस वर्ल्ड द्वारा "पीडब्ल्यूडी समावेश हेतु उत्तम संगठन" श्रेणी में बैंक को "डिसबिलिटी पॉसिटिव पुरस्कार 23" प्रदान किया गया. पुरस्कार प्राप्त करते हुए सुश्री बीना वाहीद, अं.प्र. दिल्ली, साथ हैं श्री कमलेश वर्मा, समप्र (आई.टी) और श्री राहुल गंभीर, वप्र.

दि. 04.05.23 को मुंबई में इकोनॉमिक टाइम्स समूह द्वारा आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित इकोनॉमिट टाइम्स- फ्यूचर रेडी ऑर्गनाइज़ेशन 23 पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री हृषीकेश मिश्रा, प्रमुख एल एंड डी तथा श्री जी एन वी रमण, उप अं.प्र, दिल्ली.

दि. 02.06.23 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग उद्योग और तकनीकी उत्कृष्टता में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित इंफोसिस फिनेकल नवाचार अवाड्र्स 23 के तहत 4 श्रेणियों में प्लेटिनम विजेता और 3 श्रेणियों में स्वर्ण विजेता कुल 7 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- 2023

दि. 26.05.23 को देहरादून के नए क्षे.का. का शिलान्यास सुश्री ए.मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ द्वारा किया गया. साथ हैं श्री सुमित श्रीवास्तव, अं.प्र., श्री लोकनाथ साहू क्षे.प्र., देहरादून व श्री प्यारे लाल, उप अं.प्र, श्री पी.के. श्रीवास्तव उप अं.प्र, और श्री विपिन यादव, मु.प्र.

दि. 08.06.23 को आयोजित ऋण मेले में लाभार्थियों को चैक प्रदान करते हुए श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक साथ हैं श्री बैजनाथ सिंह, अं.प्र, रांची, श्री राजेश कुमार, क्षे. प्र., पटना तथा श्री पुष्पेन्द्र तिवारी, राज्य प्रोजेक्ट मैनेजर.

दि. 07.06.2 को क्षे.का., समस्तीपुर में कार्यपालक निदेशक महोदय श्री नितेश रंजन का स्वागत करते हुए श्री बैजनाथ सिंह, क्षेमप्र, राँची और श्री समीर साँई, क्षेत्र प्रमुख, समस्तीपुर.

दि. 02.06.23 को सुश्री ए.मणिमेखलै एमडी एवं सीईओ द्वारा राजकोट में लाइफ एनजीओ को चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु चैक प्रदान किया गया, साथ हैं श्री विट्ठल बनशंकरी, अं.प्र. गांधीनगर, श्री संजीव कुमार, क्षे.प्र, राजकोट.

पटना हवाई अड्डे में यूनियन व्योम विज्ञापनयुक्त ट्रॉली का लोकार्पण करते हुए बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री नितेश रंजन, अं.प्र. रांची, श्री बैजनाथ सिंह तथा क्षे.प्र., पटना श्री राजेश कुमार

दि. 09.06.23 को क्षे.का., नई दिल्ली द्वारा श्री चन्द्र मोहन मिनोचा, मु.म.प्र, एमएसएमई एवं श्री गोविंद मिश्रा, क्षे.प्र. की उपस्थिति में "मेगा आउटरिच अभियान" का आयोजन किया गया.

दि. 22.05.23 को प्रोजेक्ट पावर के अंतर्गत गोरखपुर में श्री राजीव मिश्रा, मु.म.प्र., कें.का, तथा श्री गिरीश चन्द्र जोशी, अं.प्र. वाराणसी की उपस्थिति में गोरखपुर, मऊ तथा गाजीपुर क्षेत्रों के शाखा प्रबंधकों की बैठक का आयोजन किया गया.

दि. 20.05.23 को क्षे.का., राँची द्वारा श्री लाल सिंह, मु.म.प्र. की अध्यक्षता में "प्रोजेक्ट पावर" का आयोजन किया गया. श्री बैजनाथ सिंह, अं.प्र., श्री आलोक कुमार, उप अं.प्र. विजय कुमार रॉय, उप अं.प्र. अंचलाधीन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्र प्रमुख, उप क्षेत्र प्रमुख और बिजनेश रिलेशनशिप मैनेजर उपस्थित रहे.

दि. 08.06.23 को क्षे.का., भागलपुर द्वारा आयोजित मेगा आउटरीच शिविर में श्री गुना नन्द गामी, म.प्र. एबीडी एवं श्री इश्तियाक़ अरशद, क्षे.प्र. द्वारा ग्राहकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए.

दि. 20.05.23 को क्षे.का., आजमगढ़ श्री शैलेश सिंह मु.म.प्र का अध्यज्ञता में आयोजित प्रोजेक्ट पावर कॉन्क्लेव में अं.प्र. वाराणसी श्री गिरीश चन्द्र जोशी, क्षे.प्र.आजमगढ़, श्री वी.बी. सहाय, क्षे.प्र. जौनपुर, श्री शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव तथा अंचल के शाखा प्रमुख व स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.

दि. 09.06.23 को कानपुर में मेगा आउटरीच कनेक्ट कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ करते हुए श्री अनिल कुरील मुख्य तकनीकी अधिकारी, श्री सुमित श्रीवास्तव, अं.प्र. लखनऊ और श्री अमित कुमार सिन्हा, क्षेत्र प्रमुख.

दि. 09.06.23 को बठिंडा क्षेत्र द्वारा आयोजित मेगा आउट रीच अभियान में श्री एच के दास, म.प्र., जीबीडी और क्षे.प्र.श्री आशीष सुवालका द्वारा ग्राहकों कों स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए.

दि. 07.06.2023 को अं.का. दिल्ली में अं.प्र. श्री कबीर भट्टाचार्य, महाप्रबंधक, श्री जी एन वी रमणा, उप अं.प्र. श्री विकास विनीत तथा दिल्ली अंचल के सभी क्षे.का. के क्षे. प्र. की उपस्थिति में शाखा प्रमुखों हेतु सम्मेलन का आयोजन किया गया.

यूनियन लर्निंग अकादमी (कॉर्पोरेट एवं ट्रेजरी), गुरुग्राम द्वारा कॉर्पोरेट संबंध कक्ष (सीआरसी) के अधिकारियों हेतु दि. 12.06.23 से 15.06.23 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ श्री अभिजीत बसाक, मु.म.प्र., एवं श्री हरे कृष्णा दास, म.प्र., जीबीडी.

दि. 07.06.23 को रांची में कस्टमर कनेक्ट कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री अरुण कुमार, म.प्र., श्री बैजनाथ सिंह, अं. प्र., रांची, श्री आलोक कुमार, उप अं.प्र., श्री विजय कुमार, उप अं.प्र., श्रीमती सोनालिका, क्षे.प्र.,रांची, श्री अरुण कुमार मंडल, उप क्षे.प्र., और श्री विभाष कुमार मिश्रा, उप क्षे.प्र.

दि. 16.06.2023 को आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हेतु श्री गिरीश जोशी, अं. प्र. वाराणसी, श्री सुब्रजीत गुहा, उप अंचल प्रमुख, श्री प्रमोद कुमार जैन, निदेशक, आईआईटी बीएचयू और श्री विकास कुमार दुबे, डीन-(आर्रडी) की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.

दि. 09.06.23 को क्षे.का., हल्द्वानी द्वारा चलाए गए मेगा आउटरीच अभियान में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, म.प्र. एवं श्री गौरव कुमार, क्षे.प्र. द्वारा ग्राहकों को ऋण स्वीकृति पत्र एवं क्यूआर कोड का वितरण किया गया.

दि. 09.06.2023 को क्षे.का., आजमगढ़ में श्री गिरीश चन्द्र जोशी, अं.प्र. वाराणसी की अध्यक्षता में आयोजित कारोबार समीक्षा बैठक में क्षे.प्र. श्री वी. वी. सहाय केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु प्रदत्त पुरस्कार प्राप्त करते हुए

दि. 22.05.23 श्री अरुण कुमार, अं.प्र.,चंडीगढ़ के कर-कमलों से मलौट शाखा (बठिंडा क्षेत्र) के नए परिसर का उदघाटन श्री आशीष सुवालका, क्षे.प्र.बठिंडा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ.

दि. 19.06.2023 को क्षे.का., रीवा में श्री बिरजा प्रसाद दास, अं.प्र. तथा श्री दिलीप कुमार मिश्रा, क्षे.प्र. द्वारा शाखा प्रबंधकों की समीक्षा सत्र का उदघाटन किया गया.

दि. 09.06.23 को क्षे.का, नर्मदापुरम द्वारा मेगा आउट रीच कैंप के अवसर पर ग्राहकों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए श्री नीरज सिंह उप अं.प्र. भोपाल, श्री देवेंद्र चौबे क्षे.प्र.नर्मदापुरम साथ हैं श्री कुंजन पटेल उप क्षे.प्र.नर्मदा पुरम, श्री संतोष कुमार एम एल पी प्रमुख तथा श्री मिथुन अम्रोडे, शाखा प्रमुख बेतूल बाज़ार.

दि. 05.06.23 को सिरोही शाखा के नवीन परिसर का उद्घाटन क्षे.प्र. द्वारा किया गया. इस अवसर पर ग्राहकों को संबोधित करते हुए श्री मयूर पांड्या, शाखा प्रमुख. श्री जगदीश जी रावल, लैंडलॉर्ड, श्री सारंग अ. झंझाड, क्षे.प्र. श्री जितेंद्र कुमार मीणा,शा. प्र. सिरोही शाखा, शेख फरहान खान, प्रबंधक मंचासीन हैं.

दि. 03.06.23 को क्षे.का., धनबाद द्वारा श्री मुकेश कुमार सिंह, क्षे. प्र, श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, उप क्षे.प्र. और श्री उमेश चन्द्र, उप क्षे.प्र. की उपस्थिति में मुस्कान कनेक्ट का आयोजन किया गया.

दि 03.06.23 को क्षे.का., रायपुर में उप क्षेत्र प्रमुख श्री पुष्कर सिन्हा की उपास्थिति में मुस्कान कनैक्ट का आयोजन किया गया.

समाचार (पूर्व)

दि. 18.05.23 को आयोजित पावर कॉन्क्लेव कार्यक्रम में श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक और श्री सर्वेश रंजन, अं.प्र. भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के अंतर्गत आकांक्षी जिले की नयापल्ली शाखा के शाखा प्रमुख श्री प्रभाकर सेठी को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए.

दि. 08.06.23 को क्षे.का., भुवनेश्वर द्वारा श्री प्रवीण कुमार शर्मा, मु.म.प्र. केंका की अध्यक्षता के आकांक्षी जिला खुर्दा के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइन्स में मेगा आउटरिच कैम्पेन का आयोजन किया गया. मंचासीन हैं श्री सर्वेश रंजन, अं.प्र. भुवनेश्वर, श्री आर देवराज, उप अं.प्र., श्री निरंजन बारिक, क्षे.प्र.भुवनेश्वर.

दि. 08.06.23 को खुर्दा के नए परिसर में जन सुरक्षा शिविर में श्री प्रवीण शर्मा, मु.म.प्र., केंका, श्री सर्वेश रंजन, अं.प्र., श्री रंजीत, उप अं.प्र. श्री हरेराम शाह, समप्र द्वारा सभी स्वंय सहायता समूह ग्राहकों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए.

दि. 09.06.23 को श्री एस के दास, म.प्र., केंका द्वारा क्षे.का. हावड़ा के अंतर्गत डानकुनी शाखा में आउटरीच कैम्पेन में ग्राहकों को संबोधित करते हुए. मंचासीन हैं, श्री सत्यजीत मोहंती, उप अं.प्र., कोलकाता तथा श्री समीर कुमार, क्षेत्र प्रमुख, हावड़ा.

दि. 02.06.23 को श्री जी के सुधाकर राव, अं.प्र., कोलकाता की अध्यक्षता में श्री समीर कुमार, क्षेत्र प्रमुख तथा अन्य कार्यपालकों की उपस्थिति में हावड़ा क्षेत्र के शाखा प्रमुखों तथा उप शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया.

दि. 09.06.23 को सम्बलपुर में श्री अजय कुमार, म.प्र. कें.का. द्वारा दीप प्रज्जवलन कर कस्टमर आउटरिच कैंप का शुभारंभ किया गया. साथ हैं श्री धर्मेन्द्र राजोरिया, क्षे.प्र. संबलपुर, श्री हरेन्द्र कुमार जेना, उप क्षे.प्र., और श्री राजेश कुमार झा, उप क्षे.प्र., सुश्री एल संगीता कुजूर, एमएलपी प्रमुख.

दि. 08.05.23 को आयोजित बैठक में स्वर्ण ऋण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु श्री सुभाष दास, शाखा प्रमुख, भीमपुर शाखा को प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए, श्री एम रबीन्द्र बाबू, म.प्र. केंका, श्री सर्वेश रंजन, अं.प्र. तथा श्री वी एस वी नागेश, उप अं.प्र.

समाचार (पश्चिम)

दि. 13.06.23 को सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ द्वारा गांधीनगर में श्री सी एम मिनोचा,मु.म.प्र., श्री प्रवीण शर्मा, मु.म.प्र., श्री राजीव मिश्रा, म.प्र., श्री संजय नारायण,म.प्र. श्री विट्ठुल बनशंकरी, अं. प्र., श्री के. पी. सिंह, उप अं.प्र. श्रीमती याचना पालीवाल तथा अंचल के सभी क्षेत्र प्रमुखों की उपस्थिति में "गिफ्ट सिटी स्थित गांधीनगर अं.का. के नवीन परिसर" का उदघाटन किया गया.

दि. 12.06.23 को सुश्री ए.मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ द्वारा गांधीनगर में श्री विट्ठुल बनशंकरी, अं.प्र., श्री के. पी. सिंह, उप अं. प्र., श्री संतोष साहू क्षे.प्र., गांधीनगर एवं तुषार कान्त कर, क्षे.प्र., अहमदाबाद के क्षेत्र प्रमुख की उपस्थिति में "अक्षय पात्र फाउंडेशन' को भारत सरकार के विद्यालयों में बच्चों को "मध्याहन भोजन योजना" के भोजन वितरण के लिए वाहन प्रदान किया गया.

दि. 02.06.23 को राजकोट में सुश्री ए.मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ की अध्यक्षता में "प्रोजेक्ट पावर" कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया. इसमें श्री विट्ठल बनशंकरी, अं.प्र. गांधीनगर, श्री के पी सिंह, उप अं.प्र. व अंचलाधीन क्षेत्रों के क्षे.प्र.व संबन्धित क्षेत्रों के आंकाक्षी जिलों से शाखा प्रमुख शामिल हुए.

दि. 26.05.23 को क्षे.का., गोवा द्वारा एमएसएमई आउटरीच कैम्प में श्री नितीश रंजन, कार्यपालक निदेशक, श्री आशीष मालवीय, क्षे.प्र., श्री अजय, उप क्षे.प्र. द्वारा महिला उद्यमियों को सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए.

दि. 18.05.23 को क्षे.का., नागपुर में आयोजित प्रोजेक्ट पावर के अंतर्गत आयोजित समारोह का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ करते हुए श्री चन्द्र मोहन मिनोचा, मु.म.प्र, एमएसएमई, श्री कबीर भट्टाचार्य, अं.प्र पुणे, श्री अनूप तराले, क्षे.प्र अमरावती, श्री प्रमोद ठाकुर, उप क्षे.प्र.

दि. 16.05.23 अं.का., पुणे द्वारा कार्यपालक निदेशक श्री नितेश रंजन की अध्यक्षता में आयोजित प्रोजेक्ट पावर कार्यक्रम में साथ हैं श्री कबीर भट्टाचार्य, अं.प्र. तथा अंचलाधीन क्षेत्रों के क्षे.प्र. तथा स्टाफ सदस्य भाग लिया.

दि. 17.05.23 को क्षे.का., मुंबई दक्षिण द्वारा आयोजित पावर सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए श्री रामसुब्रमण्यम एस., कार्यपालक निदेशक, श्री योगेंद्र सिंह अं.प्र., सुश्री सौम्या श्रीधर, उप अं.प्र., श्री विजय कुमार, क्षे.प्र., मुंबई दक्षिण.

दि. 08.06.23 को सेवा मंडल एडुकेशन सोसाइटी, माटुंगा, मुंबई में क्षे.का. मुंबई दक्षिण द्वारा आयोजित मेगा आउटरीच अभियान में श्री अभिजीत बसाक, मु.म.प्र., एलसीवी, श्री योगेंद्र सिंह, अं. प्र., एवं श्री विजय कुमार, क्षे.प्र., क्षे.का., मुंबई दक्षिण द्वारा ग्राहकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए.

दि. 08.06.23 को क्षे.का., अमरावती द्वारा श्री मनोज कुमार, म.प्र. एफ़.आई. की अध्यक्षता में आयोजित आउटरीच अभियान के दौरान ग्राहकों को संबोधित करते हुए, श्री अनूप तराले, क्षे.प्र. अमरावती.

दि. 09.06.23 को क्षे.का., नागपुर द्वारा आयोजित आउटरीच अभियान के अंतर्गत श्री मनोज कुमार, म.प्र. एफ़.आई. द्वारा स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया. श्री एम वी एन रवि शंकर, क्षे.प्र., श्री राजेश यादव, उप क्षे.प्र. एवं श्री एम शिवकुमारण और सभी शाखा प्रबंधक उपस्थित थे.

दि. 09.06.23 को आणंद क्षेत्र में प्रोजेक्ट पावर के अंतर्गत आयोजित मेगा आउटरीच अभियान में श्री हृषिकेश मिश्रा- प्रमुख (एल एंड डी), कें.का. मुंबई, श्रीमती याचना पालिवाल, उप अं.प्र., अहमदाबाद और श्रीमती ऋचा जाजोरिया, क्षे.प्र. आणंद की उपस्थिति में नारी की बारी, खुदरा और एमएसएमई ऋण के तहत ग्राहकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए.

समाचार (दक्षिण)

दि. 13.06.23 को विशाखपट्टणम में आयोजित रोजगार मेला के छटे ट्रेंच में डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, माननीय राज्य मंत्री (विदेश और वित्त मंत्रालय), श्री. कार्तिकेय मिश्रा, निदेशक (डीएफएस), श्री. निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्री. अनूप कुमार श्रीवास्तव, मंडल रेल प्रबन्धक तथा श्री लाल सिंह, मुमप्र (मा.सं) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उपस्थित रहे.

दि. 13.06.23 को विजयवाड़ा में आयोजित प्रधानमंत्री रोजगार मेला के छटे ट्रेंच में डॉ. श्री भगवत किशन राव कराड, माननीय राज्य मंत्री (वित्त), कार्यपालक निदेशक श्री. रामसुब्रमणियन एस. संयोजक एसएलबीसी, आं.प्र. ,एवं अं.प्र. श्री. नवनीत कुमार, उप म.प्र. कें.का. श्री अम्बरीष कुमार सिंह और समप्र ई राजू बाबू उपस्थित रहे.

दि. 19.05.23 को तिरुपति में सुश्री ए मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट पावर कॉनक्लेव बैठक का आयोजन किया गया. श्री नवनीत कुमार,अं.प्र. विजयवाड़ा, श्री मुरली पार्थसारथी उप अं.प्र. क्षे.प्र. तिरुपति श्री राम प्रसाद, क्षे. प्र. नेल्लूर श्री जोगाराव किल्लि, क्षे.प्र. अनन्तपुर श्री जितेंद्र कुमार मिश्रा, क्षे.प्र. कड़पा श्री भास्कर बी, क्षे.प्र. कर्नूल श्री पी नरसिम्हा राव उपस्थित रहें.

दि. 13.06.23 को श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक द्वारा श्री लाल सिंह, मुमप्र (मा.सं). श्री. सी. वी. एन. भास्कर राव, अं. प्र., विशाखपट्टणम अं.का., और अन्य कार्यपालक गण तथा स्टाफ सदस्यों की उपास्थिति में अंचल कार्यालय विशाखपट्टणम के नए परिसर का उद्घाटन किया गया.

दि. 19.05.23 को कार्यपालक निदेशक श्री निधु सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित टाउन हाल बैठक के अवसर पर श्रीमती रेणु के नायर, अं.प्र., मंगलूरु, श्री राजीब एल पटनायक, म.प्र. कें. का.अनेक्स, श्री जी शंकारलाल, म.प्र., श्री बी जानकीराम, म.प्र के साथ अंचलाधीन क्षेत्रों के क्षे.प्र.एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालक गण उपस्थित रहे.

दि. 07.06.23 को नई दिल्ली में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति आंध्र प्रदेश को नई दिल्ली में पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ए पी वाई उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ. श्री नवनीत कुमार, अं.प्र. विजयवाड़ा एवं संयोजक एसएलबीसी आं.प्र. द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया.

दि. 09.06.23 को क्षे.का., सिकंदराबाद में मेगा आउटरिच अभियान के दौरान श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक ग्राहक को ऋण मंजूरी पत्र प्रदान करते हुए. साथ हैं श्री कारे भास्कर राव, अं.प्र., श्री पी कृष्णन, उप अं.प्र., श्री एम अरुण कुमार, क्षे.प्र, और श्री श्याम प्रसाद, एम एल पी प्रमुख.

दि. 08.06.23 को बेंगलूरु अंचल की समीक्षा बैठक के दौरान श्री रामासुब्रमणियन एस, कार्यपालक निदेशक दीप प्रज्वलित करते हुए, साथ हैं श्री लाल सिंह, मु.म.प्र. (मा.स.), श्री एस वी बीजू, अं.प्र., सुश्री आरती रौनियार, क्षे.प्र., बेलगाम, श्री आर ज्योति कृष्णन, क्षे. प्र., बेंगलूरु पूर्व.

दि. 09.06.23 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अं.का. विजयवाड़ा में श्री नवनीत कुमार, अंचल प्रमुख विजयवाड़ा तथा श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी एसएचसीआईएल, क्षेत्रीय प्रबंधक की उपस्थिति में स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण के लिए अधिकृत संग्रहण केंद्र के रूप में एसएचसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया.

दि. 09.06.23 को क्षे.का., पंजागुट्टा हैदराबाद द्वारा आयोजित एमएसएमई आउटरिच अभियान में मुख्य अतिथि श्री एस के महापात्रा मु.म.प्र का स्वागत करते हुए श्री यू. रजनीकांता राव, क्षे.प्र, सुश्री बी ए एल कामेश्वरी, उप क्षे.प्र. और सुश्री एम. माणिक्येश्वरी, उप क्षे.प्र.

दि. 09.06.23 को श्री लाल सिंह मु.म.प्र (मा.सं) की अध्यक्षता में आयोजित मेगा आउटरीच कार्यक्रम में ग्राहकों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए, साथ हैं श्री बीजू वासुदेवन, अं.प्र. श्री सत्यभान बेहरा, उप अं.प्र एवं श्री असीम कुमार पाल क्षे.प्र.

दि. 23.06.23 को एर्णाकुलम में लार्ज कार्पोरेट शाखा का उद्घाटन करती हुईं श्रीमती रेणु नायर, अं.प्र. मेंगलुरु साथ में श्री दीप्ति आनंदन, समप्र, एलसीबी तथा श्री आर नागराजा, क्षे.प्र.

दि. 16.06.23 को गोल्ड लोन वर्टिकल के महाप्रबंधक, श्री एम. रविन्द्र बाबू एमएसएमई लोन पॉइंट, सेलम के नवीनीकृत कार्यालय का उद्घाटन करते हुए. साथ हैं क्षे.प्र., श्री एम. चेल्लदुरै उप क्षे.प्र., श्री प्रिंस डी., उप क्षे.प्र., श्रीमती कला शिवकुमार और एमएलपी प्रमुख, श्री अंबाती श्रीनिवास.

यूनियन ज्ञानार्जन अकादमी, बेंगलूरु (मानवीय उत्कृष्टता) द्वारा दि. 15 से 17 मई, 23 तक उप क्षेत्र प्रमुखों के लिए "आरोहण" प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रतिभागियों के साथ केंद्र प्रभारी श्री दीपक नागर तथा संकाय गण श्री उज्जवल कान्त, श्री शैलेश कुमार, श्री सचिन बंसल.

यूनियन ज्ञानार्जन अकादमी, बेंगलूरु (मानवीय उत्कृष्टता) द्वारा दि. 5 से 7 जून, 23 तक बैंक की महिला अधिकारियों के लिए "विंग्स (WINGS)" प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रतिभागियों के साथ तथा केंद्र प्रभारी श्री दीपक नागर, श्री सचिन बंसल, मु.प्र. (संकाय) के समन्वयन में संपन्न हुआ.

दि. 23.06.23 को क्षे.का., बेंगलूरु उत्तर द्वारा श्री मनोज कुमार, उमप्र, केंका के उपस्थिति में आयोजित एमएसएमई, आउटरीच कार्यक्रम. मंचासीन हैं श्री के. दिनकर, उप क्षे.प्र. एवं श्री कनकराजू सी., एमएलपी प्रमुख, बेंगलूरु उत्तर.

व्यंजन

पारंपरिक सेवईयां

सामग्री:-

1 ½ चावल का आटा, 1 नारियल कछूकस किया हुआ, ½ कप गुड़ पाउडर, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच इलायची पाउडर, नमक स्वादानुसार

बनाने का तरीका :- कढ़ाई में आधा कप पानी डालें उसमें 1 चम्मच घी स्वादानुसार नमक डालकर तेज आंच पर पानी को उबालें. उबाल आने पर गैस की आंच धीमी करके इसमें धीरे-धीरे चावल का आटा डालकर मिक्स करें. अब कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर चावल के आटे को भाप दें. इसके बाद गरम चावल के आटे को एक बाउल में निकालकर आटे को ठंडा पानी डालकर गूँथ लें. आटा नरम होना चाहिए. इसी बीच इडली स्टीमर में पानी डालकर गैस पर चढ़ा दें. चावल के आटे के बॉल बना लें. अब इडली का साँचा लेकर इसमें सेवईयां की जाली लगा लें. आटे को इडली साँचा में रख कर इडली पात्र में शेवईयां निकालें. इडली प्लेट को इडली पात्र में डालकर 7-8 मिनट स्टीम करें, सेवईयां तैयार हो जाएंगी.

कछूकस नारियल को मिक्सी जार में डालें. इसमें 1 गिलास गरम पानी डालकर पीस लें. इसी नारियल के मिक्सर को छलनी से छान लें. इस नारियल पाउडर में ½ कप गुड़ पाउडर और इलायची मिला लें.

अब प्लेट में सेवईयां लेकर इसके ऊपर नारियल और गुड़ का मिश्रण डालकर सर्व करें. यह कोंकण प्रांत की पारंपरिक व्यंजन है.

नयना कच्छप
पर्रा शाखा, क्षे.का. गोवा

हेल्थ टिप्स

My Experiments With Food

One rainy day in the month of July, which happened to be the last working day of the week, I indulged in a sumptuous lunch. I realized that even the simple task of walking upto my seat seemed quite arduous and I had a difficult time keeping myself alert in the second half of the day. Later in the evening I was recollecting the afternoon situation when I struggled to pull myself out of lethargy. I realised that there is an impact of the food I ate on my activity levels.

Being a curious person. I set out to understand the phenomena by referring different ayurvedic texts like Charaka Samhita, Astanga Hridaya and from various other sources on internet. I understood the following from my brief reading :

1. Food can induce psychological dispositions on the individuals which can be expressed in 3 states i.e Sattvic (Contended state), Rajasic (excited state) and Tamasic (Lethargic state).

2. The five elements i.e air, water, fire, earth and space are grouped into Tri-Doshas i.e Vaata (air and space), Pitta (Fire) and Kapha (water and earth). Different states of mind are determined based on the innumerable permutations and combinations of these five elements.

3. According to ayurveda, food is classified into Sattvic, Rajasic and Tamasic catagories.

My study convinced me that food has an impact on the mind. One day I tried sattvic diet (like soaked peanuts, fruits, grated ash-gourd in curd with pomegranate), on another day I tried rajasic diet (like spicy biryani, momos, paneer butter masala etc) and on another day I tried tamasic diet (like sweets, pizza, burgers and maida related products).

Though the experiment lasted for a limited time, to my surprise I was able to see my mind function according to the type of food consumed. Like on sattvic diet - my mind was active without any lethargy and responding to others in a warm tone. Whereas a bit of anger, lethargy and drowsiness was observed on the days I followed rajasic and tamasic diet. My observation is not based on comprehensive research and other factors at workplace have not been taken into account.

Conclusion- This is just one lay man's perspective to observe the impact of food on mind and work. Further research can be done from ayurvedic, psychological and neuroscientific perspectives. Taste preferences, psychological patterns, body types and functioning etc differ from person to person. Therefore, it is difficult to arrive at a universal solution. From this little experiment, I understood that a contented stage can be attained by consuming certain food.

P.V.M. Kashyap
CO Annex- Mangaluru

यूनियन बैंक की गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' की अक्तूबर-दिसंबर 2022 अंक प्राप्त हुआ. पत्रिका का यह अंक अत्यंत ही मनमोहक, तथ्यपरक व ज्ञानवर्द्धक है. पत्रिका का यह अंक न केवल ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधा वरन सुविधाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास, सुझाव सहित ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक करता है. इसमें जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है जो इसे और भी रोचक बनाती है. जैसा कि यह परिचालन विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है इसमें परिचालन के अहम बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है जिसके जरिये कोई भी पाठक बैंकिंग व्यवस्था को आसानी से जान सकते हैं. यह अंक बहुत ही रोचक होने के साथ-साथ मनोरंजक भी है जो इसे पाठकों के और करीब लाती है. साथ ही इसमें संस्था द्वारा किए जा रहे कई नवीन प्रयासों, गतिविधियों को भी दर्शाया गया है. पत्रिका के उत्कृष्ट संपादन तथा बेहतरीन प्रस्तुतीकरण, मनमोहक है. संपादन मण्डल को इस उत्कृष्ट पत्रिका हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

डॉ. मंजेश परासर
नराकास सदस्य सचिव (केंद्र सरकार)
प्रधान महालेखाकार कार्यालय (ले. एवं हक.) भुवनेश्वर, ओड़ीशा

हमें आपके बैंक की तिमाही गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' की प्रति प्राप्त हुई - धन्यवाद ! इस पत्रिका में प्रकाशित आलेख 'शाखा प्रबंधन एवं शाखा परिचालन', 'भविष्य का शाखा बैंकिंग' एवं अन्य रचनाएं जैसे 'रेसः उत्कृष्टता की ओर', 'यह वर्ष भी आखिर बीत गया', 'माँ' एवं 'अच्छी ग्राहक सेवा का संचालन' पठनीय एवं ज्ञानवर्द्धक है. इसमें बैंक की गतिविधियों एवं अन्य खबरों का व्यवस्थित रूप से समावेश किया गया है. इसके प्रकाशन से जुड़ी टीम का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है. आशा है भविष्य में भी आप अपने स्तर पर हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन व तत्संबंधी गतिविधियों से हमें अवगत कराएंगे.

उमानाथ मिश्र
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), बैंक ऑफ बड़ौदा

आपके बैंक की द्विभाषी गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' पत्रिका हमें प्राप्त हुई है. 'यूनियन धारा' पत्रिका की रुपरेखा एवं साज-सज्जा अत्यंत ही आकर्षक है. इसमें निहित लेख रोचक एवं ज्ञानवर्धक है, जिससे निश्चित ही सभी पाठकगण लाभांवित होंगे. साथ ही तकनीकी, बैंकिंग, समसामयिक विषय पर समाहित इसे संग्रहणीय बनाती है 'यूनियन धारा' पत्रिका के बेहतरीन अंक के प्रकाशन हेतु आपको एवं आपके पूरे संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं साधुवाद.

राघवेंद्र कुमार तिवारी
संपादक केनरा ज्योति
केनरा बैंक

यह स्वागतेय है कि पत्रिका में सर्जनात्मकता के सभी तत्व यानी पर्यावरण, साहित्य, संस्कृति, स्वास्थ्य, वाणिज्य, बैंकिंग, सरकारी योजनाएँ, यात्रा-वृतांत आदि का समावेश है. क्षणिकाएं, मुक्तक, छंद तथा कवर का मनोरम दृश्य मन को आनंदित करने वाला है. विविध विषयों पर केन्द्रित रचनाएँ इसके वैविध्य का प्रमाण हैं. संपादकीय, क्षेत्रवार समाचार, आपकी पाती जैसे स्तम्भ सुष्ठु और सराहनीय हैं. प्रभाकर पाल का 'म्यूचुअल फंड', साहिद कबीर का 'वित्तीय निवेश', राहुल जैन द्वारा प्रस्तुत चटपटी खबर रोचक व ज्ञानवर्धक है. प्रेम गगन के ध्रुव तारा से सुविख्यात 'गोपाल दास नीरज' के परिचय ने मुशायरों और गजलों के युग की याद दिला दी. अंशुल कुमार दूबे का 'शिक्षा के बाजारीकरण' ने हमें वास्तविकता के सम्मुख खड़ा कर दिया है. मो. जावेद अर्शद द्वारा प्रस्तुत 'व्यक्तिव विकास के अहम पहलू' में उजागर जीवन की विविध परिस्थितियाँ जो एक प्रशिक्षण स्थल हैं, हमारे चरित्र की दृढ़ता को सामने लाती है. विशाल अवस्थी कौन हो तुम' ने स्निग्धता और परुषता के अवकाश को चित्रित किया है. तपन बिलखीया के 'परिंदे की चाह' जीवनपथ को दिशाशून्यता से बाहर निकलने का साहस भरता है. कौशल किशोर शुक्ला का 'इंद्रधनुष' कविता समृद्ध विरासत की अनुपम छटा प्रस्तुत करती है. विभिन्न गतिविधियों से अलंकृत चित्रों से पत्रिका आकर्षक बनी है पत्रिका के इस अंक हेतु संपादक मंडल सहित प्रत्येक रचनाकार को बधाई तथा आगामी अंक हेतु शुभकामनाएं

अजयेन्द्रनाथ त्रिवेदी
मुख्य प्रबंधक राजभाषा विभाग, यूको बैंक

'यूनियन धारा' का 'जनवरी-मार्च 2023' अंक प्राप्त हुआ. इस पत्रिका के माध्यम से मुझे बैंक कर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा की एक झलक दिखाई पड़ी. सभी विषयों के लेख अत्यंत गंभीर शैली में लिखे गए है. पत्रिका में नाना प्रकार के विषयों को समाहित किया गया है, लेखों को पढ़कर प्रतीत होता है कि लेखकों ने अपनी लालित्य कला के साथ-साथ लेख विषयों की ज्ञानपरकता पर भी बल दिया है. पत्रिका में श्री गोपाल दास नीरज पर आधारित लेख को शामिल करके संपादक मंडल ने हिंदी साहित्य को भी उचित स्थान देने का प्रयत्न किया है जो कि प्रशंसनीय है. मीसापुलीमाला केरल का दृश्य रोमांचित कर देने वाला है. 'बाबू जी' नामक लेख आधुनिक समाज की प्रवृत्तियों को उदघाटित करता है. लेख पढ़कर मैं भावविभोर हो उठा. अंततः पत्रिका अपने उद्देश्य में सफल हुई है. संपादक मंडल को बहुत बधाईयाँ एवं आगामी अंक हेतु शुभकामनाएँ.

अनवर हुसैन रिज़वी
वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का निरीक्षण - दि. 17.06.2023

संसदीय समिति के संयोजक डॉ मनोज राजोरिया के कर कमलों से सफल निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री मार्कण्डेय यादव, क्षेत्र प्रमुख, लखनऊ, साथ हैं श्री लाल सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.), श्री सुमित श्रीवास्तव, अंचल प्रमुख, लखनऊ श्री अम्बरीष कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (मा.सं.), श्री रामजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.), श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, सुश्री शिल्पी बिष्ट, सहायक प्रबंधक (रा.भा.) और सुश्री अपूर्वा सिंह, प्रबंधक (रा.भा.).

संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्यों द्वारा अंचल कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की गृह पत्रिका 'यूनियन प्रभात' का विमोचन किया गया.

डॉ मनोज राजोरिया, संयोजक तीसरी उप समिति ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी स्टाल का वीक्षण किया.

‘किसी नटखट बच्चे की तरह,
यहाँ वहाँ छुपती फिरती है,
ठंड के मौसम में,
पहाड़ों पर ये कच्ची धूप’

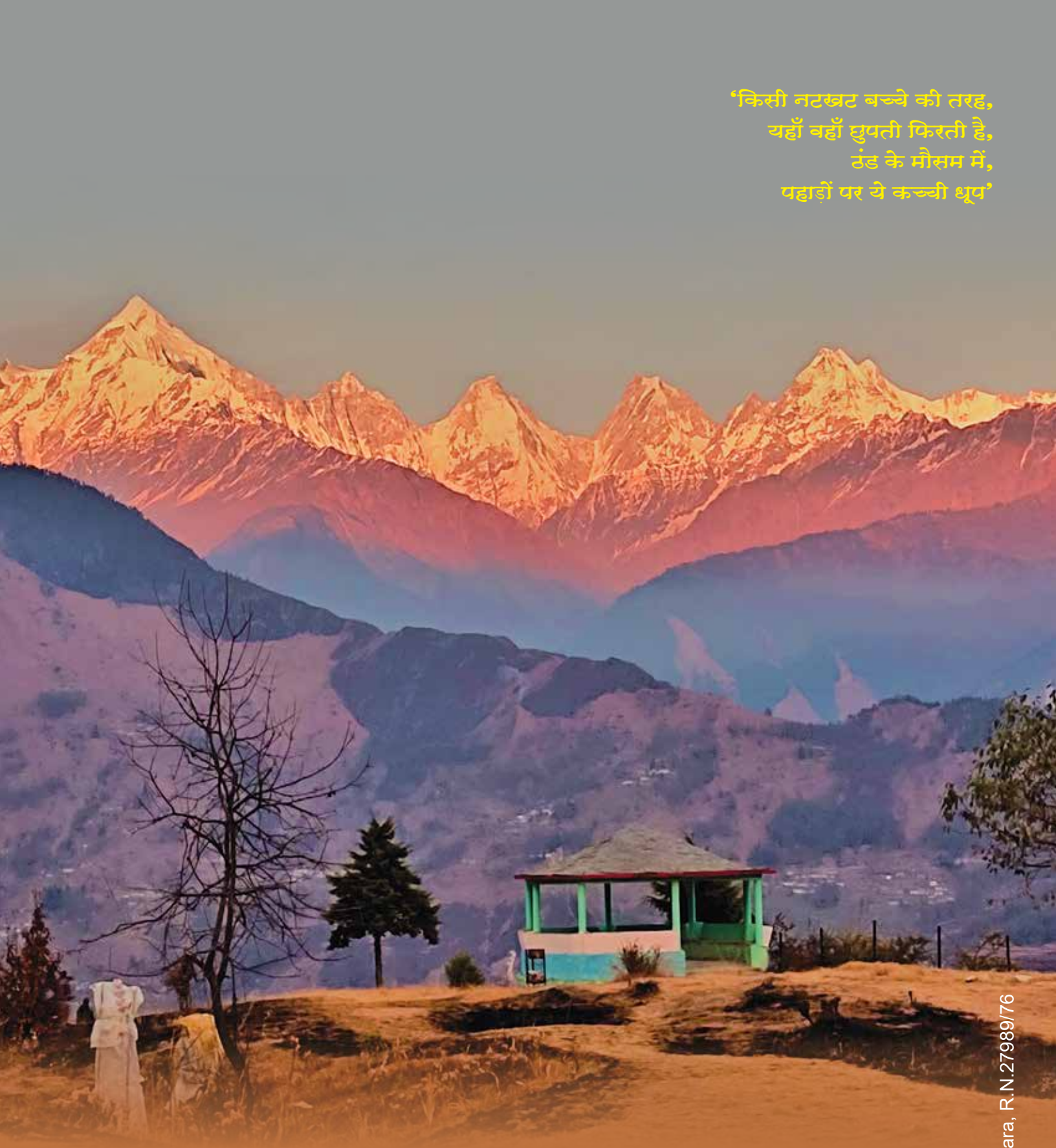

पंचाचूली चोटी - मनुस्यारी - उत्तराखंड
छायाचित्र एवं कविता - श्री रमेश राजशेखर
परिचालन विभाग - मंगलूरू

Union Dhara, R.N.27989/76

Printed and Published by Gayathri Ravi Kiran on behalf of Union Bank of India, Printed at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd., 65, Ideal Ind. Estate, Mathuradas Mill Compound, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, and Published from Union Bank of India, 239, Union Bank Bhawan, 239, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Editor - Gayathri Ravi Kiran.